[Shri B. S. Bhaura]

cedure and Conduct of Business in Lok Sabha I wish to raise the following matter of public importance.

There is acute shortage of diesel oil in Punjab resulting in hardship to farmers whose crops are not getting water because the shortage of electricity is already there and now diesel oil is also not available. Blackmarketing in the sale of diesel oil is also going on as the dealers are charging very high price. I request that the Minister should make a statement.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): I want to make a submission, Sir. You have allowed two members under Rule 377. This is a very important matter concerning 2000 workers of Haryana....

MR. SPEAKER: I am not allowing you.

13.07 hrs.

RE. BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHURAMAIAH): May I make a statement? I have consulted the Leaders of the Opposition. Because there are a number of speakers on our side as well as on their side who want to participate in the debate on the Demands for Education, the remaining time is not enough and they have all agreed that we may extend the time. May I submit that we may extend it for the whole of the day. That will give us two hours more and the Minister may reply tomorrow. They have all agreed to it.

MR. SPEAKER: I hope you all agree.

The Minister will reply tomorrow.

HON. MEMBERS: Yes.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): May I get a little favour from you in this regard....

MR. SPEAKER: Please do not bring in State matters every time.

13.09 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1973-74 *Contd.*

MINISTER OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND DEPARTMENT OF CULTURE *Contd.*

MR. SPEAKER: The House will now proceed with the further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Education and Social Welfare and the Department of Culture.

R Shri Rudra Pratap Singh.

श्री रुद्र प्रताप सिंह (बाराबंकी) माननीय अध्यक्ष जी, विगत कार्य दिवस पर मैं सदन में शिक्षा मंत्रालय के सांस्कृतिक विभाग के पुरातत्व उप-विभाग के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर रहा था। श्रीमन्, पुरातत्व विभाग के द्वारा समस्त प्रदेश तथा समस्त केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में, कश्मीर से ले कर कन्याकुमारी तक, गुजरात से असम तक स्मारकों के संरक्षण, सर्वेक्षण और अध्ययन का काम तीव्र गति से चलाने की आवश्यकता है जिस से कि राष्ट्र का प्राचीन तथा प्राचीनतम इतिहास जो अंधकार में हो गया है वह वर्तमान के प्रकाश में आ सके और भविष्य में हमारा मार्गदर्शन कर सके।

श्रीमन्, 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम की सेनानी, लक्ष्मी बाई, के पति की समाधि को भी मंत्रालय द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाय, यह हमारा बहुत ही नम्र निवेदन है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उन का जो किला है, महल है, उस में उस समय की जो ऐतिहासिक वस्तुयें प्राप्त हुई हैं उन को वहां पर एक संग्रहालय का स्वरूप प्रदान किया जाय।

श्रीमन्, पुरालेख तथा स्मारकों का सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस के द्वारा भारतीय संस्कृति की अनेकता में एकता

का दर्शन होता है और राष्ट्र की भावात्मक एकता को बल प्रदान होता है। इस बात की आवश्यकता है कि इस कार्य को अधिक तीव्रता के साथ बढ़ाया जाय।

श्रीमन्, पुरातत्व विभाग के द्वारा भारत के बाहर भी स्मारकों के संरक्षण का काम किया जा रहा है, और इस आलोच्य वर्ष में भी बमियान, अफ़गानिस्तान की कंदराओं में इस प्रकार के कार्य जारी रखे गए हैं। इसके लिए मैं सरकार की सराहना करता हूं, और मैं इस बात का अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार का यदि सरकार प्रयास करना चाहे तो हमारे भारत के साथ एशिया के जितने भी देश हैं, वह चाहे लंका, भूटान, सिक्किम, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान, बांगलादेश, जापान और चीन, समस्त देशों में हमारे भारत के इतिहास और संस्कृति के अवशेष मिल सकते हैं जिनको संरक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, राष्ट्र के संग्रहालयों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रदेश और जिस केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में वहां के पुरावशेष और बहुमूल्य कला-कृतियां प्राप्त हों तो उसी क्षेत्र में संग्रहालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि राष्ट्र की भावात्मक एकता को बल मिल सके और राष्ट्र के एक प्रदेश के और केन्द्र प्रशासित क्षेत्र के पर्यटक दूसरे क्षेत्रों में जा कर उनकी राष्ट्रीय भावना को बल मिल सके और विश्व समुदाय के लिए भारत एक आकर्षण का केन्द्र बन सके।

श्रीमन्, इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में हमने एक बहुमूल्य पुरातत्व तथा बहुमूल्य कला कृति विधेयक पारित किया था और उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि आवश्यकता पड़ने पर हमारे देश में, हमारे राजा महाराजाओं के यहां, पूंजीपतियों के यहां अब भी जो पुरावशेष बहुमूल्य कला-कृतियां उपलब्ध है उनको उनके महलों से, प्रासादों से निकाल कर उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के हेतु संग्रहालयों में रखा जा सकता है ताकि उन कला कृतियों के सामने राष्ट्र के पर्यटक और विश्व समुदाय के पर्यटक अपने श्रद्धा के पुष्प चढ़ा सकें।

दो शब्द अब मैं दूसरे राष्ट्रों के साथ हमारे जो सांस्कृतिक करार हुए हैं उनके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जहां तक मेरी सूचना है विगत वर्ष तक भारत के 23 देशों के साथ सांस्कृतिक करार हुए थे। इस आलोच्य वर्ष में हमारे जर्मन जनवादी राज्य और बंगला देश के साथ सांस्कृतिक करार हुए हैं जिस की सराहना की जानी चाहिए। लेकिन मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि हमारा सांस्कृतिक विभाग चाहे तो हमारे समस्त एशिया के देशों के साथ और विश्व के अधिकांश देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हो सकते हैं। लेकिन हमें खेद है कि रजत जयन्ती वर्ष तक हमारी सूचना के अनुसार केवल 25 देशों के साथ ही हम सांस्कृतिक करार कर पाए हैं। इस दिशा में हमें विशेष ध्यान देना होगा।

विदेशों से आने वाले सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडलों और राष्ट्र से विदेशों में जाने वाले सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडलों के सम्बन्ध में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। विदेशों से जो हमारे देश में प्रतिनिधि मंडल आते हैं उनका हमारे देश में उचित सम्मान होना चाहिए ताकि हम भारत-वासी दूसरे राष्ट्रों के दृष्टिकोण को समझ सकें। इसी प्रकार से हमारे देश से जो शिष्ट मंडल बाहर जाते हैं, प्रतिनिधि मंडल बाहर जाते हैं उनके लिए भी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उन्हें भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास आदि का पूर्ण ज्ञान हो ताकि वे विश्व समुदाय

[श्री रुद्र प्रताप सिंह]

के सामने भारत के मस्तिष्क को ऊंचा कर सकें और उनके अन्दर किसी प्रकार की हीन भावना नहीं होनी चाहिए ।

हमारी संस्कृति वसुदैव कुटुम्बकम की रही है। हमारी संस्कृति मानवतावाद की रही है । हमारे देश से जाने वाले शिष्ट मंडलों को अगर वसुदैव कुटुम्बकम का, मानवतावादी नीतियों का ज्ञान होगा तो निश्चित रूप से वे भारत के मस्तिष्क को विश्व समुदाय के सामने बहुत ऊंचा कर सकेंगे, इसमें सन्देह नहीं है ।

शिष्ट मंडलों को बाहर जाने के लिए जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसमें भी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उन्हें भारतीय संस्कृति का कितना ज्ञान है और वे बाहर जा कर हमारे देश का कितना गौरव बढ़ा सकेंगे ।

आपका अधिक समय न लेते हुए दो शब्द और मैं सांस्कृतिक विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाली साहित्यिक और नाटक और संगीत अकादमियों के बारे में कहना चाहता हूं । इन अकादमियों के द्वारा अब तक जो कार्य हुआ है वह बहुत कम हुआ है । इस दिशा में हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है । भारत की संस्कृति अनेकता में एकता की है । यही उसकी विशेषता है । हमारे राष्ट्र की, समस्त प्रदेशों की, समस्त केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों की अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है और देश के समस्त प्रदेशों और समस्त केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों की सभ्यता और संस्कृति मिल कर हमारे राष्ट्र की संस्कृति का निर्माण करती हैं । इस प्रकार से इस बात की आवश्यकता है कि हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की जितनी भाषायें हैं, केन्द्र शासित प्रदेशों की जितनी लोक भाषायें हैं, लोक नृत्य हैं उनको भी हमारे सांस्कृतिक विभाग के द्वारा उचित प्रोत्साहन और उचित स्थान दिया जाना चाहिए और इन अकादमियों को उनके कार्य के आधार पर सहायता दी जानी चाहिए । अब तक जो कार्य हुआ है, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वह अधिकतर व्यर्थ निष्ट हुआ है। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने कार्य को विषय निष्ट बनाने का प्रयत्न करें ।

मुझे विश्वास है कि हमारे शिक्षा मंत्रालय का सांस्कृतिक विभाग जिस के सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं वह हमारे ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए, उसका विकास और उसका संवर्धन कर सकेगा और विश्व को हमारी संस्कृति के स्वरूप को बता सकेगा और चाहे कोई किसी भी प्रदेश अथवा केन्द्र शासित क्षेत्र का रहने वाला हो वह उस क्षेत्र या प्रदेश का नागरिक नहीं है बल्कि भारत का नागरिक है, ऐसा आभास उनको करा सकेगा और हम सभी नागरिकों में राष्ट्रीय एकता की भावना और भारतीय संस्कृति के प्रति स्नेह और आदर की भावना का उदय कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है ।

हमारे सांस्कृतिक विभाग को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि हम विश्व को यह बता सकें कि हमारी संस्कृति यह है :

जिन्हें शक हो वे करें और खुदाओं की तलाश,
हम तो इंसान को दुनिया में खुदा कहते हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं सांस्कृतिक विभाग के अनुदानों की मांगों का हृदय से समर्थन करता हूं ।

*SHRI P. A. SAMINATHAN (Gobichettipalayam): Hon. Mr. Speaker, Sir, on behalf of my party, the Dravida Munnetra Kazhagam, I rise to say a few words on the Demands for Grants of the Ministry of Education and Social Welfare.

At the very outset, I would like to refer to the solemn assurance given to this House by the then Minister of Parliamentary Affairs, Shri Raj Bahadur. He assured this House that Hindi would not be indirectly imposed by using it in the Roman script in the Parliamentary Papers as also in documents like the Annual Reports of the Ministries of the Central Government. I am pained to say that this assurance to the House has been violated. You will see, Sir, that in all the Annual Reports of the Ministries and in all the documents like the Demands for Grants of the Ministries submitted to this House, Hindi has been used in Roman script instead of in Devanagari script. On behalf of my party, the Dravida Munnetra Kazhagam and on behalf of four and half crores of people living in Tamil Nadu I record my strong protest against the imposition of Hindi in an indirect way by using it in Roman script in all the documents placed before this House and this is a gross violation of the solemn assurance given to this House by the then Minister of Parliamentary Affairs.

13.20 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Sir, education is incorporated in the State List of our Constitution and it is the exclusive responsibility of the State to provide educational facilities to the people. The great responsibility of imparting education has been placed on the shoulders of the State Government. When this is the constitutional position, there is here the Central Ministry of Education which is not required at all. I substantiate this argument by saying that the Central Ministry of Education is just an instrument of inteference in the activities of education sponsored and implemented earnestly by the State Government by imposing unwarranted and unwanted restrictions on the State Governments. Besides interfering in the States' programmes of educational activities, what kind of assistance is being rendered by this Central Ministry to the growth of education in the country? Whatever little assistance that is being given by the Centre goes to higher education. There is no tangible assistance worth the name from the Centre for the growth of primary education among the people in the lowest rung of our society. I strongly condemn the attitude of negligence on the part of the Central Government shown to primary education. As compared to the financial allocation made to education in developed western countries, it is very much less in our country. The very fact that only 1.62 per cent of the Central Government's Budget has been allocated for education, culture and social welfare proves my contention that there is no need at all for the Ministry of Education, Culture and Social Welfare at the Centre. You will be glad to hear that the State Governments spend one-third of their Budget allocations on Education. The Education Department of D.M.K. Government in Tamil Nadu functioning under the dynamic leadership of Dr. Navalar Nedunchezhian has been given 97.23 crores of rupees for 1973-74. If you put together the allotments made for medical education, agricultural education and so on, the total allocation for education comes to Rs. 108.56 crores. This is about 24 per cent of the Tamil Nadu Budget. When the crushing burden of providing the basic necessities of life to the people on the State Government, is there any need for the Ministry of Education at the Centre? While the provision of basic needs of the people like drinking water, rural and urban roads, medical facility, education, the implementation of welfare programmes for scheduled castes and scheduled tribes and backward classes, the im-

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri P .A. Saminathan]

plementation of labour welfare measures, etc., has been made the responsibility of the State Governments, enormous revenue yielding activities like the Foreign Trade, Posts and Telegraphs, Airlines, etc., and the power to issue licences for industries are under the charge of the Central Government. In addition to this, the Central Government have appropriated to themselves activities like education, maintenance of places of historical importance and archaeological interest, museums, libraries containing valuable inscriptions on copper plates and palm leaves and so on. I am sure Sir, you will agree with me if I say that all these activities should be handed over to the State Governments. I condemn the attitude of the Centre to get bloated at the cost of the States.

Sir, a sum of Rs. 53.40 crores was allocated for education last year. But this year only a sum of Rs. 25.85 crores has been allocated for education. If I want to know why the allocation for education has been cut so drastically, immediately I will be given the reply that the subject of welfare of scheduled castes and scheduled tribes has been transferred to the Ministry of Home Affairs. This leads me to the suspicion that since the Education Ministry has done everything that it could do for the welfare of scheduled castes and scheduled tribes and since there is nothing more for the Education Ministry to do in this respect, it has been transferred to the Ministry of Home Affairs. Or, it should be that the Education Ministry has failed to pay adequate attention to the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, it has been transferred to the Ministry of Home Affairs. I shall be happy if the hon. Minister of Education could clarify this point.

I will now refer to the Special Nutrition Programme for Children and Expectant Nursing Mothers. The wisdom of starting such a programme for giving nutritious food to children and expectant nursing mothers, which will help them to restore normal health dawned upon the Central Government only in 1970, after 23 years of our Independence. It was a matter of surprise to me that this Government could think of such a scheme only after two decades of our Independence. It is reported that there are 6 crores of emaciated children in our country due to malnutrition. A medical expert has expressed his opinion that if nutritious food is not made available there is a likelihood of 4 lakhs of children dying within three months. It is to be highly deplored that the Central Government has not taken any constructive steps in this direction, though the international organisation UNICEF has been giving aid for this purpose from 1949. 2.5 lakhs of undernourished children and expectant nursing mothers in Tamil Nadu have been covered by this scheme. In Madras city alone there are 2,10,000 children and 40,000 expectant mothers who are in need of nutritious food. In Tamil Nadu this scheme is in operation in 20 towns. Sir, in this regard, the Tamil Nadu Government have formulated a scheme which is estimated to cost Rs. 10 crores to extend this scheme to backward areas, drought affected areas and to 20,000 slum areas where lakhs of Harijans are living. I appeal to the hon. Minister of Education to approve this scheme of Tamil Nadu Government and to give Rs. 10 crores to Tamil Nadu for implementing this scheme.

Sir, a National Centre for Blind has been set up and a paltry sum of Rs. 18.43 lakhs has been allocated for this. In our country there are two categories of blindness. One category is those who are born blind. The other category is those who lose their sight on account of under-nourishment and for want of nutritious food. The problems of these two categories are quite different from each other. But, here you will be shocked to know that a sum of Rs. 17,000 has been allocated for education to blind children. The number of blind people who cannot get their sight back by having

operations is about 2 crores. They are so poor that they cannot afford to undergo eye operations. If the Central Government want to help crores of blind people in our country, then there must be a Five Year Plan exclusively for this purpose. Crores of blind people in our country cannot get back their sight because they are very poor to undergo surgical operation. The Central Governmen must undertake a massive programme in this direction. Our Chief Minister, Dr. Kalaignar Karunanidhi, after pondering over this problem seriously, has become not only the path-finder but also the pace-setter for the entire country. He utilised his birthday for collecting funds for this purpose. He gave priority to giving eye-sight to the blind in his scheme of activiities. On his birthday he collected donations which he utilised for conducting eye-camps in various parts of the State. All the poor blind people were given free food and free accommodation. They were given free medical attendance. After the operation, they were also given spectacles free of cost. On account of the magnificent initiative shown by our ever-dilligent Chief Minister, in Tamil Nadu more than 1,42,000 poor blind people have got back their eye-sight.

Mahatma Gandhi, the father of our nation, felt his sacred duty to rehabilitate the beggars more particularly beggars suffering from leprosy. Our Chief Minister utilised his another birthday to collect donations for the noble task of rehabilitating beggars in Tamil Nadu. In each district of Tamil Nadu, a beggars rehabilitaion home has been set up at a cost of Rs. 10 lakh each. When a State Government is taking so much interest in these activities, it is no doubt to be condemned that the Central Government have shown scant regard for human misery.

Similarly, a negligible sum has been allocated for the National Centre for Deaf and Dumb. In Tamil Nadu, our Religious Endowments Minister, Thiru Kannappan, has been very successfully utilising the Temple Trust Funds for this humanitarian work. Orphanages, Homes for the Disabled Orphans etc., have been set up by the Temple Trusts. I say these things here because the Central Government can usefully emulate this illustrious example. The Central Government should take steps to establish in each District Headquarter a Home for Orphans which should help at least 5000 orpnans in the district.

Even after 25 years of our Independence, the Central Government have not constructively reformed our educational system. I am constrained to say that this Government want to turn out from colleges and schools youths who will be fit for white-collor jobs only.

If this is not the motive of the Government, our educational system should have been transformed for the benefit of the people long time ago. During these two decades so many Commissions and Committees have gone into the question of educational reforms. In 1948-49, the Commission under the chairmanship of our former President, Dr. Radhakrishnan went into this question. In 1952-53, the Secondary Education Commission under the chairmanship of Dr. Lakshmanaswamy Mudaliar made many useful recommendations. In 1964—66 another Commission under the chairmanship of Dr. Kothari examined the entire gamut of our educational system and made many worthwhile recommendations. I want to censure the Government on their failure to implement in full the recommendations of these Commissions. Besides this, in 1968, the Resolution on National Policy of Education was unanimously passed by this House. I would like to know from the hon. Minister of Education what steps have been taken to translate this Resolution into constructive action.

Sir, the University Grants Commission gives grants directly to private

[Shri P. A. Saminathan]

colleges. This has enabled many people to make education as a commercial proposition. At the same time the Government Colleges are denied of any financial assistance from the U.G.C. You cannot deny that the State Government is the nearest agency to know about the financial requirements of Colleges. I would urge upon the Education Minister that the U.G.C. should hand over the money to the State Governments and entrust them with the power of disbursing the funds to the Colleges.

Under the scheme of providing employment to unemployed teachers sponsored by the Central Government in 1972-73 30000 teachers were enrolled throughout the country. Under this scheme, only 900 teachers from Tamil Nadu got the employment opportunity. But, Madhya Pradesh having the same population as that of Tamil Nadu got employment for 3000 teachers. 4800 teachers in Bihar having a population of 5.5 crores got the job opportunity. Rajasthan having a population of only 2.5 crores got employment for 2600 teachers. I have no alternative but to pass stricture on the Government for this partiality shown to Tamil Nadu. In Tamil Nadu 22000 trained teachers are unemployed. We can create employment opportunities for 80000 teachers, if the Central Government are keen to implement this scheme on the basis of actual requirement rather than on any partial performances.

Here, I would like to refer to the issues raised by the hon. Lady Member belonging to the ruling party from Tamil Nadu who participated in the Debate yesterday. She has made a valiant attempt to connect the Haryana Teachers' strike and the strike of Graduate Teachers of Tamil Nadu. Generally women express their views after a thorough deliberation of the issues involved. But, in this case the Lady Member has expressed her views without making any analysis of the issues involved. The Opposition Parties demanded a discussion in this house on the strike of Haryana Teachers, but the ruling Congress Party Members including the hon. lady Member refused to permit such a discussion in this House. Does the hon. lady Member know about the demands of the Graduate teachers of Tamil Nadu? She must not be knowing because she is new to politics. She is enjoying the fruits of politics with the munificence of the Dravida Munnetra Kazhagam. Out of 5 demands of the Graduate teachers, three demands have been accepted by the Tamil Nadu Government. Sir, I would like to inform the house through you the contents of the other two demands of the Graduate teachers of Tamil Nadu were such that any Government with some sense of responsibility cannot accept. One of the demands was that the Tamil teachers should not be made the Headmasters or Principals. Their second demand was that the Tamil teacher should always get less than what a B.T. teacher gets. These Tamil teachers are their own colleagues. They have done as much to the cause of education as the Graduate teachers have done. Can you expect any Government in the world to concede to such a demand? If the hon. lady Member has got the courage, let her come to Tamil Nadu and issue such a declaration. It is easy to speak politics inside this House. She also referred to the incidents that occurred in Tiruchirappali and Tirunelveli in which some students were involved. But these two incidents are under judicial enquiry. I think that the hon. lady Member does not know about the parliamentary procedure that any matter under a judicial enquiry should not be referred to in this House. Her father was a leading lawyer. I only sympathise that this lady member has not got even an iota of legal propriety in her.

I would refer to another important issue. The places of historical importance and archological interest are spread far and wide in our country. In consequence, the Central Ministry is not able to exercise ade-

quate supervision in their maintenance. I am afraid that they will all become relics of history if they are neglected like this by the Ministry of Education. I have to point out regretfully that the Centre does not permit the State Government even to honour the sentiments of local people. The Centre seems more interested in maintaining the past glory of the places rather than to associate their past glory with the present aspirations of people. I need not say about the refusal of permission by the Centre to erect a statue of the King Raja Rajan who built the ancient temple in Tamil Nadu.

I would appeal to the hon. Minister of Education that the ancient archaeological monuments and museums should be handed over to the State Governments who are in a better position to maintain them property. The maintenance and management of Thanjavur Saraswathi Mahal Library should be handed over to the State Government of Tamil Nadu.

Before I conclude I would refer to the fact that during the Fourth Plan an outlay of Rs. 25.45 crores was proposed for the development of Indian languages. It is deplorable that for languages other than Hindi only a sum of Rs. 1.35 crores had been allocated. During the Fifth Plan, Rs. 25 crores have been proposed for Hindi alone. This is what the hon. Minister of Education has stated. I would like to warn here that every step you take for the development of Hindi and for the imposition of Hindi will to that extent endanger national unity. I am sure, Sir, that the Central Government are aware of the strong feelings of 4.5 crores of people in Tamil Nadu. I don't think that the memory of the Central Government in regard to the anti-Hindi agitation in 1965 in Tamil Nadu has yet been obliterated The Army was called to quell the emotional upsurge of the entire people of Tamil Nadu and the State was given a bloodboth. I hope that the Central Government are not interested to create such a situation in Tamil Nadu. The people of Tamil Nadu will ever be ready to shed their blood in protecting their rights. From 1938 onwards eminent Tamil leaders have opposed the Hindi imperialism. Thanthai Periyar, Perarignar Anna, Thiru Vee Ka and so many illustrious Tamil leaders had so far unequivocally opposed the imposition of Hindi on non-Hindi people. Our great leader Arignar Anna, who became the Chief Minister in 1967, gave up the three-language formula and he implemented vigorously the two-language formula in Tamil Nadu. I appeal to the hon. Minister of Education not to precipitate a crisis by trying to impose Hindi on non-Hindi speaking people.

Lastly, the Central Government every year celebrate the memory of eminent personalities of our country. But so far, the Centre has not cared to honour the memory of great Tamil savants like Thiruvalluvar, Plango Aidgal Kambar, the revolutionary poet Subramania, Bharathi, another eminent poet Bharathi Dasan and other eminent personalities like Yogi Vemana from Andhra Pradesh, Narayana Guru and Vallothol from Kerala. I appeal to the hon. Minister of Education that he should bestow his personal attention in arranging programmes for paying homage to these great men from Southern States .

With these words, I conclude.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Congress Members may take not more than ten minutes. There are 34 of them still in the queue.

Shri Parashar.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR (Hamirpur): Sir, I rise to support the Demands presented to this House by the hon. Minister for Education. I heard the speeches from the Opposition side, especially, the one made just now by D.M.K. Members; wherein the Ministry for Education at the Centre was called Ministry for Interference.

[Prof. Narain Chand Parashar]

On the one hand you are calling it as the Ministry for Interference and on the other hand, you are asking for Central assistance to various programmes in the States. Is it that you are interested only in money and not in any qualitative improvement of educational development? We must ponder over this and examine this in great depth. Unless India emerges as a nation, it is no use creating this State or that State. There can be no State or emergence of a nation unless we have a coordinated development programme for education for the whole of the country. My grouse, on the other hand, is that this wonderful book with so many of the printed words does not speak a word about the coordination of various educational programmes at the Central level.

As a member of the Central Advisory Board on Education, I moved a resolution in the CABE meeting on 19th September last year requesting for the Minister of Education at the Centre to constitute a committee to examine the Central responsibility in education. Later on it was changed that it should be a committee to examine the Central responsibility in education in the existing constitutional pattern. But the State Education Minister did not relish this idea and in the answers to my questions in the Lok Sabha, I have not so far got a clear assurance whether or not a day would come when we would examine what exactly is the Central responsibility in higher education or in education at all. There are resolutions for making education a concurrent subject and there are recommendations. A resolution by Shri Samanta was circulated for public opinion and some people supported it. But that as it may, since education is the force that will shape the destiny of the nation in the end when all these passions have calmed down and are spent, when all the regional chauvinism and the sparks produced here and there have died a natural death. It will be the Central Education Ministry which will have the final say in the shaping of this destiny. So, I request the Minister that within the existing constitutional provisions, we should examine this question in depth.

There are various sectors. The Central Ministry tells us that they propose to start one primary school in each block and one model higher secondary school in each district as pace setters. It would have been better had we been given the actual names of the places or districts where these schools have been set up and where they are proposed to be set up during the current financial year for which we are considering the demands. A vague reply, shorn of exactness is something which is not palatable to me at least.

In a recent book by Gunnar Myrdal the author of *Asian Drama* it has been suggested that all developing countries are suffering from an inverted system of priorities in the system of education. That is, greater attention is paid to the financial and other aspects of university education, lesser to the secondary education and the least to the primary education. 23 years ago, the founding fathers proclaimed it as a Directive Principle of our Constitution that primary education would be free, universal and compulsory. I am sorry to say that in these 23 years, it has not been possible to see that the lamp of education is lit in every home. Darkness remains and nobody has paid any heed to it. There are universities which are becoming increasing centres of violence. As a teacher, I hang my head in shame that one university in this country has come forward with the plea that there should be a police force of the university authorities, so that they can strut and dance in authority like a District Magistrate or SHO. It is the killing of the teacher that has taken place and the upgrading of the SHO or District Magistrate by planting him in an educational institution.

According to this Report, Delhi University presents a very fine spect-

acle. 1869 persons have registered themselves for Ph.D Over a lakh of students are getting education directly or indirectly from the colleges of this university, through correspondence courses etc. But reference could also have been made to the recent disturbances in Delhi University and some sort of a complete picture presented to the country as to what the Delhi University is. Even now the Delhi University Teachers' Association is threatening to launch an agitation for certain reasons. In this capital city of ours, the teachers who have put in some years of service outside are at a disadvantage as compared to those teachers who have started their service here with the result that some of the teachers in Punjab have become junior to their own pupils here because of the strange policy of the selection grades approved by the Academic Council of our University.

There is growing violence and the darkness is thickening in the B.H.U. and the A.M.U. These very high-sounding names are bringing to us the signals of a developing doom and, unless we act in time, we would be put to a great inconvenience in the coming years. The rising generation of our country is getting the symptoms of a disease. I have before me a statement issued by Mr. Harivansh Bahadur who is the President of the B.H.U. Chhatra Sangh, dt. 4th April, saying that there are RSS centres in the University called the Banaras Hindu University and 32 *shakhas* are being held regularly. If you cannot control communalism in one university, with what claim can you come forward before the country to wipe out communalism from the entire country? You cannot condemn, control and eradicate communalism from the A.M.U. and the B.H.U. and there are voices of communalism coming in the garb of minorities threatening the very unity of this country. I want to sound a note of warning that unless the RSS citadel is permanently destroyed from the B.H.U., nothing better can be expected. You will have every day the Vishwavidyalya *bandh* which was organised on 19th March, 1973 and other funny things of the type and you will have strikes in universities and nobody will be able to save the persons who are working there.

Recently, I visited the Vishwabharti (Central) University and I found to my dismay that there are growing signs of violence there too. You have come forward with a proposal that you want to set up a Central University in north eastern India. I wish there could be some comparative study of the Central Universities vs. State Universities. After all, when there is a demand of one area, we are going to cater to that area and give a Central university. But there are certain other parts of the country where the State universities are flourishing and these State universities are nothing better than the boards for the game of chess played by regional politicians for making their own recruitment, promotion and all that.

The hon. Minister of Education comes forward with a plea that the Central Government has no authority to intervene because Education is a State subject. May I invite his kind attention to the barbarism let loose on teaching community in the recent years by certain regional politicians in the States, exploiting the regional autonomy for their purpose. Teachers have been transferred; they have been harassed; they have been intimidated; they have been shadowed by C.I.D. and other things have been done to them and all in the name of regional autonomy. Education is a State subject but a young man is not a State subject; violence and communalism are not a State subject. It cannot be controlled by any Chief Minister or by any Education Minister or by any Vice-Chancellor. It will spread with a fast speed. Nobody will be able to control it if it is not controlled in a year or two.

Similarly, may I bring to your attention the great injustice that has been

[Prof. Narain Chand Parashar]

done to the hill areas. The hon. Minister is the Chairman of a Committee which was appointed in September. What a wonderful Committee which has had not even a single sitting. I do not know what were the reasons. The Plan allocations are being finalised. But the Committee is still to meet.

Then, there is one wonderful institute, the Ladakh Institute of Higher Studies which was envisaged by our late Prime Minister Pandit Nehru as an institute of higher education corresponding to almost a university. But it was down-graded to a higher secondary school. I say that it should be restored to its original shape so that the soul of Jawaharlal Nehru may rest in peace and the students from border areas, who came with high hopes to get integrated in what was euphemistically called the mainstream of national life would be able to get the benefits of higher education as well as be able to preserve something of their past culture and heritage.

I want to bring other important point to the notice of the Education Minister. Unless we establish libraries in each one of the community development blocks, though on a small scale, from the Central pool we will not be able to help the educated, uneducated and semi-educated masses who will be able to get a few bits of modern knowledge from their school-going children. So, I would request him to have a programme for a network of libraries in all community development blocks on the pattern of the primary schools or model schools, because one national library is not enough. With these words, I support the Demands.

SHRI HAMENDRA SINGH BANERA (Bhilwara): Sir, after twenty five years of independence we have now come to the final conclusion that there is something basically wrong with our education policy. Time and again from all corners of this nation and from people of all spheres there has been a constant demand that the education policy should be changed, that the education policy introduced by the Britishers to produce clerks should be shed and we should frame an education policy which will develop nationalism in the youth of this country. Our education policy should be job-oriented because the most acute problem before our nation today is unemployment among the educated masses. Unless and until you change your education policy and make it job oriented, the problem of unemployment can never be solved.

We have always condemned violence in the colleges and universities. But we have never detected; the root cause for the unfortunate happenings which affect everyone of us. The Education Minister has gone on record stating that a draft is being prepared to overhaul the policy of the Government of India. I hope he will be consulting the top educationists of the country before he implements it. I am saying this with a fear because a deep-rooted conspiracy is going on in the matter of higher education in India. I pray sincerely to the House to consider this aspect impartially and thoroughly and condemn the anti-national activities taking place right under the nose of Prof. Nurul Hasan.

Whenever a proposal comes before this Ministry in regard to education, even though the Minister accepts it, he quietly comes with an excuse that education is a State subject. But now with their party in power in nearly all the States and with the appointment of Chief Ministers as the Subedar of the Centre, I see no reason why he should not be able to convince them and make them implement it.

No doubt, the Government of India is appointing 60,000 teachers to help the States and the Union Territories in the field of promoting elementary education. But I pity the condition of the teachers of primary schools. See how low paid they are while we expect them to groom a child who has

to shoulder the responsibility of this great nation. In Japan the pay of a primary school teacher and that of a college lecturer are the same. We have still to attach a great importance to this section who have to contribute a great deal in the field of education and do everything to improve their service conditions. Please do not leave them at the altar of Panchas and Sarpanchas as is prevailing in Rajasthan where they are passing through torturous conditions.

I am sorry to say that the Central Government is neglecting its responsibility in the Union Territory of Delhi. The Education Directorate of Delhi has granted Selection Grades to those teachers who are no more in service, and those teachers who are entitled to them have been compelled to take the shelter of High Court. Teachers regard it as an act of dishonesty practised in the temples of learning. In schools, posts of Vice Principals, Post Graduate teachers, etc., are lying vacant. Senior teachers are frustrated on this account as well as on the account that their juniors are drawing more than what they are drawing. Faulty promotion policy, service rules, recruitment policy, etc., of the Directorate of Education, Delhi, are the main reasons for their discontentment. Selection Grade in aided schools should be implemented immediately as per the rules in government-owned schools Here I may mention one very interesting point. The Pay Commission has considered the grade of pay of the teachers which was prevalent three years back; now the grade has been improved but the Pay Commission only considered the older grade.

I also want to bring to the notice of the hon. Minister the state of affairs in the Kendriya Hindi Nirdeshalaya. Its director has not been appointed for the last three years, while the Chairman is working on a temporary basis. The plans to promote Hindi are not being completed because of shortage of staff caused by retrenchment from time to time. Urdu Seminars were held in Hyderabad and Lucknow about four months back. Rs. 80,000 were drawn to meet the expenses, but the account has not yet been submitted. Why is a separate Board for Urdu being set up? My Party has no objection to the development of this language, but the whole affair smells fishy. Because the U.P. elections are fast approaching and this Government has *mala fide* intentions in wooing the voters, they are giving it the unrequired importance. There is a strong rumour of Urdu being promoted as Raj Bhasha. I may warn the Government that any such thing at this juncture will have serious consequences.

My friends have discussed the state of affairs in the Banaras Hindu University and the problem of student unrest in the other Central Universities. Two years back when I was speaking on the Demands of the same Ministry, I had warned the then Education Minister that if the Vice-Chancellor of Banaras Hindu University, Dr. K. Shrimali, was not removed, the state of affairs in Banaras Hindu University were bound to deteriorate and it would become worse.

The present conditions there are due to the fact that the Vice-Chancellor has failed to win the confidence of the students and the teachers. His failure in curbing the activities of the unsocial elements in the University, the partiality observed in promotion of lecturers and appointments of the Heads of Departments and his only desire to activate communists who have been defeated in the elections to the students' unions, favouritism, nepotism, administrative inefficiency and the embezzlement of Rs. 13 lakhs are some of the factors responsible for the undesired climate in that temple of learning.

14 hrs.

The University was closed four times *sine die* and the students lost

[Shri Hamendra Singh Banera]

about nine months of their studies. That come to one academic year. Every time the University was closed the students had to go to their home and come back which alone cost Rs. 35 lakhs. Ten stndents were jailed from 10th March, 1973. When the Members of Parliament from the Opposition went to Varanasi, the Jail Superintendent did not allow them to meet these students. There are about ten to twelve charges—charges of murder, arson and dacoity, etc. against them. I may warn, Prof. Nurul Hasan, I know Shri Kanu Lal Shrimali, I know he is your pet. To restore normalcy in the Banaras Hindu University, you should immediately constitute a commission of inquiry, it should be a very high-power commission and it should go into all these problems in the University. I appeal to the House and the Minister of Education to try and solve once for all this problem, that is, the political interference in the Universities. We are prepared to stay away completely provided all other Parties strictly observe it. But if you want only the Communists and Congis to participate, I am sorry, we will not allow them to do it. The Vidyarthi Parishad has a clean record and after resisting violence from Communists, that organization is held in high esteem as a disciplined one and a model for others.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Why indulge in self-confession.

SHRI HAMENDRA SINGH BANERA: Now I come to higher education.

Higher Education in India, it seems, has become the exclusive domain of the people having leftist leanings particularly of the CPI brand. During the last few years, most of the appointments have been made to favour scholars who excel not in their scholarship but in their being adherents of a particular ideology and belonging to a clique. A conscious and forceful bid is being made by the leftist forces to stage, if I may say so, a *coup* in the institutions of higher learning. There is a lot of demand for what can be called 'committed' scholars who can re-write our history without any scruples as to the objectivity required of this discipline; who can pronounce their judgment afresh on the doings of Aurangzeb and Shivaji, to toe a given line by their high command. A glance at the organisation and functioning of such bodies as the Indian Council of Historical Research, Indian Council of Social Sciences Research and institutions like the Institute for Advanced Studies, Simla and the Jawaharlal Nehru University in New Delhi would reveal that most of the people who have been given the plums happen to be these 'committed scholars'. More often than not their achievements in the field of scholarship have only been a secondary consideration in entrusting them with the jobs they now do. I would now like to cite a few instances to subtantiate what I have just said.

The Indian Council of Historical Research, a brainchild of our present Education Minister Shri Nurul Hasan, has been constituted in such a fashion as to distribute the official patronage to the people who have been or still are the members of the CPI. The present director of a project on history has a basic degree in political science. Of course he was Secretary of the district CPI in Bihar. Another youngman who is not eligible for any scholarship anywhere, having a III Class in his BA and MA has been awarded a fellowship of Rs. 500 p.m. recently. I can give the names if you want. These scholars confine their research to a particular type of material and have a declared contempt for regional languages and various dialects of northern India spoken in medieval times.

The Indian Council of Social Sciences Research and the Institute of Advanced Studies do not conform to the norms in matters of selection laid down by themselves. For instance a person out of employment

was appointed on the staff on an *ad hoc* basis in the early years of the establishment of the ICSSR and soon after awarded a fellowship of Rs. 1100 p.m. He was later absorbed as an Associate Professor in the Jawaharlal Nehru University.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not use the floor of the House for going into these individual cases. You can write to the Minister and he will let you know.

SHRI HAMENDRA SINGH BANERA: If he wants, I can name them.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, no. You have already exceeded your time. These are individual cases. You can as well write to him and draw his attention. Please conclude.

SHRI HAMENDRA SINGH BANERA: About Jawaharlal Nehru University the most favoured child of the Education Ministry the less said the better. People have made it a springboard for more lucrative avenues and in doing so they shift from one discipline to another at their convenience. Nobody knows who will become a professor or an associate professor there. A gentleman who was a Reader for only a few months at the university next-door was offered a professorship and is now manoeuvring to stage a comeback to his parent institution as a senior professor.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now. You can pass on these details to the Education Minister.

SHRI HAMENDRA SINGH BANERA: Government is not doing much in promoting among the youth of this country the necessary spirit of nationalism. I hope the Minister will spell out some concrete programme which will develop self-confidence amongst them by opening new avenues of employment. More youth hostels should be opened in the country. Again, don't pay attention in the urban areas only. Massive programmes of sports should be undertaken both in rural and urban areas. Please pay adequate attention to village areas also. This is very important. I need not have to tell you the advantages but it will certainly increase discipline and better understanding between themselves. Everyone knows the way Raja Bhalinder Singh, the IOA Chief failed at the Munich Olympics. The Government has not dealt strictly with the persons who are guilty of projecting such a nasty picture of our nation. I can understand the facts why we lost and if improved next time we will again become the champions, but, what about the misbehaviour of these senior officials? Will they be let free or will action be taken against them?

Lastly, I want to strongly make a demand for setting up a university at Ajmer. I know the Rajasthan Government has appointed a Committee headed by Dr. K. L. Shrimali which was going to decide where the location of a university in Rajasthan has to take place. He is busy in the politics of Banaras Hindu University. So, I pray that he should be relieved from there and sent to Rajasthan where he can solve our problem.

SHRI SHYAM SUNDER MOHAPATRA (Balasore): Mr. Deputy-Speaker, Sir, listening to the debate I am reminded of the great Prime Minister of U.K., Mr. Gladstone, who while moving the Education Bill to give education to the people of England said:

"Let us educate our masters."

It was a great saying because if we did not educate our masters we will not be doing justice. I feel I must invoke the couplet:

"Lead kindly light Amidst the encircling gloom lead Though me on Over crag and torrent till the night is gone Lead me on"

[Shri Hamendra Singh Banera]

The illitrates of India today invoke the kindness of the Government of India to lead them through darkness to reach light. In our country there are more than 150 million illiterates who should get education. The Directive Principle says: We should give education to people upto the age of 14. After 25 years of Independence the illiterates in India are still groping in darkness and if we do not educate the people the country will never progress. The standard of a country's progress is measured by the standard of education that the people have. If we do not educate our masters, government will also become government of the illiterates as many political scientists say.

I must now bring to your notice the unrest, disappointment and frustration in the youth which culminated in the beginning of a naxalite movement in our country. There are more than 18,000 people in our jails who are naxalites and are rotting. Many of them are children below the age of 18. What was their fault? Frustration. They wanted jobs; the education could not give any jobs. Our education is not job-oriented. The students must feel that they are participants in the making of a nation. I remember Dr Chandrasekhar who was Member when he visited the Chinese Republic he went to a university and met the Rector of the University and said that he wanted to visit the hostel and campus. The rector took him round but he did not find a single student. Dr. Chandrasekhar asked where the students had gone. The Rector said they have gone to the fields. Dr. Chandrasekhar asked what they were doing there. The students should be in the university. Then the Rector said our education system is different. They have to participate in the making of the nation. They are now helping the peasants in the harvest season The Meteorological Department has warned that within 7 days there will be a big cyclone and, as such, the harvest has to be over within 7 days. This is the type of education which is needed. The students have to feel that they are part of this great nation. If there is trouble for the nation it is as much for their parents as for them. I asked the students have they become desperate? They have not. Who is responsible? All of us—the teachers, the guardians and the government—are responsible for this because we have not given them an opportunity to participate in the re-generation of our country. Every year the number of illiterates is growing. 1.60 crore illiterates are added every year. Who is responsible for this? In the Asian Conference in December, 1970 the then Education Minister, Dr. V. K. R. V. Rao, said we should have pilot projects. Well, seeing the news I thought it is something like pilot industry that he wanted that the country should have pilot projects to educate the people.

I say the students are very poor. Why not take up a scheme that in their off-time students can go and educate adult illiterates? The hon. Minister is a great professor. He knows that the student are in difficulty. They must do something. If every student is given 20 a month to educate a required number of adult illiterates, he has done a great job. Why not take up a scheme like that?

In our country, there is no such thing as voluntary labour. Our great Prime Minister, the late Pandit Nehru, sent a group of experts to China to see how through voluntary labour, a great dam had been constructed. The experts were surprised to know that a great dam was constructed by voluntary labour in China. Why not ask our students to do some road work, bridge work, railway construction work and other things? That is how students should participate in the making of the nation.

After the last great war, the entire nation of Japan was demolished, almost crumbled down to dust. The same thing happened to the German nation. Their entire society almost crumbled to dust. But what happened then? Everybody participated in the making of their new State.

Today that small, tiny group of islands constituting Japan is helping us as an industrial country. They claim they are the biggest industrial state in the entire South East Asia region or one of the biggest industrial countries in the world.

The students and youth have to be made to feel that they have to contribute something to the making of the nation. If you ask them to do voluntary labour, you must set before them an example of your own honesty and integrity. You must also participate and ask them to do likewise. You cannot move about in limousines or sit in air-conditioned rooms and expect the college and school boys and youth to participate in the making of the nation. Such a slogan will be hyperbole and nonsense.

The universities have become almost citadels of corruption. I am a teacher myself. I feel ashamed to say this. But I have to because I have to bring to your kind notice, and through you to the notice of the Government and people, how these universities have become citadel of corruption. This is because the teachers of today are not the teachers of olden days. The great Maharishi Janaka, who was a great philosopher, who had spiritual vision, had to walk miles to meet his teacher Yagyavalkya. We read about it in mythology. Where is that sentiment today? Today the students and teachers sit across the table, drink alcohol and discuss vices, something which we can never tolerate. They say 'we are friends'. Of course, we are friends, but there should be a distance kept between teachers and students. The teachers have no character. Naturally the students have no character. The parents have no character; naturally, the students have no character.

AN HON. MEMBER: What about us?

SHRI SHYAM SUNDER MOHAPATRA: So we have to build up a new society.

Everyday we hear of some ugly incidents. We heard the other day that some boys in Delhi University tried to rape a girl. Today I was reading in the newspapers that the Supreme Court had upheld the Patna High Court's strictures on some college boys who had engaged in a nude demonstration of themselves in front of a girls' hostel in Patna.

Who is responsible for all this? Is this our civilised society? Is this the society India had in bygone days? India was one of the pioneers in the movement of cultural philosophy. Today that has crumbled down to test, with boys making demonstrations before girls, before our own sisters and mothers.

Then mass-copying is a great problem. Students go on copying in the examination hall. We could not think of it in our days. Could anybody in our days think of teachers and students drinking alcohol and smoking together? Why do they do it. The students want jobs. We have to give them jobs. I feel that if the right to work was a fundamental right, there would have been no trouble. The right to primary education should have been a fundamental right. But it is not there. Education is the means to harmonise development of the mind and soul, said the great Plato, many many centuries ago. How to bring about harmony between mind and soul, how to bring about the feeling that 'I am part of this entire universe, feel that my mind and soul is part of the entire universe. We have to do this by education.

I wil not take much time. But I will just quote from an article written by Shri Aswini Roy in the *Hindustan Times.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Give a summary.

SHRI SHYAM SUNDER MOHAPATRA: He writes that the social status of the professor in Germany

[Shri Shyam Sunder Mohapatra]

can be the cause of jealousy in many countries. One additional evidence of the status is the number drawn from their ranks into the prize political post of the country. He is a permanent civil servant with salaries equivalent to those comparable to the highest civil servant; the diplomats in that country are drawn from the ranks of professors. That is the status they enjoy. And what is the status of the professors in our country? The status of the college teacher is this: he feels that he is less than a peon; the college teacher feels that he is less than a domestic servant in Delhi. In Delhi, a domestic servant gets probably more amenities than a college professor. Unless we give the professors that status in society—they are no less than Ministers; they are no less than scientists; they are no less than military generals; they are the makers of our country—our country will not go ahead.

I hope the hon. Minister will pay them more money and bring a regeneration of our educational system.

SHRI B. S. MURTHY (Amalapuram): Mr. Speaker, Sir, I rise to support the demands made by the Ministry of Education and Social Welfare. Sir, this Ministry is today suffering from a stunted growth. I do not know why this Ministry does not deserve a Minister of Cabinet rank; not that a Minister of Cabinet rank will add anything great, but the country at large will be able to understand that the Ministry has been given a place of pride. For many years, this Ministry has always been treated as a Cinderella before marriage. I do not know when this Ministry will get itself married like Cinderella and get a better status than it is enjoying today.

AN HON. MEMBER: He is Prince Charming, as Minister.

SHRI B. S. MURTHY: Which Minister? Both of them are professors; and professors make very bad husbands, often, excluding honourable exceptions like the Deputy-Speaker

Sir, I am afraid that the Ministry is not able to do justice to this subject not because there is anything wrong wih the people at the helm of affairs but because of the very attitude of the nation towards this subject. India has given the highest place for education. The Sanskrit sloka says, *Vidya Viheenaha Pashu*: the man who is not educated is a *pashu;* he is an animal. If that is the idea with which India has always given the highest place for education, how is it being done today? The most shabby treatment is given to the subject of education. I do not know why education has fallen on bad days.

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash): Bad hands.

SHRI B. S. MURTHY: Yes; that is in Tamil Nadu. (*Interruptions*) Sir, one simple example is enough to state how things are deteriorating. In 1947, the illiterate population in India was computed to be 298 million, and this figure rose today to 386 million. That is, 88 million more have been added. At this rate, with this population explosion, how many years does India require to make cent per cent illiterates? It is a very serious matter. It is not that the Ministers only or the Government alone have to think of it; but it is the whole nation that should think of it.

Again you have promised universal, compulsory, free primary education 25 years ago. In many places education facilities are not there and I do not know how you can call it universal. I want to talk about primary education only because that is the crux of the problem. If 100 children are admitted to class I, only 50 reach the fifth class and by the time they go to the 7 or 8th class, the number dwindles to 25 and perhaps it comes down to 10 or 15 at the higher secondary stages. Why is there so much loss in terms of education? I do not know why the Government has not thought of this and appointed a committee to remedy this wastage in the primary classes

If you neglect primary education, there will be neglect all along the line. Some friends said how the colleges and universities were seething with persons who had gone there, not for studies but for other purposes. Primary education is the foundation and every effort must be made to see that healthy and good primary institutions are started in all the States.

There is a move today to have new primary schools and call them by grandiose names. I do not want education to be divided; one community or person to have one type of education and another, a different type of education. If you want to build an integrated nation, children must be brought together and given education and other opportunities of growth. Children should live together and learn to love each other as brothers and sisters; from that stage we must build up. If you are thinking that leaders of political parties and Members of parliament or the legislative assemblies could meet in Kashmir and promote national integration, it cannot be done it is sheer waste. We must start with the children and instil in them a sense of nationalism and that is laying foundations for national integration Therefore, I am anxious that more money should be allotted to primary education.

How many of those so-called new schools are being established? It should not be limited to the children of the privileged, rich class. 50 or 60 per cent of the seats should go to children from backward and other communities, to the weaker sections. Otherwise these schools will not thrive and there will be revolt against such schools. The Ministry should take early steps to see that 60-70 per cent of the seats in these newly-started schools go to these backward communities.

In many places there are schools managed by the community development blocks. The role of the Community development Blocks is very bad. So much so, many teachers are today resigning in revolt against the maltreatment meted out to them. I would like to tell the Central Ministry that there must be reproachment between the State Governments and the Central Government in order to see that Education is not entirely the monopoly of the State Governments.

Now, a good friend of mine, Shri Parashar said that education should be the Central subject. But, what about the nation? We cannot divide them into States and Central subjects. The building of a nation should be the entire responsibility of the Central Government. The State Governments may also participate and take the responsibility. I do not want to say that the State Governments need not wash off their hands of this responsibility. But, the Central Government should see that the educational policy is such that they build up a healthy nation. This is completely one with our national goal.

Once again I would like to emphasise that casteism and communalism should be avoided. About this I do not think either the State Governments or the Central Government is doing anything. Even to-day, there are a number of villages where caste-Hindu children are not being sent to the schools where the scheduled castes or backward class teachers are working. I do not know whether any enquiry has been made to find out how many schools are like this and how many of the teachers have been transferred. I would like the Centre to look into the matter and see that education really develops a nation which will become healthy and strong.

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव सदन के सामने रखे हैं और शिक्षा मंत्रालय के पैसों में कमी न हो, कटौती न की जाय, लगभग सभी सदस्यों ने इस बात की मांग की है—इस के लिए मैं उन के प्रति आभार मानता हूं।

[श्री डी० पी० यादव]

माननीय सदस्यों ने जो सुझाव रखे हैं, उन में कुछ आलोचनात्मक हैं और कुछ रचनात्मक, मैं प्रत्येक बिन्दु पर तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इस माननीय सदन के सामने आश्वस्त हो कर और मुस्तैदी के साथ यह कहना चाहूंगा कि पिछले 25 सालों के अन्दर अगर हम ने कुछ गल्तियां की हैं तो अब हम उन को दोहराने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारी जो गल्तियां हुई, हमारी जो खामियां थीं, हम उन को मान कर चलते हैं। आज देश में कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितने बेकार हैं, इस को बराबर न दोहरा कर, अब तो हमें एक ठोस रचनात्मक धरातल पर काम करना होगा।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी जी ने एक बहुत कारुणिक दृश्य खींचा है--हमारे यहां की एडल्ट इलिट्रेसी पर—मैं उन को बतलाना चाहूंगा कि आज हिन्दुस्तान में 38 करोड़ की संख्या निरक्षर लोगों की है, उस में शून्य से लेकर 6 वर्ष तक और 6 वर्ष से लेकर 80–90 साल के जो लोग हैं, उन तमाम लोगों की संख्या निहित है। यदि हम उस की समालोचना करें तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचूंगा कि करीब 6–7 करोड़ बच्चे ऐसे होंगे जो 0 से 6 वर्ष की एज-ग्रुप में होंगे, उनकी कटौती हम पहले कर दें। इन के बाद हमारे पास जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं, उन की शिक्षा पर भी अधिक पैसा खर्च करना, उन को साक्षर बनाने की चिन्ता करना भी इस समय उचित नहीं होगा। इस लिए 15 से लेकर 30 साल तक के जितने लोग हमारे देश में हैं उन की शिक्षा व्यवस्था कैसे हो, हम उन के लिए क्या करें—इस पर हमें एक ठोस कदम उठाना होगा। यदि हम इनकी संख्या को भी लें तो कम से कम 10–12 करोड़ लोग हमारे पास ऐसे हैं। लेकिन मैं सदन के सामने स्पष्ट कहना चाहूंगा कि पांचवीं पंच वर्षीय योजना में सरकार ने यह फैसला किया है कि कम से कम 4 से 5 करोड़ तक ऐसे लोगों को जो 15 से लेकर 30 साल की उमर के होंगे उन्हें साक्षर बनायेंगे। साक्षर केवल साक्षरता के लिए नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए साक्षर बनायेंगे ताकि वे जीवन में ऐसा कदम बढ़ायें जो रचनात्मक हो, उन के लिए जीविकोपादक प्रवृत्ति पैदा करें। इस लिए हम केवल थ्योरैटिकल शिक्षा देने में विश्वास नहीं करते टैकनीकल, वोकेशनल शिक्षा देने में विश्वास करते हैं और ऐसी शिक्षा में विश्वास करते हैं जो उत्पादक हो।

उत्पादन या उत्पादकता शिक्षा में कैसे आये, इस के बारे में लोगों में भिन्न भिन्न विचार हैं। जैसे महामात्र जी अभी कह रहे थे तथा कुछ अन्य सदस्यों ने भी कहा है—अब हमें अपने छात्रों को, निरक्षर बन्धुओं को ऐसे राजकीय कामों में लगाना होगा, जिस से राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करें। अब जहां तक हमारी पोटेंशियेल्टी का सवाल है, मैं इस सदन में दोहराना चाहूंगा—जब जब हमारी युवा पीढ़ी को पुकारा गया, वे राष्ट्र निर्माण का काम करने के लिए आगे आये, बड़ी मुस्तैदी के साथ आगे आये और उन्होंने काम किया। इस से बड़ा दृष्टांत और क्या हो सकता है कि 1972 में जब करोड़ों शरणार्थी आये थे, हम ने छात्रों को बुलाया था और उन्होंने नेशनल सर्विस स्कीम के माध्यम से इस चुनौती का मुकाबला किया— ऐसी दूसरी एक्जाम्पल नहीं हो सकती। अभी कुछ वर्ष पूर्व कोसी की भयंकर बाढ़ को कोई नहीं भुला सकता, उस समय हमारे छात्रों ने जो स्वयं-सेवा की और जो काम वहां पर किया, उसकी दूसरी एक्जाम्पल नहीं हो सकती। जरूरत इस बात की है कि इस अपार शक्ति को कैसे चैनलाइज करें? अतः हमारे मंत्रालय ने इस बात को सोचा है कि इसी साल हम गर्मियों की छुट्टियों में इन तमाम

छात्रों को जो 75 प्रतिशत स्कूलों और कालिजों से आयेंगे और 25 प्रतिशत ऐसे छात्र होंगे जो नान-कालिजियेट्स होंगे, ऐसे लगभग एक लाख छात्रों को अलग अलग कैम्पों में राष्ट्र निर्माण में, खास कर वार-अगेंस्ट-फैमीन के प्रोग्राम में इन्वाल्व करेंगे । यह एक बहुत बड़ी चनौती है । मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगा कि हम भरसक प्रयत्न करेंगे कि हमारा यह कार्यक्रम सफल हो और हमारी युवा पीढ़ी इस राष्ट्र निर्माण के काम में आगे आये ।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लिट्रेसी को एम्पलायमेन्ट से लिंक करना चाहते हैं और इस सम्बन्ध में जो भी सुझाव सदन के सामने आये हैं और हमारा मंत्रालय इस सम्बन्ध में जो कुछ सोच रहा है—उस में हम बहुत जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं, जिस से कि उस में कोई गड़बड़ी पैदा हो जाय । हम ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि जो 100 नेहरू यूवा कैम्प खोले हैं और जिन में 87-88 कैम्प काम भी करने लगे हैं, उन के माध्यम से हम अपनी योजना को आगे बढ़ायेंगे, वार अगेंस्ट डिजीज और दूसरी समस्याओं का मुकाबला करने के लिए उन को तैयार करेंगे । इन तमाम समाज सेवा के कार्यों को पूरा करने के लिए, उन को एक साथ कोआर्डिनेट करने के लिए हम ने ये 100 नेहरू युवा केन्द्र खोले हैं और पांच पंच वर्षीय योजना में प्रत्येक जिले में कम से कम एक-एक नेहरू युवा केंद्र खोल देंगे । इन के माध्यम से जो कालिज के हैं, नान-कालिज के हैं, पढ़े-लिखे हैं, बिना पढे-लिखे हैं, इन तमाम शक्तियों को एक साथ बटोर कर किस प्रकार काम में लगाया जाय, हम ने उस तरफ़ कदम बढाया है, हम किसी भी ब्रिम-पिक्चर से निराश होने वाले नहीं हैं । मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम युवा पीढी की शक्ति का सदुपयोग करेंगे और मुस्तैदी के साथ सदुपयोग करेंगे ।

उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने प्रत्येक प्रखंड और प्रत्येक जिले में लिट्रेसी के प्रचार के लिए लाइब्रेरी की बात कही है । राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन के माध्यम से हमने यह फैसला किया है कि प्रत्येक खंड तक लाइब्रेरी विस्तार की सेवा हम कायम करेंगे । कुछ पैसे की कमी शुरू में जरूर हो सकती है लेकिन जन सहयोग से और नेहरू युवक केन्द के माध्यम से राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन का हमने कार्यान्वयन शुरू कर दिया है, राज्य सरकारों को भी मदद दे रहे हैं और देंगे ।

रह गई यूथ पालिसी की बात, तो उस मामले में मैं आपको बता चुका हूं कि यूथ पालिसी में जो कुछ भी सदस्यों ने कहा है, सरकार एक पालिसी सोच रही है लेकिन उस पालिसी को सोचने से काम नहीं चलेगा, उसका कार्यान्वयन करने से काम चलेगा । पालिसी तो बनायें और उस पर कार्यान्वयन न कर सकें तो सारा का सारा बेकार हो जाता है । हमारे सामने एक टार्गेट होना चाहिए और हमारा गंतव्य स्थान होना चाहिए कि युवा शक्ति का हम क्या सदुपयोग करेंगे । वह पालिसी हमारे मंत्रालय में विचारार्थ है और हमने अन्त में निष्कर्ष निकाला है कि देश के रचनात्मक कार्य में, गरीबी मिटाने के कार्य में युवा शक्ति को हम लगायेंगे और यही हमारी पालिसी होगी ।

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) : बीस साल में हो जायेगा ?

श्री डी० पी० यादव : पांच साल में हो जायेगा । पांच साल का हम आश्वासन देते हैं । पांच साल में जरूर कर देंगे ।

एक और बात माननीय सदस्यों ने स्पोर्ट्स के बारे में कही । हम इस बात को मान कर चलते हैं कि हम बहुत अधिक या

[श्री डी० पी० यादव]

कम गोल्ड मेडल बाहर से नहीं ला पाते हैं। अभी तक हमारा स्पोर्ट्स का काम कुछ ढीला जरूर था, इसको हम मानते हैं लेकिन अब ढीला नहीं है और न होने दिया जायेगा—इस बात का आश्वासन देने दीजिये। एसोसिएशन्स के नाम पर, फेडरेशन्स के नाम पर स्पोर्ट्स में कुछ पालिटिक्स आ गई है—उसको नेपोटिज्म कहिये, पालिटिक्स कहिए, जो कुछ भी कहिए—हम मानते हैं लेकिन हम उस पर रोने के लिए तैयार नहीं हैं। सरकार भी इस बात को मानती है, आप भी मानते हैं और यह सदन भी मानता है लेकिन करना क्या होगा, जो भी आपका निर्देश होगा, जो भी आप चाहेंगे, हमारा मंत्रालय उसके लिए तैयार है। हमने सोचा है ग्रास रूट्स से, जो टैलेन्ट्स हमारे पास हैं सारे देश के युवक, नेहरू युवक केन्द्र के माध्यम से उस को संवारा जाये और उन तमाम लोगों को लेकर ट्रेनिंग दी जाये।

आज स्वीमिंग की बात उठती है, तैराकी की कि हम तैराक हैं या नहीं। हिन्दुस्तान में जितना साफ्ट वाटर है, जितनी नदियां यहां हैं उतनी कहीं नहीं हैं। जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में यमुना बहती है वहां के लोग तैराक नहीं होंगे यह बहुत आश्चर्य की बात है। अतः हमने सोचा है कि हम सौ टैलेन्ट्स को सम्पूर्ण देश से लायेंगे, गांवों से मल्लाहों की फैमिलीज से लाकर एक सौ ऐसे नवयुवकों को तैयार करेंगे जिसमें कोई भी फेडरेशन हमारा काम नहीं देंगे, इसके लिए हम एडवर्टाइज करेंगे सारे देश में और इस तरह से उनको यहां लायेंगे। साथ-साथ हमारे पास आर्चरी की जो विद्या है उसमें भी डिसाइड किया गया है कि सारे देश के कोने-कोने से तमाम लोगों का कम्पिटीशन करा कर सौ लोगों को रिसीव करेंगे और उनको इन्टेंसिव ट्रेनिंग देंगे। दंगल, कुश्ती में भी देहात के जो चुने हुए हमारे पहलवान हैं उनको राष्ट्रीय, अन्तर-राष्ट्रीय स्तर की जो कुश्तियां होती हैं उनमें तैयार करने के लिए सौ पहलवानों को, युवकों को चुनेंगे और उनको तैयार किया जायेगा। हम ओलिंपिक्स से सोने के मेडल लायेंगे, चांदी के मेडल लायेंगे। वैसे हमको मेडल्स में ज्यादा विश्वास नहीं है बल्कि हमको राष्ट्र की हेल्थ में ज्यादा विश्वास है। राष्ट्र की हेल्थ, नेशनल हेल्थ को हमें देखना है, सोने के मेडल को नहीं देखना है। वहां जो पालिटिक्स है उसमें हम पड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। रह गई हमारी टीम्स को विदेशों में भेजने की बात तो पालिटिक्स के कारण कुछ फेडरेशन्स और एसोसिएशन्स जो टीम भेजने में लोगों को प्रलोभन देते हैं और वहां जो राजनीति करते हैं, हमने फैसला किया है कि बाइलेट्रल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्रैम में स्वयं इसको अपने हाथ से करेंगे लेकिन उनको भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, टीम ले जाना चाहें तो ले जायें लेकिन सरकार इसको दूसरों पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बाइलेट्रल प्रोग्राम के अन्तर्गत स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की पर्मीशन देंगे जिससे खिलाड़ियों को संतोष हो कि सरकार उनकी कदर करती है और सरकार में उनका स्थान है।

हमने स्पोर्ट्स के लिए पिछले साल क्या किया, इसके बारे में भी सदन जानना चाहेगा। पटियाला में हमारा एक नेताजी सुभाष स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है उसमें हम कोच को तैयार कर रहे हैं ताकि सभी प्रकार के जो खेल हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में उस खेल का ट्रेन्ड कोच जाये जिससे सारे प्रदेश से टैलेन्ट एक साथ संग्रहीत कर सकें। हम ने अभी करीब करीब एक सौ स्पोर्ट्स कोच को देश के विभिन्न भागों में भेजा है। यह हमारी नेकनीयती का प्रमाण है कि हमने एक कदम इसमें आगे बढ़ाया है और आप इस बात को सराहेंगे।

माननीय सेठ गोविन्द दास जी जो सदा संस्कृति, धर्म इत्यादि की बात करते हैं, मैं उनकी भावनाओं को चोट नहीं देना चाहता हूं लेकिन यह देश जो है इसके संस्कार, इस देश की संस्कृति कहीं दूसरी जगह से उधार मांग कर नहीं लाई गई है। इस देश के संस्कार

और संस्कृति है परोपकार, इस देश की संस्कृति है दूसरों को मदद करने की क्षमता और पिछले साल डेढ़ साल पहले इस परोपकार की जिस क्षमता को हमने दिखाया है उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है । आज हम झूठ मूठ की बातों में पड़कर अपने असली कर्तव्य **बसूधैव कुटुंबकम्** की थ्योरी को भूल जाने के लिए तैयार नहीं हैं । हमारी जो संस्कृति है उसमें हम विश्वास करते हैं । पं० जवाहरलाल नेहरू ने बांदुंग में जो पंचशील के सिद्धांत का अपनाया था उससे बड़ी संस्कृति और क्या हो सकती है ।

सेठ जी ने सी०एस०टी०टी० के बारे में कुछ उल्लेख किया । मैं अधिक नहीं कहना चाहूंगा लेकिन साइन्स टर्मिनालोजी जो हमारी थी, हमको हर्ष है जिस उद्देश्य से वह बनाई गई थी उसका 90 प्रतिशत काम लगभग समाप्त हो चुका है और दस प्रतिशत काम बचा हुआ है और हमारे मंत्रालय ने सोचा है कि इसको भी हमको सेन्ट्रल हिन्दी डायरेक्टोरेट और सी०एस०टी०टी० को मिलाकर कुछ ऐसी रूपरेखा करनी होगी जिससे प्रैजन्ट दायरे में काम निहित हो सके । एप्वाइन्टमेन्ट का कोई सवाल उसमें नहीं उठता है ।

उपाध्यक्ष जी आप ने मुझे आदेश दिया है बैठने का, मैं उसकी अवहेलना नहीं कर सकता । एक, दो बातें और कहना चाहता हूं । उर्दू की कुछ बात आयी, हिन्दी के विकास की और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास की बात आयी है । मैंने यहां कई बार कहा है और पुनः दोहराना चाहता हूं कि कोई भी भारतीय भाषा पैसे के अभाव में बिलखने नहीं पायेगी । जितने पैसे की आवश्यकता भारतीय भाषाओं के विकास के लिए पड़ेगी. . . .

SHRI C. T. DHANDAPANI (Dharapuram): What is the allocation?

SHRI D. P. YADAV: Whatever you can spend. It depends on your capacity to spend.

SHRI C. T. DHANDAPANI: We wanted more funds for international studies. We have an istitute. We sent a proposal for Rs. 18 lakhs. But you turned it down; you sent back the proposal asking us to prepare another scheme.

श्री डी० पी० यादव : उपाध्यक्ष जी, हम सभी भारतीय भाषाओं को बराबर की दृष्टि से देखेंगे । तमिलनाडु में तमिल भाषा के विकास के लिए 1 करोड़ रु० का आबंटन किया गया है । और वही तेलगू के लिए भी किया गया है । अतः किसी भाषा के लिए ज्यादा करें और दूसरी के लिये कम करें. यह आरोप सही नहीं है ।

उपाध्यक्ष जी, कुछ लोगों ने बनारस हिन्दू यूनवर्सिटी की बात उठायी है, कुछ ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की बात उठायी है । माननीय शिक्षा मंत्री इस पर विस्तारपूर्वक विवेचन करेंगे, मैं सदन को सिर्फ़ यह जानकारी देना चाहता हूं कि कुछ अनअवायडेबिल सर्कम्सटांसेज के कारण आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बन्द कर देना पड़ा है कुछ समय के लिए । इस पर शिक्षा मंत्री जी अपने विचार विस्तारपूर्वक आप लोगों के सामने रखेंगे और बतायेंगे कि वस्तु स्थिति इस समय की क्या है ।

उपाध्यक्ष जी, मैं सोशल वैलफ़ेयर के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा और इतना आश्वासन देना चाहूंगा कि मिड डे मील, इंटेन्सिव चिल्ड्रन्स इंटेग्रेटेड प्रोग्राम और नरिशमेंट प्रोग्राम जो हमारा है तो पांचवीं योजना में न्यूट्रिशन पर हम करीब करीब, सभी को जब मिला देंगे तो, करीब पांच से 6 सौ करोड़ रुपये का आबंटन करने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि इस से कम सारी पौपुलेशन को तो कवर नहीं कर सकेंगे, लेकिन बहुत हद तक पौपुलेशन को कवर करेंगे ।

सैन्ट्रल सोशल वैलफ़ेयर बोर्ड की चर्चा की गयी है । अभी तक मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि सैन्ट्रल सोशल वैलफ़ेयर बोर्ड ने कोई

[श्री डी० पी० यादव]

गनाह नहीं किया है, हो सकता है कि कहीं मानवीय कमजोरी हो, लेकिन उसके कारण इस संस्था को एक दम तोड़ दिया जाय यह कहना उचित नहीं है। मैं इस दलील को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जहां तक डेस्टीट्यूट्स और ब्लाइन्ड बच्चों का सवाल है, यह पूछा गया कि हम क्या कर रहे हैं और आगे ऐसे लोगों के लिए हम क्या करना चाहते हैं। मुझे कहते हुए दुख होता है कि आज भारत में करीब 50 लाख के करीब लोग अंधे हैं, इतने लोग आंख के रोग से पीड़ित हैं। यह हमारे लिए एक चुनौती है। . . .

श्री कृष्ण चन्द्र पाडें (खलीलाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हर साल शिक्षा का बजट एक औसत पर रहता था। लेकिन जब हम शिक्षा नीति में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं तो ऐसे समय में शिक्षा का बजट कम क्यों हो गया है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, please. I do not understand it.

श्री डी० पी० यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह सच है कि चिल्ड्रन्स इंटेग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के मातहत हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ कोआर्डिनेट करके कुछ ऐसा उपाय किया जाय जिससे किसी बच्चे को न्यूट्रिशन के अभाव में यह अनुभव न करना पड़े कि वह जन्मान्ध हो जाय, या उसकी आंख खराब हो जाय। इस प्रकार के सोशल वेलफेयर वर्क्स पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भी हैं और हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा आश्वासन मैं देना चाहता हूं।

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash): I would not have taken part in the debate but for the senseless act of the Government this morning in closing down the Aligarh Muslim University.

Yesterday I was there in Aligarh Muslim University. The examinations were going on. If fact, last night, I witnessed a Mushaira also in the University Campus. There was no tension, no clash but this morning I was told and I was surprised to hear that the University has been closed down indefinitely.

This action of the authorities is not only undemocratic, it is atrocious. This Government and the Education Ministry want to spoil the academic career of the students. I do not know what the reason is. I want the Minister to explain why they have taken such an extreme step to close down the Aligarh Muslim University.

What is happening there? After all, it is a silent protest by the teaching staff and the students. There is no demonstration or agitation going on.

When the Aligarh Muslim University Bill was brought before this House in 1972, in the morning the Bill was sent to us, circulated the same morning and the Government wanted to introduce the Bill. We opposed it at the introduction stage itself. Even at that time was pointed out that this Bill would cause have on the students and the teaching staff, that we would have to consult all people concerned with the University and that you might take some time or refer it to the Select Committee, but it all fell on deaf ears. The Government refused to accept the suggestions and the Bill was rushed through and passed. Now, we are facing the consequences.

After all, the students and the staff of the Aligarh Muslim University want that the minority character of the University should be retained. It is the duty of the majority to safeguard the interests of the minority community, whether it be a linguistic minority or a racial minority or a religious minority. It is the duty, it is the bounden duty of the majority to safeguard their interests and the minorities should feel that they are safe and secure in the hands of the

majority. But, what the Government is doing is suppressing the rights of the minorities.

They say that they are implementing the Gajendragadkar Committee's report. I want to ask the Minister. When there are so many universities all over India, why have you picked up only the Aligarh Muslim University? Why have you not implemented it in other Universities? Why did you choose the Aligarh Muslim University as a sort of guinea pig for the experimentation of the Gajendragadkar Committee's report?

Not only the age-old concept of University autonomy is not being accepted by the Government but, on the other hand, they want to nominate to the Senate, the Governing Council and the Executive Council and pack them with their yes-men whether they belong to Prof. Nurul Hasan or the Government. We are afraid that most of them are going to be fallow-trvellers and persons against the Muslim theology. The Government must give an assurance that the University will be re-opened.

This morning I saw truck-loads of the UP Provincial Armed Constabulary standing near the campus. Hundreds of buses are standing there and the students are being asked to vacate their rooms. Notices have been put up this morning and about 3000-4000 students are asked to vacate the hostels and they are asked to board the buses to reach their destination. It is a most atrocious thing one can ever imagine in the country.

I want the Government to immediately rescind the order closing down the University and the University should be immediately re opened.

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली (टिहरी-गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

माननीय उपमंत्री, श्री यादव, ने इल्लिट्रेसी को दूर करने के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं । किन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ी विडम्बना है कि एक ओर तो पिछले दस वर्ष में शिक्षितों की संख्या में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, अर्थात् लिट्रेसी का प्रतिशत 24 प्रतिशत से बढ़ कर 29 प्रतिशत हो गया है, और दूसरी ओर इसी अवधि में देश में 9 करोड़ निरक्षर और बढ़ गये हैं । आज भी हमारे में देश में 80.54 प्रतिशत निरक्षर हैं और हमारे देश में निरक्षरों की जितनी संख्या है, वह विश्व भर की निरक्षर जनसंख्या का एक-तिहाई है ।

जहां तक स्त्रियों का सम्बन्ध है, पुरुषों की तुलना में निरक्षरता का उनका प्रतिशत बहुत अधिक है । स्त्रियां आज पुरुषों से 32 वर्ष पीछे हैं । इस देश में केवल 18.72 प्रतिशत स्त्रियां साक्षर हैं । जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, शिक्षा की दृष्टि से वह नैशनल ऐवेरेज से बहुत पीछे है । उत्तर प्रदेश में 21.77 प्रतिशत साक्षरता है और स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत केवल 10.70 प्रतिशत है । गांवों में साक्षर स्त्रियों की संख्या 7 प्रतिशत से भी कम है ।

15.00 hrs.

[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*]

एजूकेशन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में कांस्टीट्यूशनल डायरेक्टिव का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्राइमरी एजूकेशन को विशेष महत्व दिया गया है । मैं शिक्षा मंत्री को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि इस रिपोर्ट में चौथे फ़ाइव-यीअर प्लान के अन्त तक 90,000 अतिरिक्त अध्यापकों की भर्ती का उल्लेख किया गया है । इस योजना में पिछड़े हुए क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया जायेगा ।

मैं आपका ध्यान सब-हिमालयन बार्डर रिजन की समस्याओं की ओर खींचना चाहता हूं । यह क्षेत्र काश्मीर से लेकर नागालैंड और मेघालय तक फैला हुआ है । मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि दिल्ली

[श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली]

में बैठ कर पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एजूकेशन की जो योजनायें बनाई जाती हैं, वे वहां की स्थिति के अनुकूल नहीं होती हैं । उस क्षेत्र के हजारों प्राइमरी स्कूलों में ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, जिनको स्वच्छ पानी तक नहीं मिलता है । उन छोटेछोटे बच्चों को पहाड़ की चढ़ाई और उतराई पार करके चार पांच मील की दूरी पर स्कूल जाना पड़ता है । इस अवस्था में वे ठीक प्रकार से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं ।

पिछले दिनों मैं उत्तर प्रदेश के उत्तर काशी जिले के टूर पर गया था । वहां मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि अध्यापक महीने में केवल उस दिन स्कूल जाता है, जिस दिन उसको वेतन लेना होता है । वहां न अध्यापक और न विद्यार्थी स्कूल में जाते हैं । आज वस्तुस्थिति यह है कि विद्यार्थी नकल करके इम्तहान पास करता है, सिफ़ारिश से नौकरी पाता है । और रिश्वत से काम करता है । जब देश का यह हाल है, तो उसकी शिक्षा में उन्नति कैसे हो पायेगी ?

उत्तर प्रदेश में टिहरी–गढ़वाल पहले महाराजा के शासन में एक रियासत थी । विलीनीकरण की शर्तों के मुताबिक वहां के सब सरकारी कर्मचारी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी माने जाने चाहिए थे । विलीनीकरण की शर्तों के मुताबिक महाराजा को पेन्शन और अन्य सुविधायें तो सरकार ने दे दीं, किन्तु प्रान्तीय शासन ने 26 साल के बाद भी वहां के बेचारे अध्यापकों को अपने यहां नहीं लिया है । आज भी वे अधर में लटके हुए हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है और वे संघर्षरत हैं । मैं शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव डालें कि मर्जर एग्रीमेंट के मुताबिक राज्य सरकार उन अध्यापकों को अपनी सेवाओं में सम्मिलित करे ।

मंत्रालय की रिपोर्ट में पहाड़ी क्षेत्रों में मिड-डे मील्ज और न्यूट्रीशन प्रोग्राम का उल्लेख किया गया है । यदि आप स्वयं जाकर देखें, तो ज्ञात होगा कि यह योजना एक तरह से फ़ार्स है और उस में कोई वास्तविकता नहीं है । अठारह पैसे प्रति बच्चा न्यूट्रीशन के नाम पर दिया जाता है, किन्तु उतना भी उसको नहीं मिल पाता है । इस योजना के लिए काम करने वाले स्टाफ के लोगों का वेतन इतना कम होता है कि वे ठीक तरह से काम नहीं कर सकते । इसके अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट का खर्च और मैनेजेरियल खर्चा भी उसी में जोड़ दिया जाता है । इसलिए बच्चों को कुछ नहीं मिल पाता है । महंगाई बढ़ने की वजह से यह कुछ न करने के बराबर है । इसलिए यदि इस योजना को कार्यान्वित करना है, तो उसके लिए आवश्यक धनराशि दी जाये, और पूरी सुविधायें दी जायें, वर्ना इस काम को एक ढकोसलेबाजी का रूप न दिया जाये । यह कहना प्रवंचना मात्र होगा कि इस योजना से इतने प्रतिशत बच्चों को कवर कर दिया जायेगा । पहाड़ों में जिन बच्चों को दो वक्त खाना भी नहीं मिलता है, वे क्या पढ़ाई करेंगे । कुछ पाकेट्स ऐसे हैं, जहां मैलन्यूट्रीशन के कारण पचास प्रतिशत से अधिक बच्चे टी० बी० या दूसरी बीमारियों के शिकार हैं । उन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए उन्हें अच्छा भोजन देने की विशेष आवश्यकता है ।

आज हमारे देश में अंग्रेजी माध्यम से दी जाने वाली पब्लिक स्कूल एजूकेशन एक अभिशाप बनती जा रही है । अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा पाना और अंग्रेजी में बातें करना हमारा स्टेटस सिम्बल हो गया है । इससे सारे देश की जनता दो वर्गों में बंट गई है । एक तरफ़ सरकारी कर्मचारी और नेता आदि मुट्ठी भर गिनती के लोग हैं जिनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं । देश के बाकी लोगों के बच्चों के लिए ऐसे स्कूल हैं, जहां अध्यापकों को वेतन न समय पर मिलता है और न वह पर्याप्त होता है, जहां बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई ठीक व्यवस्था नहीं है । इस तरह सारा देश एक तरफ़ है और कुछ मुट्ठी भर

लोगों का एक अलग वर्ग बनता जा रहा है। इसकी रोक-थाम करने की आवश्यकता है।

मैं देश की एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ़ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसका सम्बन्ध शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय से भी है। उचित शिक्षा न होने के कारण हमारे देश में अनैतिकता बढ़ती चली जा रही है। किसी सदस्य ने अनैतिकता अथवा वेश्या-वृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया है। लाखों वेश्यायें हमारे देश के बड़े-बड़े शहरों में रहती हैं, किन्तु उससे अधिक संख्या क्लैडेस्टाइन प्रास्टीट्यूट्स की है। यूं तो दिल्ली और बम्बई जैसे बड़े शहरों में साफ़िस्टिकेटिड क्लासिज में यह एक फ़ैशन जैसा हो गया है, लेकिन वास्तव में यह समस्या सोशो-इकानोमिक ज्यादा है।

मैं इस सदन का ध्यान आदिवासी इलाकों की लड़कियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिनको बहुत पतित जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। देहरादून जिले के जोनसार–भावर, उत्तर काशी और टिहरी–गढ़वाल की कोलटा जाति की लड़कियां और मध्य प्रदेश की बेड़िया और कंजर जाति की लड़कियां इसकी शिकार हैं। कुछ समय पहले इस सदन में मध्य प्रदेश और बिहार की आदिवासी लड़कियों को बेचने और वेश्यालयों में रखे जाने की घटनाओं की चर्चा हुई थी। ये आदिवासी बहुत ग़रीब होते हैं और पीढ़ियों से ऋणग्रस्त रहते हैं। जोनसार–भावर में, जो देहरादून का हिस्सा है और जहां 61,000 की आबादी है, उन लोगों पर विभिन्न विभागों का पचास लाख रुपये से अधिक का कर्जा सरकारी खातों में दर्ज है। किसी के दादा या परदादा ने कर्जा लिया होगा, लेकिन वह अभी तक उसको नहीं चुका पाया है। केवल सूद देने के लिए ये लोग अपनी लड़कियों को बेचने पर बाध्य हो जाते हैं। वे लड़कियां आठ दस हाथों में गुजरने के बाद अन्त में वैश्यालयों में पहुंच जाती हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस समस्या के समाधान की ओर ध्यान न दिया गया, तो इससे वेनिरीयल डिजीजिज और क्राइम आदि कई अन्य समस्यायें पैदा होंगी। अगर यह समस्या हल हो गई, तो जो दूसरी बीमारियां इस के कारण पैदा होती हैं उनका स्वत: निराकरण हो जाएगा। मेरा निवेदन है कि वेश्या-वृत्ति निवारण की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सप्रेशन आफ़ इम्मारेल ट्रैफिक एक्ट किसी जमाने में बना था, लेकिन वह इतना पंगू और निष्क्रिय हो चुका है कि उसके आधीन कुछ काम नहीं हो पाता है। मैंने अभी सोशल एन्ड मारल हाईजीन एसोसिएशन के लोगों से बात की और उनसे पूछा कि कितनी लड़कियां ऐसी हैं, जो वेश्यालयों में भेजी जाती हैं। उन्होंने कहा कि इसके आंकड़े तो हमें मालूम नहीं हैं, लेकिन दिल्ली के जी० बी० रोड पर इतनी लड़कियां लोकेट की गई। मैं समझता हूं कि लड़कियों को लोकेट किए जाने के आंकड़ों से काम नहीं चल सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि जिन इलाकों में यह समस्या है, उन इलाकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए उचित कदम उठाए जायें। लेकिन इस काम को केवल सरकार नहीं कर सकेगी। यह वालेन्टरी आर्गनाइजेशन के करने का काम है।

एजेन्डा नोट्स फ़ार दी कान्फ्रेंस आफ़ स्टेट मिनिस्टर्ज, जो 23 जुलाई, 1972 को हुई थी, के पेज 46–47 पर जो उल्लेख किया गया है, मैं आशा करता हूं कि उसके अनुसार केन्द्रीय शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय राज्यों को मार्ग-निर्देश देगा कि वालेन्टरी आर्गनाइजेशन्ज के माध्यम से किसी प्रकार इसी काम को आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार उनको कंजूसी से पैसा देती है और उनको पर्याप्त साधन सुलभ नहीं होते हैं। वालेन्टरी आर्गनाइजेशन्ज में नौकरी करने वाले कार्यकर्ता किसी भी प्रकार उन लोगों से कम योग्य या कम सक्षम नहीं हैं, जो शासन के द्वारा वेतन पाते हैं। इसलिए वालेन्टरी आर्गनाइजेशन्ज के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए।

[श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली]

जहां तक आश्रम टाइप स्कूलों का और बालवाड़ियों का सम्बन्ध है, मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में उनका निरीक्षण किया है और मैंने यह पाया है —मुझे स्पष्ट बात कहने के लिए क्षमा करें—कि वालन्टेरी आर्गनाइजेशन्ज द्वारा संचालित आश्रम टाइप स्कूल और बालवाड़ियां कम सहायता मिलने पर भी शासन द्वारा चलाए जाने वाली संस्थाओं की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह चल रही हैं।

कुछ सदस्यों ने संकेत किया है कि चूंकि यह डिपार्टमेंट निकम्मा था, इसलिए वह होम मिनिस्ट्री को दे दिया गया। कुछ सदस्यों ने कहा कि इसको ठीक पैसा नहीं मिलता है और वह लैप्स हो जाता है। सही बात यह है कि इसी सदन में पिछले सत्र में माननीय सदस्यों ने यह मांग की थी कि प्रधान मन्त्री के पास गृह मन्त्रालय है, इसलिए इस विभाग को गृह मन्त्रालय को सौंप दिया जाए, तब इसका काम ज्यादा अच्छी तरह से हो सकेगा। इस सदन की मांग पर इस विभाग को गृह मन्त्रालय को सौंपा गया था। लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि जो पैसा इस काम के लिए स्वीकार किया जाता है, वह लैप्स हो जाता है। अव्वल तो कम पैसा मिलता है और जो मिलता है, वह लैप्स हो जाता है। स्टेट सब्जेक्ट होने के कारण यह पैसा राज्य सरकारों के माध्यम से खर्च होता है। अगर राज्य सरकारें इसका ठीक उपयोग नहीं करती हैं, तो केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग क्या करे?

इसके लिए मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि कोई न कोई इसका सोल्यूशन निकालें कि एक तो इसके लिए पैसा अधिक हो। आप दूसरे मन्त्रालयों से पैसा बटोर कर के इस काम के लिए ज्यादा प्रायमिकता के आधार पर दें और जो पैसा इसको मिलता है उसका पूरा-पूरा सदुपयोग हो। मैं अनुरोध करूंगा कि वालन्ट्री आर्गनाइजेशन्ज के माध्यम से इस काम को आप करना चाहेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि विशेषकर जो वीकर सेक्शन के हरिजन और आदिवासी लोग हैं या पिछड़े हुए इलाके के लोग हैं उनको ज्यादा सहायता आप करें।

अन्त में मैं एक शब्द अपने कांस्टीट्यूएन्सी के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं। टिहरी गढ़वाल में जो मेरा कांस्टीट्यूएन्सी है, साक्षरता देश में सब से कम है और सामाजिक विषमता बहुत अधिक है। वहां शिक्षा के लिए विशेष सहायता देने की आवश्यकता है। यह वर्ष स्वामी रामतीर्थ की सेंटिनरी का है। उनके नाम पर एक डिग्री कालेज वहां है जिसको स्नातकोत्तर कक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने का प्रावधान आपको करना चाहिए और वहां पर एक सेंट्रल स्कूल का प्रावधान भी आपको करना चाहिए।

श्री शिव कुमार शास्त्री (अलीगढ़): माननीय सभापति जी, स्वतन्त्रता के प्रारम्भिक काल से ही हमारे देश के मनीषी और विचारक यह अनुभव करते रहे हैं कि शिक्षा का यह ढांचा जो अंग्रेज ने अपने लाभ के लिए खड़ा किया था वह हमारे देश के विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। अंग्रेज की शिक्षा का उद्देश्य क्या था यह मकाले ने अपने एक पत्र में लिखा है जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं:

> 'to form a class who may be interpreters between us and the millions, whom we can call a class of persons Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions....'

इसके आगे कुछ और है। उसका कहना है कि हम इस प्रकार के लोग तैयार कर दें जो हमारे और जिन के ऊपर हमें शासन करना है उनके बीच में बिचौलिए

का काम करें। अंग्रेज केवल यह चाहते थे। उन्हें और किसी प्रकार का विकास हो हो या न हो इससे कोई मतलब नहीं था।

शिक्षा का उद्देश्य यह है कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो। शरीर का विकास हो, मन का विकास हो, और आत्मा का विकास हो। आज की शिक्षा के ढांचे में आप देखें तो ये चीजें कोई भी नहीं हैं। शरीर के विकास के लिए आवश्यक है कि उचित आहार हो। उसके साथ उचित व्यवहार और संयम का जीवन हो। आप देख लीजिए यह सारी की सारी चीजें आज उपेक्षित हैं। उसके बाद मानसिक उन्नति के लिए और आत्मिक उन्नति के लिये जो चीज हमारी शिक्षा में होनी चाहिए वह नहीं है। अगर केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा है तो आज वही हमारी सारी को सारी बुराइयों की जड़ है। रिश्वत खाने वाले बिना पढ़े लिखे नहीं हैं। बिना पढ़ा लिखा आदमी चार रोटी ज्यादा खा जाएगा तो बदहजमी हो जायेगी। पढ़े लिखे सीमेंट के सैकड़ों कट्टे और सैकड़ों मन तेल के पीपे पी जाए तो भी उनकी बदहजमी नहीं होगी। तो यह सारी की सारी बुराई पढ़े लिखे जो हैं उनके अन्दर है जिसके लिए कहा कि:

आदमियत और शय है इल्म है कुछ
और चीज।
लाद तोते को पढ़ाया पर वो हैवां
ही रहा॥

इसलिए मैं यह आग्रह करूंगा कि जो मानवता का उद्देश्य है वह उसमें आना चाहिए, इस प्रकार से इसमें परिवर्तन किया जाए। प्रधान मन्त्री जी ने और शिक्षा मन्त्री जी ने भी कुछ स्थानों पर अपने भाषण में यह चर्चा की है कि हम शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन कर रहे हैं। यह बड़े स्वागत योग्य बात है और यह बड़ी प्रशंसा की बात है। लेकिन इसके साथ-साथ जो विद्वानों की गोष्ठी एक इस प्रकार को होनी चाहिए जो पूर्व और पश्चिम की सारी बातों को देख कर उसमें परिवर्तन करे, उसकी कोई चर्चा मैंने नहीं सुनी। केवल एक अनुरोध मैं करना चाहता हूं कि आप शिक्षा में परिवर्तन के लिए जो एक तरफ को झुकते रहे हैं और अपने यहां नहीं देखते यह प्रवृत्ति दूषित है और यह पहले से चली आ रही है। मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि अपने प्राचीन आधार को शिक्षा बहुत अच्छी है। हमारे यहां आजकल समझा यह जाता है कि शिक्षा तब से प्रारम्भ होती है जबसे बच्चा स्कूल में जाता है। उससे पहले दो और शिक्षकों का जिक्र है और वह इससे अधिक महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले शिक्षक मां है और दूसरा शिक्षक पिता है। आजकल उनको शिक्षक की कोटि में गिना ही नहीं जाता। वह कितने महत्वपूर्ण शिक्षक हैं उनके लिए एक बात लिखी है कि :

उपाध्यायान् दशाचार्य, आचार्याणान्तु शत पिता।
सहस्रन्तु पितृणां मांता गौरवेणाति-रिच्यते॥

एक लाख साधारण अध्यापक जितना पढ़ा सकते हैं उतना अकेले माता की शिक्षा होती है। इसलिए जब आप परिवर्तन करें तो इन सब चीजों का ध्यान रखें और तब परिवर्तन की बात आए।

अब मैं थोड़े से सुझाव आपको देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि आपने शिक्षा मंत्रालय की ओर से गुरूकुल की शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए एक कमेटी बनाने का निश्चय किया है। यह बहुत अच्छी बात है। वह एक इस प्रकार की प्रणाली है जो आपकी प्रचीनता के चिह्न को दिखलाती है कि प्राचीन स्वरूप क्या था। इसके साथ-साथ जो चीज आप राष्ट्र के हित में रखना चाहते हैं वह उसके लिए एक आदर्श स्वरूप होगा। इसके लिए जितना शीघ्र कार्य हो सके उतना अच्छा है। वहां किसी प्रकार का अर्थाभाव न

[श्री शिव कुमार शास्त्री]

आए, किसी प्रकार से उसके विकास में बाधा न आए इस प्रकार का यत्न आप करें।

इसके साथ-साथ जो बात मैं हर डिबेट में कहता आ रहा हूं वह आज फिर दोहराता हूं कि आपके त्रिभाषा फार्मूले से और किसी का लाभ हुआ हो या न हुआ हो लेकिन संस्कृत की हानि अवश्य हो गई है और हमारे यहां आता है कि :

त्वयिवर्षतिजीमूत सर्वेपिल्लविता द्रुमा।

अस्माकन्त्वर्क वृक्षाणां पूर्वपत्रंच नश्यति ॥

जब वर्षा होती है तो चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। लेकिन आक के पत्ते बेचारे पीले पड़-पड़ कर गिरने लग जाते हैं। संस्कृत की आज वही दशा हो रही है। इस समय परिवर्तित परिस्थितियों में उसकी विशेष सहारे की आवश्यक्ता है। अगर उसे यह सहारा नहीं देंगे तो आपके भारत की वह प्राचीन विद्या नष्ट हो जाएगी।

अब अन्तिम बात जो मुझसे और आपसे सीधे सम्बन्ध रखती है उसकी तरफ आता हूं और वह है अलीगढ़ विश्वविद्यालय। पिछली बार जब उसका विधेयक प्रस्तुत हुआ था जो अब अधिनियम के रूप में है तो मैंने कुछ चीजों के आधार पर उसका विरोध किया था। लेकिन फिर भी जैसा आपने पास किया हमने सन्तोष इस बात पर किया कि कुछ लोग जो अधिकार किए हुए बैठे थे अपने फौलादी पन्जों में उस विद्यालय को कसे हुए बैठे थे, उनके पंजे ढीले होंगे। लेकिन अब मैंने सुना है कि अब फिर वही सारी की सारी शिथिलता आ रही है और उसमें आप कुछ परिवर्तन करने के लिए उद्यत हैं। कहावत वही हुई कि आगे क्यों बढ़ते हैं कि लड़ेंगे? कहा पीछे क्यों खिसक रहे हैं? कहा कि डर लग रहा है। जब आपने इतनी हिम्मत से एक काम किया था तो उसका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। इसलिए अलीगढ़ विश्वविद्यालय के विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए जो निश्चय किया था यदि वह ठीक है तो उसको क्रियान्वित कीजिए। इस समय जो राजनीतिक चालें वोटों को लक्ष्य में रखकर या और किसी प्रकार से चली जा रही हैं उनके सामने आपको झुकना नहीं चाहिए।

श्रीमती सहोदराबाई राय (सागर) : सभापति महोदय,.....

सभापति महोदय : आप बैठिए। देखिए, मेरे पास जो लिस्ट है वह आपके व्हिप की तरफ से आई है। मैं उसी को फालो कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि लिस्ट बड़ी लम्बी है। इस वजह से मैं ज्यादा समय लोगों को नहीं दूंगा। पांच से सात मिनट दूंगा चाहे इस साइड के हों या उस साइड के हों।

SHRI K. MALLANNA (Madhugiri): Sir, I support the demands for the Ministry of Education. While supporting them, I would like to give some suggestions with regard to educational policy. Why should we give education to our youth? Why should we spend crores of rupees over education? The Centre is spending so much of money. The States are spending crores of rupees over education. Is our educational approach fulfilling the aspirations of the people and of the youth? Are we taking into consideration the growing awareness among the youth, the students and the people with regard to the socio-economic and political justice?

Does our educational approach help in self-employment of youths and relieve the youth from office job seeking. What is the result.

Our education policy is as old as the British rule. Even after 25 years of independence our education system

is the same. So many changes have taken place. But our education policy maintains the *status quo*.

Under the present system of education, our educational institutions are producing students and youths only fit for office jobs. Our education system is like a big factory, which produces machine tools. Those tools are meant for only specific purpose; like that our educated young people fit only specific purpose, jobs in the offices. Now the outlook of the people is changed.

Among students and youths there is unrest, indiscipline etc. This is not only among the youths and students but also among teachers and parents. All this is due to our wrong educational approach.

There are vast differences with regard to managements of private and public schools, colleges and universities. In private schools the managements collect heavy tuition fees, contribution amount, earnest money etc., making huge profits. They have become actually commercial institutions. I need not say much about these things. The staff and teachers have no security and they are poorly remunerated. In public schools, colleges and universities, the staff and teachers are worrying about their grievances and studens are worrying about their rights and standard of education.

The unemployment is due to defective policy of education. Due to unemployment and under-employment, there is unrest among our youths. The youths of the country have surrendered all their zeal, and enthusiasm. Due to improper nourishment, they have lost their mental and physical strength. There is restlessness in the country. Occasionally we hear of disturbances among the youth, teachers and parents because of all these factors. All these lead to demoralisation in society. All these are due to our existing educational approach.

So we have to realise that our educational policy should be changed so as to rouse the awareness of the people with regard to socio-economic and political justice so as to make them take to self-employment and it should raise the standard of education.

Lastly we must think of the growing population and its menace to society. We must introduce population education so that our young generation should study the population situation, in family, community and the nation. We are spending crores of rupees on family planning over married people.

Our younger generation should know the situation as well in future. The object of population education should be to enable the students to understand that family size is controlable. The population limitation can facilitate the development of higher quality of life. The population education will also enable the students to appreciate the facts for preserving the health and welfare of the family, to ensure economic stability of the family and assure good prospects for younger generation.

Sex education is universally accepted in these days for the younger generation. So many countries are following it. I am concerned with sex-education only, so far as it relates to the objective population education. There should be no controversy or confusion. In our new policy of education the major components of sex-education with the Human physiology and reproduction, contraception, social interaction with human sexuality. Since our students are already studying biology, human reproduction, the new traits may also be introduced easily. It helps the students in developing a healthy outlook. Of course, this programme should be handled very carefully. We should study the needs of the community, its social norms and cultural backgrounds. It should be managed by competent people and proper evaluation should be done before extensive programme is under taken.

Unless we control our population and give its due place in our educational

[Shri K. Mallanna]

system, we will not be able to solve the multiple economic, social and political problems of our country.

In the light of these things, I feel that there must be change in the existing pattern of education and it must be implemented.

श्री हीरा लाल डोडा (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय, में अपने आपको सौभाग्यशाली समझता हूं कि आपने मुझे शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय की मांगों पर बोलने का मौका दिया है। शिक्षा मंत्री जी ने सन 1969 से 70 और 1972–73 के बीच की चतुर्थ योजना की अवधि के लिये पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये समाज-कल्याण विभाग की मार्फत जो कार्यक्रम चलाये गये तथा पिछड़े एवं गरीब बच्चों को दी गई छात्रवृत्तियों तथा शिक्षा विभाग द्वारा दी गई धनराशि का अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है। मैं 25 वर्ष पूर्व की तरफ नजर डालता हूं तो मुझे लगता है कि देश के अन्दर शिक्षा की प्रगति हुई है । उस समय के कालिजों, उस समय के प्राइमरी स्कूलों और आज के कालिजों और स्कूलों के स्तर में काफी फर्क पड़ा है । मगर देश के 80 प्रतिशत गांवों में बसने वाले गरीब वर्ग का स्थान वहीं का वहीं नजर आता है । आर्थिक स्थिति 25 वर्ष पूर्व से आज ज्यादा खराब है । उनके पास न जमीन और न कोई उद्योग धन्धा है । उस पिछड़े वर्ग तक आज न बिजली पहुंच पायी है और न दूसरे साधन पहुंच पाये हैं, जब कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा पिछड़े एवं गरीब वर्ग के लिये नई-नई योजनायें बनीं, करोड़ों रुपये के बजट बने और खर्च हो गये । उनके आंकड़े संसद के सामने आते हैं । मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस खर्च के अनुपात में शिडयूल्ड कास्टस और शिडयूल्ड ट्राइब्स की कितनी उन्नति हुई है।

मैं शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि 25 वर्षों के बाद गांवों में, पहाड़ों में, जंगलों में बसने वाले आदिवासियों की क्या स्थिति है ? बड़े बड़े शहरों में कालिज बन गये हैं, स्कूल बन गये, उन बच्चों के लिये पढ़ाई की व्यवस्था है, उनके लिये बैठने की सुविधा है, मगर गांवों और पहाड़ों के मध्य में रहने वाले आदिवासियों के बच्चों के लिये बैठने के साधन भी उपलब्ध नहीं हैं और न पक्के भवनों की व्यवस्था है । गांवों में जब स्कूल का भवन बनाने की बात आती है तो सरकार पहले ही कहना शुरू कर देती है कि गांव वाले स्कूल का भवन श्रमदान में बना कर दें, तब स्कूल खुलेगा । क्या यह गरीब वर्ग के साथ अन्याय नहीं है ...

सभापति महोदय : लिख कर लाने और पढ़ने की आदत अच्छी नहीं है । नोट्स बना कर लाय, उसको कन्सल्ट करना एलाउड है । हम देख रहे हैं कि आपके पूर्व वक्ता भी उसी तरह से लिख कर लाये और यहां पर पढ़ गये और आप भी पढ़ रहे हैं, यह पद्धति अच्छी नहीं है ।

श्री हीरा लाल डोडा : सभापति महोदय, मैं तो पहली दफा बोल रहा हूं, इसलिये तैयार करके लाया हूं । आप कृपा करके मुझे पढ़ने दीजिये ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या शहरों में बसने वाले गांवों में बसने वालों से ज्यादा निर्धन और गरीब हैं ? मैं गरीब और पिछड़े वर्गों की स्थिति सदन के सामने साफ साफ रखना चाहता हूं । आज हमारी सरकार पिछड़े वर्ग को उठाना चाहती है और उसके अनुरूप योजना बनाई जाती है मगर कार्य रूप में परिणत नहीं होती—इसके क्या कारण हैं ?

गांवों में प्राइमरी स्कूलों से लेकर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शालाओं के भवन निर्माण में काफी मुसीबत है । मैं उन पिछड़े एवं गरीब वर्ग में से आता हूं जहां आज खाने को रोटी मिलना दुर्लभ है, वहां स्कूल

भवन कैसे बन सकते हैं ? मैं अपने क्षेत्र का नक्शा आपके सामने रखना चाहता हूं । गांवों में मिडिल स्कूल खोले जा सकते हैं, उच्च माध्यमिक शालायें खोली जा सकती हैं, मगर भवन निर्माण गरीब वर्ग नहीं कर सकता । मैं अपने गांव में मेरे सामने गुजर रही कहानी आपको बताना चाहता हूं । सन 1953 में मैंने अपने गांव में बड़ी मुश्किल से मिडिल स्कूल खुलवाया । टूटा-फूटा भवन बनवाया लेकिन आज उसकी वही स्थिति है जो 1953 में थी । कारण यह है कि आदिवासियों की स्थिति खराब है । आज हम चाहते हैं कि गरीबों के बच्चों के लिये हाई स्कूल बनें मगर भवन की समस्या आगे बढ़ने से रोकती है । मैंने चारों तरफ अपने हाथ फैलाये, पैर मारे मगर अनाथ के हाथ खाली हैं । भवन कैसे बने यह स्थिति मेरे सामने है । तो गरीबों का भगवान मालिक है ।

इसी प्रकार डुंगरपुर जिले में कालेज होस्टल बन रहा है, उसका शिलान्यास राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने किया है मगर उसकी तरफ आज नजर उठा कर नहीं देखा जा रहा है । अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह मुसीबत मेरी नहीं है, यह मुसीबत देश की है । उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । पिछड़े एवं गरीब वर्ग के उत्थान हेतु, समाजवाद के सिद्धान्त को चरितार्थ करने हेतु सदन के सामने में कुछ मुख्य बातें रखना चाहता हूं जिस पर सदन गौर करे ।

शिक्षा देश में अनिवार्य कर दी जाये । शेडयूल्ड ट्राइब्स और शेडयूल्ड कास्ट छात्रों को स्कूली फीस से मुक्त किया जाये । हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में बसती है, वह गरीब वर्ग में आती है । अतः मेरी सरकार से प्रार्थना है कि पिछड़े वर्ग को उठाने हेतु, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये गांवों में भवन निर्माण, जैसा कि शहरों में होता है वैसी ही सरकार भवन निर्माण का कार्य अपने हाथ में लेकर बनावे ताकि हमारी नीति को सफलता मिले और गरीबों के बच्चे सुविधा से पढ़ सकें ।

कालेज होस्टल हर जगह खोले जाने चाहिये ताकि पिछड़े वर्ग के छात्र उनमें रहकर अपना अध्ययन कर सकें । पिछड़े इलाकों में जहां माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शालायें हैं वहां उन छात्रों के स्वास्थ्य को मद्दे-नजर रखते हुये डिस्पेंसरी होनी चाहिये । यह समाज कल्याण बजट बनाते समय योजना में अनिवार्य करना चाहिये—यह म मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं ।

अब समाज कल्याण की मार्फत जो पिछड़े वर्ग के होस्टल देश के विभिन्न भागों में चल रहे हैं उनकी तरफ मैं आना चाहता हूं । उन जंगलों एवं पहाड़ों में बसने वाले आदिवासियों के बच्चों को होस्टलों में भरती किया जाता है । सरकार के नियमानुसार समाज कल्याण की मार्फत उनके खाने पीने, कपड़े और किताबों का खर्च दिया जाता है । उन होस्टलों की व्यवस्था अस्त-व्यस्त चलती है । होस्टलों की देख रेख नहीं हो पाती है । रुपये का दुरुपयोग होता है । होस्टलों के मठाधीश अपने बंगले बनाते हैं और छात्रों को खाने के लिए पूरी रोटी नहीं देते हैं । इस लिए मैं यह कहने की स्थिति में हूं कि समाज कल्याण विभाग इसकी जांच करे : इसके साथ ही माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग की मार्फत या संस्थाओं की मार्फत चल रहे होस्टलों में जाएं और उन छात्रों की स्थिति को देख और उनकी मदद करें । मैं ने कई होस्टलों में जाकर देखा है कि 65–70 छात्रों के लिए एक किलोग्राम दाल ही दी जाती है । आटे की बात मैं क्या करू उनके दर्द को भगवान ही सुने ऐसी हालत है । उन होस्टलों में तमाम छात्रों की रोटी

[श्री हीरा लाल डोडा]

बनने के बाद बांटकर दी जाती है जो प्रति छात्र एक या डेढ़ रोटी हिस्से में आती है। अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि होस्टलों की जांच हेतु संसद सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाये ताकि वह जांच करके अपनी रिपोर्ट दे सके। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह एक वास्तविकता है। हमारी सरकार ने लाखों रुपये शिक्षा पर खर्च किए हैं मगर उसका सही ढंग से उपयोग नहीं हुआ है। बीच में दलाल अपना फायदा उठा रहे हैं।

पोषाहार कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में चल रहा है। पिछले वर्ग के बच्चों तथा माताओं को पौष्टिक आहार प्रदान किया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों में 24,600 केन्द्र खोले गए हैं जिनमें 32 लाख को लाभान्वित किया गया है। यह पोषाहार का कार्यक्रम शिक्षा विभाग के शिक्षकों की मार्फत किया जा रहा है। आज का शिक्षक देश का निर्माता है, वह देश का भविष्य बनाता है। मगर आज क्या हो रहा है? शिक्षक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और छात्र अपने सेक्शनों में मजे ले रहे हैं। मास्टर पोषाहार की गरम गरम पकौड़ियों में मस्त हैं—यह स्थिति है। वार्षिक परीक्षाओं में छात्रों को पास जरूर कर दिया जाता है मगर योग्यता के बारे में क्या कहा जाये? सभी समझते हैं कि आज का बी० ए० पास विद्यार्थी पुराने जमाने के पांचवीं पास का मुकाबला नहीं कर सकता है। यह आज की स्थिति है। शिक्षक वर्ग अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाते हैं मगर वेतन वृद्धि के लिए यूनियनें बनाई जाती हैं और हड़तालें की जाती हैं। पार्टियों का सहारा लिया जाता है और सरकार पर दबाव डाला जाता है तथा अपनी मांगों को मंजूर कराने में जोर शोर से ताकत लगाई जाती है। विरोधी दल के नेता उन शिक्षक वर्ग को उकसाने में लगे रहते हैं। ऐसी ही समस्या हरियाणा, काशी विश्वविद्यालय की हमारे सामने आई है जिस में छात्र संघ के अध्यक्ष श्री हरिकेश बहादुर ने अपने भाषण में स्पष्ट किया है।

हमारी सरकार ने शिक्षा के विषय में काफी तरक्की की है मगर फिर भी सुधार करने की गुंजायश है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे निम्न प्रश्नों का उत्तर संतोषजनक देने की कृपा करें।

देश में अनिवार्य शिक्षा का कानून लागू किया जाये। शेड्यूल्ड कास्ट तथा शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के छात्रों को स्कूल की फीस से मुक्त किया जाये। गांवों में स्कूल भवन निर्माण का कार्य सरकार अपने हाथ में ले। कालेज होस्टेल हर जगह खोले जायें। हर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शालाओं के पास डिस्पेन्सरी कायम की जायें ताकि छात्रों को सुविधा मिल सके। समाज कल्याण के होस्टलों की सारे देश में व्यवस्था करनी चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि मेरी मांगों पर शिक्षा मंत्री महोदय अपना उत्तर देते समय ध्यान रखेंगे।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (चांदनी चौक): सभापति महोदय, आज शिक्षा विभाग के मंत्रालय पर बहुत चर्चा हो रही है। हमारे एक साथी पाराशर साहब ने इसका जिक्र किया कि स्टेट सब्जेक्ट है या सेन्टर का सब्जेक्ट है, इस बात के झमेले में स्कूलों और यूनिवर्सिटियों की सारी शिक्षा की हालत बहुत खराब है। मैं तो यह कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने बड़े बड़े काम खराब किए, बहुत बड़े बड़े लोहे के कारखाने लगाये, इंजन बनाए और बहुत काम हैं जो अभी नहीं किए पर फिर भी ऐसा लगता है कि जो सबसे ज्यादा आवश्यक काम था वह था हमारे नवयुवकों को बनाना, बच्चों को बनाना, मेरा ख्याल है उस तरफ सरकार ने बहुत कम ध्यान दिया है और इसका मुझे बहुत अफसोस है। इस बात की सरकार को मुबारिकबाद है, मुझे ऐसा लगता है शायद पहली दफा कैबिनेट

को यह विभाग दिया गया है (व्यवधान) खैर यह बात हुई पर अभी भी मेरी राय है कि शिक्षा का सारा काम या तो केन्द्र को अपने हाथ में लेना चाहिए या ऐसा कोई कोआर्डिनेशन होना चाहिए जिससे कि अच्छी तरह से काम हो सके ।

बरसों हो गए हम लोगों को सुनते कि टेक्स्ट बुक्स को अच्छी तरह से सुधारा जा रहा है और उसमें जो नफरत की चीजें हैं, जो लोगों को अलग अलग करने की चीजें हैं वह उसमें से हटाई जा रही हैं पर अभी तक उसका कोई परिणाम हमारे सामने नहीं आया है । कई साल हुए एक कमेटी बैठी थी "सैयदीन कमेटी" उस कमेटी की रिपोर्ट हम लोगों को चुपके से तो देखने को मिल गई पर सरकारी तौर पर उस कमेटी की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई वह आज तक हमको मालूम नहीं है । मैं चाहती हूं मंत्री महोदय उस पर रोशनी डालेंगे । सैयदीन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में मैं एक बात साफ करना चाहती हूं कि उन दिनों में जो किताबों की शिकायत हुई थी वह किसी खास जमात की तरफ से हुई थी पर जहां तक शिकायतों का ताल्लुक है उससे कोई हिन्दु मुसलमान का ताल्लुक नहीं था, एक विचारधारा की बात है जोकि सभी को देखना चाहिए कि बच्चों को किस तरह से शिक्षा मिले ।

दूसरी बात यह है कि जो ऐसे हमारे स्कूल और कालेज हैं जो अभी भी प्राइवेट तौर पर चलते हैं वह ज्यादातर टीचिंग शटाप्स की तरह से हैं जहां पर व्यापार ज्यादा होता है और पढ़ाई की तरफ कम ध्यान दिया जाता है। मुझ को बहुत पहले एक स्कूल प्लस कालेज प्लस यूनिवर्सिटी और पता नहीं क्या क्या वह थी वहां पर प्रिंसिपल रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । वहां पर टीचर्स को जो तनख्वाह दी जाती थी, किसी को ज्यादा दी जाती थी कम की रसीद उससे ली जाती थी ताकि दूसरे लोग शिकायत न करें और किसी को कम दी जाती थी और उससे रसीद ज्यादा की ली जाती थी । इस तरह से कई किस्म का हेर फेर वहां पर होता था । जब मैं ने उस स्कूल प्लस कालेज प्लस यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दिया तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर ने मुझ से कहा आप अभी पढ़कर आई हैं और आप समझती हैं मैं खराब आदमी हूं । इस लिए आप जा रही हैं, और उन्होंने कहा कि आप ने दुनिया देखी नहीं है, अभी आप देखेंगी कि दुनिया में मुझसे भी ज्यादा खराब लोग हैं । सभापति महोदय , यह बात सच है कि प्राइवेट स्कूल और कालेजों का बहुत बुरा हाल है और उस की तरफ जरूर को ज्यादा ध्यान देना चाहिए । यह जो प्राइवेट स्कूल और कालेज हैं, चाहे किसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हों, उन की जो मैनेजिंग कमेटीज हैं, उन का अपना पढाई का क्या स्टैन्डर्ड है, इस का भी कोई सर्वे होना चाहिए । मुझे बलरामपुर के एक डिग्री कालेज का मालूम है, कि उस की मैनेजिन्ग कमेटी में चौथी और पांचवी जमात पास लोग भी नहीं हैं, जोकि पढे लिखे टीचर्स और प्रोफेसरों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं जो कि आने वालों के लिए बड़ा ह्यूमिलियेटिंग एक्सपीरियेंस होता है । वहां टीचर्स का प्रोवीडेंट फंड का रुपया गायब सब तरह के फंड गायब, और जब टीचर्स ने प्रधान मंत्री को मेमोरन्डम दिया कि इस की जांच हो तो जितने लोगों ने मेमोरंडम पर हस्ताक्षर किए थे सब डिसमिस हो गए, उन का आज तक पता नहीं है । कई दफा इस बार में गोरखपुर यूनिवर्सिटी को और चांसलर के पास दर्खास्त की गयी लेकिन आज तक उन की कोई तहकीकात नहीं हुई । हमने राजाओं से रियासत ले ली, और बहुत कारखाने ले लिये, लेकिन कालेजेज और स्कूल अभी तक उन लोगों के हाथ में छोड रखे हैं कि तुम चाहे जैसा बनाओ ।

सभापति जी, अभी एक वकालत आप ने सुनी जो बनारस में आर० एस० एस० कर रहीं है, उस की किस जोर से यहां पर वकालत की गयी और मंत्री महोदय तथा सरकार को किस तरह से धमकी दी गयी । किस तरह से

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

उन्होंने स्वीकार किया कि दो साल पहले हम ने कह दिया था कि इस वाइस-चांसलर को हटाओ नहीं तो यहां पर यह परिणाम होने वाला है। आप को यह मालूम हो जाना चाहिए कि कौन लोग हैं जो बनारस विश्वविद्यालय में इतना उधम मचा रहे हैं ? कौन लोग हैं जो वहां पर शाखाएं चला रहे हैं ? आज वहां की इमारत का मामला अदालत में पड़ा हुआ है। पर क्या यह मामला भी वहां अदालत में पड़ा है जो वहां पर 36 शाखायें चल रही हैं और उन को बन्द नहीं किया जाता मैं मंत्री महोदय से आज पूछना चाहती हूं कि बनारस यूनिवर्सिटी का हाल देखिये जहां 35 शाखायें चलती हैं, जहा पर हथियार, बल्लम, लाठियां, तलवार यूनिवर्सिटी के अन्दर चलती हैं, बम भी गिराये जाते हैं और बनाये जाते हैं। और सभापति महोदय मैं मंत्री महोदय का उसी बनारस शहर के दूसरे मोहल्लों का जिक्र करना चाहती हूं कि उसी बनारस में एक कानून पास नहीं हुआ तो कुछ लोगों ने काले पट्टे बांध लिये एक यूनिवर्सिटी के बारे में। एक यूनिवर्सिटी में बम चलाये जाते हैं, तलवारें रखी जाती हैं, लाठियां चलायी जाती हैं, कत्ल किये जाते हैं और वहां सरकार खामोश रहती है, और उसी शहर के मोहल्लों में अगर कोई यूनिवर्सिटी का कानून पसन्द नहीं आया वहां किसी ने काले पट्टे बांध लिये, आज वहां पर जो अत्याचार किया जा रहा है वह इतिहास में लिखी जाने वाली बात है। इस लिये मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि शिक्षा ऐसा मंत्रालय है जिस को सबसे पहले इस देश में यह साबित करना है कि इस देश में धर्म और भाषा के ऊपर कोई भेद नहीं किया जायेगा, और शिक्षा मन्त्रालय को पहले कदम उस तरफ उठाना चाहिए।

सभापति महोदय अलीगढ का कानून पास हुआ, अभी हमारे डप-मंत्री महोदय ने कहा कि अलीगढ यूनिवर्सिटी का जो कानून पास हुआ उस पर मंत्री महोदय रोशनी डालेंगे। इसके बारे में बहुत नहीं कहना चाहता हूं, एक ही बात कहना चाहती हूं, और यह कि दुनिया में कोई कानून सरकार का बनाया ऐसा नहीं होता जो कानून आवश्यकता पड़ने पर तबदील न किया जाये, उस को सुधारा न जाय। उस वक्त जब यह कानून पास हो रहा था उस के भी कई साल पहले से फिरकापरस्त लोगों ने और फिरकापरस्त जमातों ने इतना उधम मचा रखा है कि उस कानून को ठीक से सोचने समझने का मौका ही नहीं देते। उन फिरकापरस्तों की खिचातानी में अलीगढ कानून की जो ऐकेडेमिक साइड थी उस की तरफकम तवज्जह देने का मौका मिला। इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि कोई भी कानून हो, खासकर जो यूनिवर्सिटी से संबंधित है, जो पढ़ने पढ़ाने वालों से ताल्लुक रखता है, वह उन की समझ में आना ही चाहिये। चाहे हम कितने ही क्रान्तिकारी कदम उठायें डेमोक्रासी में हम को जनता को साथ ले कर चलना है और जनता को समझा कर साथ ले कर चलना है। इस लिए कभी कभी हमारे क्रान्तिकारी कदमों की गति धीमी हो जाती है। क्या सरकार के पास कोई ऐसा क्रान्तिकारी कदम समाजवाद की तरफ तेजी से चलने के लिये नहीं है ? सरकार इसीलिये धीमी हो जाती है कि उन को भारत के करोड़ों लोगों को समझाकर साथ ले चलना है इसलिये धीमे चलना पड़ता है। इसलिये फिरखापरस्ती का मुकाबला, कम्युनिलिज्म का मुकाबला अनडेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हो सकता है, उस को डेमोक्रेटिक तरीके से ही करना होगा। अलीगढ़ की ही बात नहीं, मैं तो यह कहूंगी कि मंत्री महोदय जितनी सेन्ट्रली ऐडमिनिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज हैं उन के ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यूनिवर्सिटीज से सम्बन्ध रखने वालों की, सब की राय लें, और कोई ऐसा नक्शा बनायें जो कि सब किस्म की सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज लग सके। ऐसा कोई इंतजाम करें और वह सब पर लगाने की कोशिश करें तो मैं समझती हूं कि ज्यादा फायदा होगा। और चलेगा।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे उप-मंत्री महोदय ने उर्दू का जिक्र किया। अब इस बारे में क्या कहा जाय? एक तो पहले ही उर्दू पढ़ाने के लिये किस्म किस्म की शर्तें हैं कि कितने विद्यार्थी हों तब उर्दू पढ़ाने की सहूलियत हो सकती है। अब विद्यार्थी कोई यूनियन तो बना कर आते नहीं हैं कि 20–25 एक साथ जायें। जब एक-एक जाते हैं तो अध्यापक कहता है कि तुम तो एक ही हो। जब दूसरा आता है तो वह भी एक ही आता है। तो उर्दू की क्लास शुरू नहीं हो पाती है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि जब आपने उर्दू पढ़ाने का ईमानदारी से फैसला कर लिया है तो यह शर्तें हटानी चाहिये ताकि सचमुच लोगों को पढ़ने का मौका मिले। साथ ही अगर उर्दू पढ़ानी है तो उर्दू की किताबें भी मिलनी चाहियें। दिया तले अंधेरा वाली बात दिल्ली में लागू होती है। यहां उर्दू की किताबें कई सालों से विद्यार्थियों को नहीं मिली। क्या फायदा आप की पौलिसी से? आप कहते हैं कि यह हमारी नीति है, आप कहते हैं कि संविधान में इस की व्यवस्था है, फिर भी अगर उस की उन्नति न हो और कोताही हो तो यह बात लोगों के दिल पर चोट करती है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि इन सब चीजों का इंतजाम करें और ऐजुकेशन को अपने हाथ में ले कर सही करें ताकि यह जो प्राइवेट टीचिंग शौप्स जगह वह जगह खुली हुई हैं इनको बन्द किया जा सके।

आखिर में एक बात और कहनी है और वह यह कि जो पब्लिक स्कूल खुले हैं और उनमें पढ़ाने में जो अन्तर है, सारे स्कूलों में, इस को बन्द होना चाहिये। मुझे मौका मिला एक गांव में जाने का जहां एक गांव के टीचर्स ने जमा होकर कहा कि हमारे बच्चों के लिये स्कूल खुलना चाहिये। मैंने कहा कि आपके पड़ोस में स्कूल हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोस में जिस स्कूल में हम पढ़ाते हैं हमारे बच्चे उस स्कूल में पढ़ नहीं सकते, उन को वहां पढ़ाना मना है उन्होंने कहा कि हम यहां उन बच्चों को पढ़ाते हैं, जिन के मां-बाप की बहुत आमदनी है, वे मोटरों पर चढ़ते हैं, उनके बच्चे मोटरों पर चढ़ते हैं इस स्कूल में उन बच्चों के बैठने के लिए कुर्सी-मेज है। उन्होंने कहा कि इस स्कूल में हमारे बच्चों को पढ़ाने की इजाजत नहीं है, हमारे बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ना पड़ता है, जहां बैठने के लिये टाट या चटाई भी नहीं है, डेस्क नहीं हैं।

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हमने आज नहीं तो कल, दस या बीस या सौ बरस बाद इस देश में समाजवाद लाना है। लेकिन अगर हमारे बच्चों की परवरिश, पढ़ाई और नौकरी पाने में इतना फर्क होगा, तो वह दिन कभी नहीं आयेगा, इस बात की मुझे चिन्ता है। इस लिये मैं चाहूंगी कि सब स्कूलों को फौरन एक जैसा बनाने की कोशिश की जाये।

SHRI SAMAR GUHA (Contai): I want to start with a leading question to the hon. Education Minister. How long should this process of mass production of unemployed degree-holders and that too, nowadays, spurious degree-holders, continue in the name of education? The educational system not only has become a junk but its objective has become absolutely obsolete. We are carrying the legacy of the imperialist days when some kind of degrees were given to the students to make clerks.

Now, the effect is terrible. You are creating aspirations in the minds of those unemployed having BA and MA degrees. They are not getting employment. Aspirations are high, yet no requisite qualifications nowadays. The result is tension, conflict and frustration,—the result is education is out of tune with the social life.

In West Bengal I just cite you one instance, just a week before, according to press reports, in the live register of the employment exchange are 14 lakhs degree-holding unemployed

[Shri Samar Guha]

youth-a mass production of the Universities and Colleges. If you take the total figure of the whole country, it will be a fantastic figure. This fantastic figure does not require any sociological research to understand as to how they are contributing to the instability of the country, how they are contributing to the tension, how they are contributing to the regional tension and how they are contributing to the political conflicts. Recently, you yourself said in the House that there are regional conflicts in Assam, Orissa and other parts where the students have taken prominent part. In Assam, it is mostly students who have taken part in these regional conflicts. Not only so, it indicates that the sons of the soil theory is vitiating the whole concept of our national integration and the sons of the soil theory is getting into the minds of those youngs, I say, those degree-holding unemployeds who have high aspirations. But there is a dangerous tendency of the erosion of the concept of national unity and national harmony. Regional concept is growing. I would say that the main reason of these tensions and conflicts, agitations, regional imbalances and the dangerous possibility of erosion of the whole basis of our national integration is this faulty system, this obsolete system of education.

I am extremely sorry to say that although there have been four Plans and we are just now going to the Fifth Plan, nevertheless it is strange, Sir, that in none of the Plans the importance of the education and its co-relation with the other aspects of planning has been mentioned. When we, the Opposition Leaders, had a discussion with the Planning Minister, he was mentioning about that, but, going through pages after pages, I do not find any integrated scheme or any idea of how to integrate the planning with education and without integration of planning with education, as I said, these problems of unemployment and consequent regional tension will wreck the whole future of the country.

Sir, I have a pet subject, you know, that I draw inspiration from where. Netaji Subhash Chandra Bose while drawing out the future outline of planning, in free India gave third priority to education. First, defence-centric industries, second, employment-centric agriculture and other jobs producing small scale industries, and third, education and then other things.

I want to draw the attention, of the Honble Minister Sir, that he should have the courage to take certain decisions. About that decision of educational courses i.e., 10 plus 2 plus 3 scheme. Out of this 10 plus 2, this 2 must not be either junior college or the intermediate college. This idea of intermediate college or junior college must be cast aside.

There must be rigorous admission of meritorious students and at the moment I would place this at 50 per cent although I would prefer 60 per cent,—but since at the present moment there are various difficulties I would place this at 50 per cent. If you can do it that would be better. What is absolutely necessary. I think, is that we should have professional oriented education,—I won't say job-oriented,—.If you give more emphasis on professional-oriented education, then, there is the possibility of creating a sense of purpose in the minds of our youth, of our students. Then you will be able to create a feeling of faith in themselves which will greatly help us in lessening the sociological imbalances and tensions developing outside.

Then with regard to the period of education of ten plus two years, in West Bengal, while they followed 11 years till now, they are now reverting to the 10 year period and they are devising junior college, intermediate college. They are only reverting back to the system which was there 15 years ago. There is utter confusion in the whole method of education, in the whole curriculum, in the system of education and there is no coordination, no homogeneity.

A conference of Education Ministers should be called to devise a system of uniformity upto the secondary and higher secondary stages. Let there be uniformity in the method of teaching, let there be proper system of examination and curriculum and let there be uniformity all over the country. There are varicus difficulties regarding admissions about which I cannot go into in detail at this stage as I have no time, but one thing I would say and that is, that this uniformity in the curriculum, in the method of teaching and also examination of the students is a must. Have higher education, university education, post-graduate edueation etc. only for the meritorious boys and for no other boys. Leave the rest to the professional type of education. Only then you will be able to tackle this problem.

Recently I had occasion to go through a few history books; particularly of the English-medium schools. These are produced by Macmillan, Orient Longmans etc. They are written by British authors. I am horrified to go through them and I wondered whether we are living in Victorian age or that of George V. These books make casual mention of Gandhiji. they don't devote enough attention to our freedom movement or on the important role played by Netaji, but about the visit of Queen Victoria, four or five pages are devoted.

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN): Would you be kind enough to let me have the names of some of those books.

SHRI SAMAR GUHA: Certainly, Sir, I will do it. I am telling you about these things because this leads to cultural erosion of our youth. Cultural synthesis of the country is based on proper study of our own national history. In many school boards of different States only 50 per cent marks in history is being introduced. With 50 per cent marks in history how can they understand the national culture? This is what I would particularly wish to stress for the attention of the hon Minister. They should take special care to see that proper history, not communal history, is being taught to our students—proper history having national perspective and the idea of national synthesis, at the formative, primary stage, so that the whole idea of national integration is stuck in their mind. You should have a few mobile exhibitions, particularly in the train, which may go all over the country and show some good films on national culture and national unity and the history of freedom. The audio-visual means of projecting national ideas into schools is very necessary. It is very dangerous that the concept of our national unity is getting eroded. It may lead to dangerous consequences.

16.00 hrs.

About Aligarh Muslim and Banaras Hindu universities I will say that you have done the original crime. You may have any theological university for the Muslims, Hindus and Christians but in the science course and the humanities course it is crime to have this concept of communal education. In the Bangla Desh constitution they have banned not only communal political parties but also denomination of any institution with communal or religious names. Have courage after the liberation of Bangla Desh and try to get out of this communal morass. Let there be theological university, if they want it, but not national university.

Now, a word about Dr. Sharimali. I should say the gentleman was Education Minister here. It is better if some friends advise him to quit. He has bungled and mismanaged and the whole nation is victim of it.

[Shri Samar Guha]

Lastly, about Dr. R. C. Majumdar. I have raised this question many a time in the past. He is 82 years old. He is doing great work of erudition and scholarship in history but you have not recognised him for national professorship. You have awarded national professorship to many. You have not honoured such an international scholar.

I want to ask one question whether in the Social Welfare Department the fund that was provided for war widows and destitute women—it is worth lakhs of rupees—has remained unspent. If it is so, why it is so? About the Children Welfare Policy Resolution, I would like to know how long it will continue to hybernate. There should be an integrated policy regarding Children Welfare Policy Resolution, National Children Board; services for children and youth in rural and urban areas and expansion of family and child welfare projects. How long would you take to integrate all these organisations? How long would you be in a state of uncertainity about the development of integrated policy in regard to children?

A word about Social Welfare Board. It mostly deals with women. As you are thinking of having a Children Welfare Board why not call the Social Welfare Board as Women Welfare Board and seek the help of really dedicated voluntary organisations for the same.

श्रीमती सहोदराबाई राय (सागर) : सभापति महोदय, आपकी निगाह बड़ी अच्छी रही जो आपने मुझे मौका दे दिया। मैं आपको धन्यवाद देती हूं और शिक्षा मंत्रालय की जो मांगे हैं उनका भी मैं समर्थन करती हूं। मैं अंग्रेजी राज्य में पैदा हुई थी। 1947 के बाद से मैं देख रही हूं, 1947 से पहले शिक्षा में इतनी उन्नती नहीं थी जितनी हमारे यहां सन् 1947 के बाद हुई है। क्योंकि पहले देहातों में न मिडिल स्कूल थे न हाई स्कूल थे और अब हरएक जगह प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल खुले हुए हैं। मैं अपने मध्य प्रदेश की बात करती हूं क्योंकि यह यू०पी० का झगड़ा तो बराबर बना ही रहता है, न जाने कौन ग्रह लगा हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश में बड़ी-बड़ी यूनीवर्सिटीज खुली हैं जैसे सागर यूनिवर्सिटी है, इन्दौर यूनिवर्सिटी, जबलपुर यूनिवर्सिटी है। मध्य प्रदेश में हर एक जगह आज यूनिवर्सिटी हैं। कोई झगड़ा नहीं है, न हमारे यहां के लड़के झगड़ा जानते हैं डिप्टी मिनिस्टर साहब यहां हैं मैं उन से कहूंगी कि आप मध्य प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा अनुदान दीजिए ताकि हमारे यहां की यूनिवर्सिटीज और स्कूलों में किसी प्रकार के झगड़े न हों और पढ़ाई ठीक से हो।

हमारे जो इतने लड़के और लड़कियां पढ़ कर निकलती हैं इन विद्यालयों से उनको कोई नौकरी नहीं मिलती और वे मारे-मारे फिरते हैं। तो ऐसी हालत में उनके लिए क्या कदम उठाने चाहिए यह आप सोचिए। जो एम० एल०ए० और एम०पी० उस क्षेत्र के होते हैं उन के यहां आकर वह दिन भर इक्ट्ठा होते हैं। कहां तक चाय पिलाएं और कहां तक गालियां सुने ? तो कैसे उनको नौकरी मिल सके इसके ऊपर सरकार सोचे। एक मेरा सुझाव है कि एक तो जो हाई स्कूल या मिडिल स्कूल हों वहां कृषि की शिक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि देहात के लड़के बहुत आते हैं। उनके लिये कृषि की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जो वह सीखें। नहीं तो हाई स्कूल या यूनीवर्सिटी से पढ़ कर निकलते हैं, नौकरी नहीं मिलती, घर जाते हैं तो खेती काम या घर का कोई काम वह करना नहीं चाहते। टेकनिकल स्कूल हों जहां लोहे का काम, बढ़ई का काम, लकड़ी का काम उन्हें अपने स्कूल में ही सिखाया जाये जिससे नौकरी न मिले तो अपने पैरों पर वह खड़े हो सकें।

जो थर्ड क्लास पास होने वाले लड़के होते हैं उनका तो कोई नाम ही नहीं लेता। उनके लिये कोई जगह कहीं नहीं होती। तो वह रात दिन

हम लोगों को कोसते हैं और गालियां देते हैं और शिक्षा मंत्री को भी गालियां देते हैं ऐसी स्थिति में उनके लिये कुछ काम दिलाने का उपाय सोचना चाहिये ।

हरिजन और आदिवासी लड़के जब शुरू से प्राथमिक पाठशाला में भर्ती होते हैं तो उन्हें उसी समय से वजीफा नहीं देते हैं । मेरा निवेदन है कि उन्हें शुरू से वजीफा और किताबें देनी चाहिये क्योंकि उनके माता-पिता की हालत बहुत खराब होती है । इस लिये वह उनको पढ़ाने से भी इनकार कर देते हैं । तो आप उनको शुरू से ही किताब और वजीफा दें । यह वजीफा जो देते हैं उसमें अगर लड़का पास नहीं हुआ तो साल भर के बाद उसका वजीफा बन्द कर देते हैं । ऐसा नहीं होना चाहिये । उनको यदि वह फेल हो जाते हैं तब भी वजीफा जरूर दीजिए जिससे कि वह आगे शिक्षा ग्रहण कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें । ऐसा नियम आप लागू करिए । दूसरे, जो वजीफा उनको देते हैं वह रुपये के बराबर है क्योंकि महंगाई का टाइम है ।

एक माननीय सदस्य : प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि इसको बढ़ाया जाय ।

श्रीमती सहोदराबाई राय : प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया है पर हर चीज तो इनके हाथ में है । तो इनको सोचना चाहिये कि जो 25 रुपया और 15 रुपया वजीफा हम देते हैं उसमें न तो लड़के के लिये चाय पानी का इंतजाम हो सकता है, न खाने का इंतजाम हो सकता है । तो 25 की जगह 50 रुपया और 15 की जगह 25 रुपया उसको दें जिसमें सही ढंग से वह पढ़ लिख सके ।

दूसरे, जो हमारे यहां अमेरिका का दलिया और तेल देते हैं वह इतना सड़ा हुआ है कि उससे दो चार बच्चे मर जाते होंगे । उस को बन्द कर देना चाहिये । सड़ा गला दलिया आता है अमेरिका का और वह इसलिये देते हैं कि आप मांगते हैं, वह समझते हैं कि हिन्दुस्तान के लोग भुखमरे हैं, दे दो उनको । तो ये आप बन्द करें । अपने यहां भी तो अच्छा गल्ला होता है । आप क्यों नहीं उसका दलिया बना कर देते ? आप क्यों नहीं अपने यहां का तेल देते ? क्यों नहीं इस स्वल्पाहार की व्यवस्था अपने यहां से करते ? आपको सोचना चाहिये कि अमेरिका का दलिया वर्षों का रखा हुआ है । वह जब लड़कों को देते हैं तो उनकी विद्या भी चली जाती है और वह मर भी जाते हैं । ऐसा अन्न खाने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती है ।

हरिजनों के छात्रावास जो आपने खोले है उस में बहुत भेदभाव है । एक तरफ आप कहते है कि छूआछूत दूर हो । तो ये छात्रावास अलग से नहीं होने चाहिए । सब का एक साथ होना चाहिए । सब एक साथ पढ़ें लिखें और सब एक साथ रहें । अलग से छात्रावास होता है तो वह कहते है यह हरिजन है, यह हरिजन है, इस प्रकार के दूसरे ठाकुर, बाम्हन के लड़के जो होते है वह इनके साथ छूआछूत बरतते हैं । अगर ठाकुर, बाम्हन के लड़के और हरिजन लड़कें एक साथ पढ़ेंगे तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी के अन्दर छूआछूत नहीं रहेगा । क्योंकि हम जो पुराने आदमी हैं वह छूआछूत ज्यादा मानते हैं । अगर पुरुष छूआछूत को नहीं मानता है और किसी चमार के घर हो कर आये तो घर की स्त्री कहती है कि तुम चमार के यहां हो कर आये हो, घर की रोटी मत छूओ । यह भेद कैसे दूर होगा? जब तक हमारी एजूकेशन से भेद नहीं हटेगा, तब तक शिक्षा नहीं बढ़ सकती ।

पहले मौलाना आजाद शिक्षा मंत्री थे अब आप इस पद पर आये हैं – मंत्री महोदय अभी यहां बैठे थे, पता नहीं क्यों चले गये, उनको मेरी बातें सुननी चाहियें – उनका मुखारबिन्द भी हंसता है और नाम भी हंसना है, हंस कर बात निकाल देते हैं । आपको बड़े कदम उठाने चाहियें, अगर आप हंसते-हंसते समय निकाल देंगे तो काम

[श्रीमती सहोदराबाई राय]

नहीं होगा, शिक्षा की उन्नति नहीं हो सकेगी इसलिए मैं उनसे निवेदन करती हूं कि आप सख्त कदम उठायें । जब मौलाना आजाद मिनिस्टर थे, तब कोई गड़बड़ी नहीं होती थी, लेकिन आपको न जाने कौन सा ग्रह लग गया है, जब से आप आये हैं शिक्षा के क्षेत्र में दंगे होने लगे हैं । कहीं हरियाना में हो रहे हैं, कहीं पंजाब में हो रहे हैं, दूसरी जगहों पर हो रहे हैं – इस तरह से काम नहीं चलेगा, आप सख्ती से कदम उठायें ।

हमारे लड़कों को जो वजीफा मिलता है, यह बहुत थोड़ा है, उसमें उनका गुजारा नहीं होता है । उसे बढ़ाना चाहिए । आप न जाने क्यों डरते हैं, शायद मुसलमान होने के नाते डरते हैं, कहीं हमसे कोई नाराज न हो जाये । इस में हिन्दू और मुसलमान का सवाल नहीं है, आप जी करें वह ठीक होना चाहिए ।

मध्य प्रदेश में कई उर्दू के स्कूल हैं – वहां के बच्चे कहते हैं, मौसी तुम वहां जाती हो, शिक्षा मंत्री जी से कहो – हमारे पास किताबें नहीं हैं, पैसा नहीं मिलता है, मौलवी या मुल्ला नहीं हैं, हम कैसे पढ़ेंगे ? आप उनके लिए कदम क्यों नहीं उठाते हैं । देश की संस्कृति में उर्दू, अंग्रेजी, हिन्दी सब के लिए मान है । इस लिए मैं कहना चाहती हूं कि हमारे जो आदिवासी इलाके हैं उनको ठीक प्रकार से शिक्षा नहीं मिलती है और इसलिए वे ईसाई हो जाते हैं । क्यों हो जाते हैं ? इसलिए कि न उनको पैसा मिलता है, न कपड़ा है, न उनके पास साधन हैं, न घर हैं । इसलिए यदि हमको धर्म को बचाना है—किसी भी धर्म के साथ जबरदस्ती नहीं होना चाहिए—तो उनको सुविधायें दीजिए, किताबें दीजिए, कपड़ा दीजिये, खाना दीजिए, तब वे कभी ईसाई नहीं होंगे ।

हमारी महिलायें मुसलमान या ईसाई हो जाती हैं—क्यों हो जाती हैं । अगर कोई विधवा स्त्री है तो न उसको मायके वाले रखते हैं और न सुसराल वाले रखते हैं वह कहां जाय । इसलिये दूसरे धर्मों में चली जाती है । अगर आप उस को सोशल वैलफेयर में जगह दें, ग्राम-सेविका में रखें, जहां भी जगह हो, उस को लें तो उससे उसका धर्म बच जायेगा ।

सभापति जी, मैं आप को धन्यवाद देता हूं, आखिर आपने मुझे समय दिया, लेकिन आपको काले और गोरे सब को देखना चाहिये .....(व्यवधान)... । अब चुनाव के तीन साल रह गये हैं, इस लिये शिक्षा की उन्नति कीजिये । इस कर मत टालिए, कदम उठाइये ।

*SHRI SAKTI KUMAR SARKAR (Joynagar): Mr. Chairman, Sir, in keeping with the saying 'let hundreds of flowers blosom' I feel that we should speak in all the languages for the development of our culture. Due importance should be given to all the languages. The hon. Deputy Minister has spoken a short while ago in Hindi, Hence I think that I should speak in Bengali too. Sir, while rising to support the demands of the Ministry of Education, I will like to confine my views on a few points only, because at the fag end of the day, I do not think there is much scope left for delivering a speech. The important issues that I would like to place before you has already been covered to some extent by the Deputy Minister in his reply, but I feel that his reply to those points was incomplete. Sir, in yesterday's newspaper as well as in today's newspaper I have seen that the Delhi University authorities are contemplating what steps they would take against 'mass copying'. This problem is not confined to Delhi University alone. Today this problem is being faced by all the Universitiies all over the country. Sir, I am the Principal of an higher Institute and am asso-

*The Original speech was delivered in Bengali

ciated with two colleges. I am also on the Governing Body of four higher Secondary schools. From my personal experience of running educational institutions, I can say that the present day education system, instead of creating a healthy and creative atmosphere in our national life has only helped to create an explosive atmosphere. Now how to prevent this explosion, that is the problem before us. From the discussion held in this House and from the Deputy Minister's reply I found that efforts are being made to contain this student and youth unrest through the opening of a hundred Nehru Centres. But, Sir, we would have to dig deep to locate the root cause of all this unrest. Unless the cause of a disease is diagnosed, how can the treatment be prescribed? One reason for this discontent and unrest is generally said to be the lack of job opportunities to the educated youth and that is why the student unrest today has assumed this staggering proportion. It has been said that today we need expertise in every field and general education is being criticised. We are told to produce scientific and technically educated persons, more of engineers and technocrats. I do not know how much logic is behind such arguments. If that was true, how is it that there are thousands of jobless engineers in our country today. Does it not follow that the system of education which we have built in our country is basically defective? I have failed to find what measures have been taken till this day to remove those defects from our system of education. Sir, it is a matter of great regret that illiteracy is ever increasing in the country. If we fail to realise that darkness, instead of receding, is constantly on the increase, then all our efforts will be in vain and the grand edifice that we are dreaming to build through our Five year plans will collapse and crumble in the dust.

Sir, it is a matter of regret that even the renowned professor Dr. Gridal Midal has said that in our country about one-third of the total expenditure on education is spent on higher education alone. Next comes secondary education and lastly comes primary education. So we see that primary education is not given due importance. We have failed to make primary education compulsory till this day, although we have professed in our Constitution to make primary education compulsory within 10 years. What happened to that assurance? Sir, 25 years have already elapsed since our independence but we are nowhere near the fulfilment of our promises and I am doubtful whether we will be able to fulfil them in another 25 years. Therefore we will all have to make sincere efforts to banish illiteracy from this land and this should be given topmost priority. By illiteracy of course I do not mean just the 3 R's. Imparting knowledge of the 3 R's alone will not mean removal of illiteracy. Our hon. President Shri V. V. Giri perhaps had said sometime back that the concept of the 3 R's should now be replaced by the 3 F's. We should place due stress, I think, on the functional 3 F's now. Sir, I want to place only one more question about higher secondary education. One fine morning we suddenly saw that the higher secondary system is being abolished. The eleventh class is being abolished and replaced by the earlier ten class course. At least this system has been already introduced in West Bengal. No wonder this whimsical action will create an disillusion in the field of education. Today we are having a system upto 10th class only, tomorrow it is replaced by eleven classes and the day after a 12th class system is introduced. What is all this? Certainly this uncertainty in the education system is not congenial to the healthy growth of education. Sir, I am myself a teacher. I run educational institutions and on the basis of my personal knowledge and experience I can say that this chaos in the field of education canot be allow-

[Shri Sakti Kumar Sarkar]

ed to continue. Therefore we will have to consider here and now how a permanent education system can be evolved. If we are to save education from this suffocating atmosphere, from this explosive atmosphere then we will also have to pay attention to the condition of the teachers. Why are the teachers forced to come down on the streets today like trade unions. Education can never flourish and prosper in a country where the teachers come down on the streets like trade unions. Therefore we will have to see that the teachers are not forced to behave like the trade unions. I will therefore implore that whenever the teachers have any grievance and whenever they put forth any demands, those should be considered forthwith and satisfactory solutions must be found.

Another thing I will mention Sir, and that is about the examination system in our country. The present examination system needs complete overhaul. Unless the examination system is overhauled completely, we will not be able to bring real education to the people even if we establish thousands of universities. Education creates and develops the creative mentality in a person for building the nation. Due to the defective education and examination system that creative mentality is being turned into an explosive mentality. Unless this is checked in time, we will have to pay a high price for this. Sir, I will like to draw your attention to one more thing and that is about the education system in West Bengal. As you know, in many States, education has been made free for the students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, upto the Higher Secondary standard. But Sir, in West Bengal this concession is being delibrately denied to the Scheduled Caste students. I do not know whether this is due to the paucity of funds. If it is, I will request the hon. Minister of Education with folded hands to provide the necessary funds to the West Bengal Government so that education may be made free for the Scheduled Caste students in West Bengal atleast upto the secondary stage. Sir, I once again support the demands of the Ministry and with that Sir, I conclude my speech.

MR. CHAIRMAN: Shri H. M. Patel.

SHRI H. M. PATEL (Dhandhuka): Mr. Chairman, Sir, I must begin by congratulating the last two speakers. My own regret is that the last speaker did not speak in English. But, they certainly said great many home truths in a very straightforward and fortright language.

My request to the Minister for Education would be this. He might consider presenting his report in a somewhat different manner. I would have expected his report to tell me something about what, he thinks, he has achieved in the course of a year in respect of educational achievements as against the targets and objectives that he might have set for himself. For instance, when he talks of higher education, there is no mention about Kothari Commission report. That report was submitted six years ago. I think that one would have reasonably expected him to say how much of it, how many of their recommendations have been implemented or rejected and how many of them are under consideration. And what is the situation in regard to the Kothari Commission Report? Is it that that Commission was appointed only in order that his Report should be kept in a pigeon-hole or was there some other objective behind it. We should really do something to our education. Before Independence, we used to keep on saying that our educational system was bad; it was only designed to make Clerks and so and so forth. One, therefore, rightly expected that after Independence, there would be radical change in the system. That seemed to be the intention why several very learned Com-

missions had been appointed. They submitted their reports. But, it seems to me that we have continued with the same system without any significant change in it—whether it be the higher education, secondary education or anything else.

In regard to Secondary education, we are still talking about 10+2+3. The Report refers to a Committee of Chief Ministers and it says that they have now accepted the 10+2 formula. Education Ministry hopes that they will come forward and implement it with some degree of expedition.

What grounds does the minister have for expecting that they will really implement this decision with any degree of speed? I have grave doubts. I am sure he realises that the implications of this particular decision, however good and desirable it may be, are that it will mean very considerable financial burdens upon the State Governments and many State Governments may well hesitate to go forward with it, unless the Central Government is going to come to their assistance. As my friend Mr. Samar Guha said, already in Bengal they are thinking of junior and intermediate colleges. That is the direction in which certain other States are also thinking purely for financial reasons and not for educational reasons, because it will be almost impossible for the existing secondary schools to provide the facilities necessary for the 11th class requirements.

When I said the report is not presented in the way in which it should be, I had only this in mind that I would have expected the report really to tell us much more about the achievements towards the policy objectives that the ministry has set for itself. Only then can we be in a position to applaud its achievements or deride it for failure to achieve those objectives. I find it very difficult indeed to understand, for instance, what is the attitude and approach of the ministry is regard to primary education. It says, as required in the Constitution's directive compulsory primary education is our objective. But how will you achieve it? If you look at the primary schools in almost any States, a vast majority of them scarcely deserve the name of a school. More often than not, one teacher is required to teach more than one class. What kind of education are we seeking to impart through these schools? Is it not generally conceded that primary education is the very foundation of education? Should these primary schools, therefore, not be established so that they are much more satisfactory? Should the number of teachers provided not be adequate? Should they also not be of a calibre that would enable them to impart the kind of teaching that should be imparted at that stage?

You would say, it is not the Central Government's responsibility. Undoubtedly, education is one of these subjects in regard to which all the criticisms made in this House today could be answered by the minister by one simple remark that much of this is the responsibility of the State Governments and I am not answerable for it. But why should you not make yourself answerable for it? If you cannot make yourself answerable for it, it seems to me that we might as well forget that we shall ever achieve any real progress in education in this country. There has to be a certain degree of central directon in the matter of education at all levels. Therefore, I have often felt and I am quite convinced that education should be made a concurrent subject. It is about time this was given serious consideration because unless that is done, it seems to me that the Ministry of Education will not be able to ensure, even if it were so minded and most earnest, that the State Governments carry out and implement the most desirable of the objectives in the manner in which they should be implemented.

[Shri H. M. Patel]

I would only refer to one further point, and that is with regard to National Social Service, National Sports' Organisation and the NCC. These three are very important for our young students, young men and women. Now two organisations are looking after them. While the Defence Ministry looks after the NCC the National Social Service and the National Sports' Organisation come under the Ministry of Education. In the same campus you have two separate organisations and quite often it leads to unhealthy competition. It would be far better if the three organisations were run in a co-ordinated manner and, if possible, run under one organisation, under one supervision. This, I think, is a suggestion which merits serious consideration.

SHRI RAJA RAM SHASTRI (Varanasi): Sir, I too want to join hands with those who want a complete revolution in our education system. No doubt, the whole system has completely collapsed. Beginning from the examination system, the whole scheme of studies and education has gone down from stage to stage and something radical needs to be done. From this point of view, I do not think we have a ready-made scheme to replace the existing one. We can only suggest that a study be made by competent people, particulaly of those countries which have developed education of their own, independently, like China, Russia, Germany, Japan and Iran. We should not model our system, as we have been doing so long, only on the Western countries, big countries like America and England. We should look to other places where they have had to face conditions and situations similar to ours in modern times. I think some such study should be undertaken. Whether it is made by a committee or otherwise it is for the Ministry to decide.

Then, I have complaints regarding non-implementation. For instance, last year a very beautiful scheme was formulated by the Education Minister in which he tried, and I think successfully so far as the scheme went, to reconcile our limited resources to our recruitment policy. His principle was that if we cannot admit everybody, we should admit only those who are selected on the basis of talent, rather than on the basis of the fact that they can pay for their education. The deficiency of payment can be made up by liberal scholarships. This was a very good scheme, a very beautiful scheme, which went towards providing equal opportunities and usher in socialism. We heard about this scheme last year. Till this year we have seen nothing of implementation on those lines. We have been doing something on these lines during the recent past too, but that is not the point. The point is that since the Education Minister formulated the scheme, nothing has been done further.

I will limit myself to that aspect of education which has relevance to national integration. I think education is the most important field of integration. It is here that the intellectual integration is first made, which is later carried out into practice. Our troubles in the field of national integration began not recently but as early as in ancient India. It is then that we separated our three religions Hinduism, Jainism and Buddhism into different lines and relegated them to three languages, that is, Sanskrit for Hinduism, Prakrit for Jainism and Pali for Buddhism. This was a sort of disintegration that we were working for in those early classical days.

Now, we know the results. The Education Minister being a great historian knows how we have lost by the trifurcation of these systems. Many progressive elements which would have held our country in good stead have been lost to us. Many opportunities of progress have been lost to us because of antiquated ideas dominating the field because they had no challenge from any other stream. The streams were three but we divi-

ded into separate channels. We shut our eyes to each other and rather became hostile to each other.

It is very necessary, I feel, that at least one institute in Delhi on a very high level should be established where the study of Sanskrit, Pali and Prakrit, that is, the study of Hinduism, Buddhism and Jainism could be made together, not only together in the sense of being within the same walls but in a very integrated way. This is the point.

Now, coming to recent days, we know there is a lot of talk about majority character of education and minority character of education. This is again a process of disintegration. From this, the feeling comes that our educational system has not been thoroughly secularised. Otherwise, there is no relevance in the cries of majority character of education and minority character of education. These questions begin only when we are not working on a firm secular base in our education. I think, a study should be made either through a Committee or otherwise as the Ministry thinks fit as to how to secularise our education completely so that these questions do not arise.

Coming to the Banaras University, in this context, I would say, the Banaras University is in a very difficult situation. I, coming from Banaras itself, know the intricacies of the problem. It is no use running down one side or another. So long as we do not approach the fundamentals of our educational policy, we should give all support, complete support, to the Vice-Chancellor because the Vice-Chancellor is a secular man, a thoroughly good man and a very competent man. Give all the powers to him. It would help, I think, if some Parliamentary Committee is sent to Banaras to help the Vice-Chancellor in his understanding and in his execution of the policies there and also to inform this august House about the true state of affairs there.

Another field of national integration is the emontional field, that is, the cultural field. As this Ministry also covers the field of culture, I would point out only one flaw in its working so far as culture is concerned. The Education Minister is a great historian and he knows that in the field of art, whenever some alien people, foreigners, settled down in our country, they brought their own style of art to this country and tried to integrate their art with the art of this country. In several stages, not all at once, they succeded completely in producing new beautiful forms which really added the beauty of one form to the other.

This is the way how a composite culture develops. It is not by keeping ourselves in separate compartments, not by keeping our creations in separate varieties. We are talking of varieties all the time. Some of these varieties are so obnoxious and so offensive that they better go. But the fact is that we tolerate all those varieties under the assumption that there is underlying these a very beautiful unity. But looking closely at the point of unity, we hardly discover any unity except in the geographical sense.....

AN HON. MEMBER: Hippy culture.

SHRI RAJA RAM SHASTRI: This is all Hippy culture. This is all a museum sort of unity. I do not find any unity. Unity should rather develop in the field of emotions, in the field of art, in the field of education, in the field of work, in the field of action. Calling oneself by separate caste names, wearing separate types of turbans, eating separate types of food, observing separate types of days, all these varieties do not help in creating the beauty of unity. Unity should be free from these disunities. This unity can be developed in a deliberate way, if our academies and our cultural councils take the problem in right earnest.

[Shri Raja Rav Shastri]

The last field of national integration is social welfare. It is in social welfare that you put your integarl theories into practice. In social integration, there is the question of social justice. Without social justice, there cannot be practical integration. Emotional integration, you get culture; intellectual integration, you get education, but without bringing this feeling of integration and the idea of integration, into practice in the social field, you cannot be really integrating the various divisive forces in the country. There should be the assurance of social justice. Social justice is a big thing. Social welfare is only the first step to social justice. Social justice has many forms, developed forms, but social welfare is just the first step, the very beginning of social justice. Unless this is looked after it is very difficult to say that we are an integrated people. If a person has no security against starvation, if he feels utterly lost in old age or when unemployed, he is absolutely reduced to a street beggar; in these conditions how can he feel and accept his responsibility in the development and growth of the country? There is a complaint against the common man, that he does not cooperate in implementing the plan. How can the common man cooperate when he is suffering from these disabilities? So, I would insist that social security must be taken in hand by the Ministry in right earnest. A committee should be constituted to go into the whole matter, and some scheme should be evolved. I do not say that there should be, immediately, a scheme like the Beveridge Plan in England, but something according to our own conditions, according to our resources. After studying the social security schemes in other countries, big and small, we should be able to come to something which gives us some security, at least so far as the resources permit.

These are the points I wanted to make.

MR. CHAIRMAN: Shrimati Savitri Shyam.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: (Diamond Harbour): Sir, when the Demands for Grants of the Education Ministry are being discussed here, we are alarmed to hear that the Aligarh Muslim University has been closed down this noon for an indefinite period. It is a very serious matter because that institution has a character of its own, the minority culture is deeply involved. We want the Government to give us a statement right now. It is a very serious matter. They cannot impart education, but they are shutting down Universities often universities of this type of character.

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT (Kozhikode): Actually, at Aligarh Muslim University, there was no incident, no tension, nothing of that sort. It is a shameful thing that it has been closed down..... (*interruptions*).

MR. CHAIRMAN: This matter was raised before—I am told. The Minister has not made any statement. He may make, but just now we cannot compel the Minister to make a statement when he has nothing ..... (*Interruptions*) There is a compulsion of discipline also. That, of course; we have to compel.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: We take it that the Minister declines to give a statement. You have been good enough not to apply compulsion. We appreciate that. *Suo motu* should be not make a statement? The House is concerned and agitated over this.

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN): My distinguished friend, as usual, is absent for most of the time from the House and then raises a problem. My collegue, the Deputy Minister, gave this information to the House and also stated that in the winding up reply,

I shall be dealing with this question at some length. This he has already said.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I am glad to hear that, but your remarks, perhaps, are not quite kind.

श्रीमती सावित्री श्याम (आंवला) : सभापति महोदय, आप ने मुझे समय दिया इसके लिए आप को हार्दिक धन्यावाद ।

इस से पहले कि मैं शिक्षा मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर अपने कुछ विचार प्रकट करूं, मैं सब से पहले प्रो० नूरूल हसन साहब को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि वह आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं जिन के मुंह से यह बात निकली कि हिन्दुस्तान की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन होना चाहिए । हम महसूस करते हैं कि जब से हम आजाद हुए हैं, हमारी शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । इस में कोई सन्देह नहीं कि बड़ोतरी हुई है– हर तरफ बड़ोतरी हुई है, स्कूलों की संख्या में, शिक्षकों की संख्या में, पढ़ने वालों की संख्या में, लेकिन एक स्वतंत्र देश में जिस प्रकार की शिक्षा होती है, उस के अनुरुप हिन्दुस्तान की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन नहीं हुआ है । आखिर हिन्दुस्तान केवल नदी पहाड़ों या कारखानों का ही देश नहीं है । वह इन्सानों का देश है और उस तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, वह नहीं दिया गया है ।

प्रोफेसर साहब ने, जो स्वंय एक शिक्षा के विशारद और पंडित हैं, यह एहसास किया है कि हमारी शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए । यह पहला कदम है, जो उन्होने सोचा है और वह अवश्य होगा । मैं मांग करती हूं कि हिन्दुस्तान की शिक्षा का प्रोडकिटविटी से क्या नाता है, यह साफ साफ होना चाहिए । समाज वादी सामाज में उस बच्चे की क्या भूमिका है जो आज स्कूल में बपढ़ रहा है, यह साफ साफ हो जाना चाहिए ।

आज हमारे देश में विश्वविद्यालयों की कमी नहीं है । लेकिन वे विश्वविद्यालय राजनीति के अखाड़े बने हुए हैं । मुझ से पहले कई वक्ताओं ने कहा है कि बनारस यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है , अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की क्या दशा है । आज भी बनारस यूनिवर्सिटी में जनसंघ की शाखायें लगती हैं । आज भी वह बिल्डिंग आर० एस० एस० के हाथ में है, जिस का उपयोग किसी अच्छे काम में होना चाहिए था । प्रो० नूरूल हसन साहब एक सैकुलर स्टेट के सिटिजन है और एक सैकुलर स्टेट की गवर्नमेंट के रिप्रेजेन्टेटिव हैं । मेरी मांग है कि वह साहसपूर्वक सब सम्प्रदाय सम्बन्धी नामनक्लेचर को मिटा दें, चाहे वह नाम बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में हो और चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो । अगर वह इस का प्रयास करेंगे , तो जनता उन का साथ देगी और भारत के इतिहास में उन का नाम अमर होगा । यह मेरी एक मांग है और मेरा यह निवेदन है । इस के ऊपर आप अपना एक सख्त कदम उठाइए ।

मुझ से पहले और लोगों ने भी इस पर प्रकाश डाला है और मैं भी कहना चाहती हूं, इस से पहले साल जब में शिक्षा मंत्रालय पर बोली थी तो आपके यही आफिसर्स थे इस गैलरी में जो आज भी बैठे हैं और मैं ने यह बात कही थी कि पंच वर्षीय योजनाओं के जरिए निस्सन्देह हमारी बहुत बढ़ोतरी हुई , उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी हुई । लेकिन जितनी डिस्पैरिटी, जितनी भिन्नता शिक्षा के क्षेत्र में साफ साफ दिखाई देती है और दूर से दिखाई देती है उतनी दूसरे क्षेत्रों में दिखाई नहीं देती । मैं विरुद्ध भी नहीं हूं पब्लिक स्कूलों के लेकिन मैं कहना यह चाहती हूं कि जितना इन पब्लिक स्कूलों ने एक भिन्नता का वातावरण एक्सप्लायटेशन और शोषण खड़ा किया है उतना और किसी क्षेत्र में देखने में नहीं आता है । मैं साहस के साथ में मिसाल दे कर कहना चाहती हूं कि माडर्न स्कूल दिल्ली का है जिस में बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, इन आफिसर्स

[श्रीमती सावित्री श्याम]

के बच्चे भी पढ़ते हैं जो गैलरी में बैठे हैं और यहां के लोगों के भी बच्चे पढ़ते हैं, जितना पक्षपात और जितना शोषण इस स्कूल में है उतना मुझे बहुत कम देखने को मिला है और भी बड़े शहरों के बहुत से स्कूल मैंने देखें हैं। कैपिटेशन फीस के नाम से दस दस हजार पांच पांच हजार और बीस बीस हजार रुपया इकट्ठा कर लिया जाता है और किस किस का दाखिला वहां किया जाता है यह देखने को चीज है। आप ने बड़े बड़े कामों के लिए बड़े बड़े कमीशन बिठाए कहीं मुदालियर कमीशन, कहीं राधाकृष्णन् कमीशन। तो मेहरबानी करके इन पब्लिक स्कूलों के लिए भी एक कमीशन बिठाइए जिससे कि आप को पता चले कि किस किस तरह का यहां इंतजाम है, किस किस तरह का यहां शोषण है और किस किस तरह का काम है। मैं पढ़ाई के लिए नहीं कहती कि पढ़ाई अच्छी नहीं होती। जरूर अच्छी होती होगी। लेकिन किस कीमत पर? देश के दो प्रतिशत बच्चे तो पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं 98 प्रतिशत बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं जिनकी छतें टपकती रहती हैं। 300 स्कूल हमारे यहां ऐसे हैं जिन पर इसी सदन के माननीय सदस्य श्री फ्रैंक एंथनी जी की मोनोपली है जिस के हिसाब किताब को, जिस के प्रबन्ध को कोई देख नहीं सकता। उस में चर्च भी हैं, आर्फनेजर्ज भी हैं और उस की आड़ में लाखों और करोड़ों की एड जो बाहर से आ रही है उस का कोई अन्दाजा आप को नहीं है। वैसे तो मैं भी जानती हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के नियमों के अनुसार बिना सरकार की जानकारी के कोई भी ग्रान्ट नहीं आ सकती। लेकिन उस में वह आ रही है। तो इस कार्मशियलाइजेशन को, इस एक्सप्लायटेशन को आप किस तरह से रोकेंगे, यह आप को सोचना है। दो प्रतिशत बच्चों के लिए 98 प्रतिशत बच्चों की आहुति मत दीजिए यह मेरी आप से मांग है।

इसी सदन में सन 1968 में एक घोषणा हुई थी सरकार की तरफ से नेशनल पालिसी आन एजुकेशन की। उस के बाद य विचार भी हुआ था कि हम कामन स्कूल खोलेंगे, नेवरहुड स्कूल खोलेंगे और हर एक ब्लाक के अंदर उस की स्थापना होगी। प्रोफेसर नरूल हसन साहब ने भी एक बार एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया था। तो मैं उन से जानना चाहूंगी कि कितने कामन स्कूल और कितने नेवरहुड स्कूलों की स्थापना अब तक की है? उन की यह घोषणा थी 1968 की जो मैं पढ़ना चाहती हूं।

"To promote social cohesion and national integration the Common School System as recommended by the Education Commission should be adopted. Efforts should be made to improve the standard of education in general schools. All special schools like Public Schools should be required to admit students on the basis of merit and also to provide a prescribed proportion of free-studentships to prevent segregation of social classes."

इस की घोषणा सन 1968 में हुई थी और आज सन 1973 है। इस की घोषणा आप ने भी की और इसी सदन में की। इस लिए मैं मांग करती हूं कि आप इस का भी जवाब दें कि कितने स्कूलों की स्थापना अब तक की गई है।

एक बात और कह देना चाहती हूं। जब किसी भी चीज में सरकारी रुपया खर्च करते हैं, किसी कारखाने में करें, किसी पब्लिक सेक्टर में करें तो पांच छः महीने बाद या साल बाद आशा करते हैं और देखते हैं कि कितनी उस में से उत्पादकता हुई? मैं पूछना चाहती हूं कि क्या शिक्षा के उपर भी खर्च करने के बाद आप यह देखते हैं कि कितनी इससे उन्नति हुई। मैं धन के संबंध में उन्नति नहीं कह रही हूं। कोई कार्मशियल बात मैं नहीं कह रही हूं। लेकिन काम कितना हुआ है इस बात के लिए मैं कहती हूं, क्या आप इस बात को जानने की कोशिश करते हैं? मैं पब्लिक एकाउंटस कमेटी के आधार पर जिस की कि

इस सदन में बहस नहीं होती यद्यपि होनी चाहिए उसके आधार पर दो तीन मिसाल देती हूं कि कितना शिक्षा के अंदर पैसे का दुरुपयोग है ? रूरल इंस्टीटयूटस जो 13 हैं हिन्दुस्तान में, उन को अभी अभी कुछ पैसा दिया गया है। उस में कोई एतराज नहीं है, लेकिन उन रूरल इंस्टीटयूटस के अंदर जिन की कई साल पहले स्थापना हुई थी, अब तक जो हम ने देखा तो जितनी उन की कैपेसिटी थी वह सब खाली रही। 1969–70 में 473 की कैपेसिटी खाली थी और 70–71 में 400 की कैपेसिटी खाली रही। क्या इस तरह से पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ ? या तो यह हो सकता है कि उस जगह की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था क्या है उस के साथ उन बच्चों का अथवा उन इंस्टीटयूट का कोई वास्ता नहीं था जिस से वहां उन्होंने दाखिला नहीं पाया और इसलिए वह खाली रहे। परकैपिटा उस का एक्सपेंडीचर पड़ा। लेकिन टीचर और टाट के अंदर जो एक रेशियो होना चाहिए उस में अंतर आया।

इसी तरह से दूसरी मिसाल में देना चाहती हूं। इंडियन इंस्टीटयूट आफ टेक्नोलाजी जिस की स्थापना के महत्व को सब समझते हैं कि बड़े बड़े टेक्नोक्रेट और इंजीनियरस इस में से हम पैदा करेंगे, इन की स्थापना का यह उद्देश्य है और उन्होंने काम भी अच्छा किया है। टैक्नालाजी के अंदर और इलेक्ट्रानिक्स के अंदर जो चमत्कार आज है वह वहां के विद्यार्थियों का है, उसके लिए हमें गौरव है। लेकिन अकेले आई टी आई दिल्ली के अंदर 300 विद्यार्थी ऐसे पढ़ते हैं जो कुछ पिछले साल भी निकले हैं और कुछ इस साल भी निकल रहे हैं वह मैथेमैटिक्स के अंदर फिजिक्स के अंदर और कैमिस्ट्री के अंदर गैच्युएटस है। तो दिल्ली के अंदर यह आई आई टी इसलिए नहीं बनी कि वह साधारण ग्रेच्युएट तैयार करे चाहे वह साइंस के हों या सोशल साइंस के हों सोशल साइंस की भी एक ब्रांच वहां बन गई है। तो ये जो ईस्टीट्यूटस हैं इन को आप सुधारने का प्रयत्न कीजिए। इनका जो लक्ष्य है, जो महत्व है, और इनका जो परपज है कि अच्छे सांइटिस्टस, अच्छे टैक्नोलाजिस्टस और टैक्नोक्रेटस पैदा करें, उस की पूर्ति होनी चाहिए। इन का यह काम नहीं है कि सिम्पल ग्रेच्युएटस बनाए। इस के लिए और बहुत से कालेजेज और सकूल्स हिन्दुस्तान भर में हैं जो इन की फैक्ट्री बने हुए हैं।

एक दूसरी मिसाल में और देती हूं। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी को एक हिस्टारिकल ग्रामर आफ हिन्दी लैंग्वेजेज लिखवाने के लिए साढ़े तीन लाख रुपया सन 1959 में दिया गया। वह रुपया खत्म हो गया, उस का हिसाब नहीं किताब नहीं मेरा कहने का मतलब यह है और मिसाल दे कर मैं कह रही हूं कि शिक्षा के नाम पर जितना रुपया खर्च हो रहा है वह कहा खर्च हो रहा है इस की किसी को जानकारी नहीं और इस में बहुत बड़ी जिम्मेदारी यू जी सी की है क्यों कि बहुत सा रुपया उसके माध्यम से जाता है। अभी प्रोफेसर कोठारी जो उसके अध्यक्ष थे रिटायर हुए हैं. बड़े योग्य व्यक्ति थे, मैं ने उन से भी कहा था कि आप जहां रुपया देते हैं उस के लिए आप एकाउंटेबल हैं पार्लियामेंट को। आप इस बात को देखें कि वह रुपया कहां जाता है, उस का हिसाब किताब पार्लियामेंट को बताएं।

पब्लिक एकाउंट्स कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटीज जो सिफारिशें करती हैं आप के आफिसर लोग लीपपोत कर उनका जवाब भेज देते हैं। मैं चाहूंगी कि आप इसको पोलिटिकल लेवेल पर देखें कि कहां उसमें कमी है।

17.00 hrs.

सभापति महोदय, हमारे देश के अन्दर हजारों ऐसे व्यक्ति हैं, हिन्दुस्तान के हर कोने में हैं, जो बड़े लिग्विस्ट हैं, शायर हैं। हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में वे जेल नहीं गए फांसी के तख्ते पर नहीं लटके, लेकिन उन्होंने अपने इल्म से इस मुल्क की बहुत खिदमत की

[श्रीमती सावित्री श्याम]

है । ऐसे लोग हर भाषा के अन्दर मौजूद हैं— हिन्दी, उर्दू, फारसी, तेलगू, मलयालम, सभी भाषाओं में हैं । पचासों वर्षों से सेवा करने के बाद आज उनके पास खाने के लिये रोटी भी नहीं है, ठिकाना भी नहीं है । मैंने आपके बजट को देखा लेकिन ऐसे व्यक्तियों के लिये आपके बजट में कहीं भी कोई प्रावीजन मुझे नहीं मिला । हिन्दुस्तान के उन लोगों के लिये, जिन्होंने अपने गीतों से आजादी की लड़ाई में जान फूंकी, जिन्होंने अपने गीतों को स्वयं गाया और दूसरों से गवाया, चाहे देवबनद का स्कूल हो, बनारस हो या साउथ का एक बड़ा विश्वविद्यालय हो, मैं उनके लिये मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वह अवश्य प्रावीजन करें । उन लोगों ने वतन के लिये बहुत कुछ किया है, अब उनका बुढ़ापा आसानी से और इज्जत से कट सके ।

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT (Kozhikode): Mr. Chairman, Sir, while I stand up to take part in the discussions on the demands of Ministry of Education I cannot but say that we have complete dis-satisfaction about the working of the Education Ministry. You know, today educational standards are deteriorating. We find a lot of unrest amongst the student population of the country and that is due to basic defect in the whole of education system which is causing frustration among the students today. Our education system does not suit to Indian conditions. Actually, we are copying the same education system that was made prevalent by the British Government when India was a slave country just to produce clerks. Therefore, the education system today is nothing but an education system that is not suited to the conditions of the country. We should have an education system that is job-oriented by which our younger generation is able to raise their standard in future life and face the realities of life with confidence.

One fact to which I want to draw the attention of the Education Minister is about the most shocking and disturbing situation that is prevailing at the Aligarh Muslim University today. We have got the news this afternoon that Aligarh Muslim University has been ordered to be closed by the Vice Chancellor of the Aligarh Muslim University. As far as I know there was no reason to do as there was no incident and tension in the university at all.

Just yesterday, our respected colleague Mr. Viswanathan happened to be at the Aligarh Muslim University and has just returned this morning from there. He told me that he was attending a Mushaira last night at the Aligarh Muslim University and the situation there was peaceful. Suddenly, I am told this morning there was a order that Aligarh Muslim University should be closed down. Now, what is happening there? I am told that police and PAC is standing by and forcing the students to get out of the campus. Sometime back Aligarh Muslim University was made a concentration of the police force inside the campus. How is it possible for thousands and thousands of students who are just going to sit for the examination to vacate and get away and thus destroy their future academic career and future life as citizens of this country. This is a very very disturbing situation that has taken place at the Aligarh Muslim University.

I will not deal at length with the circumstances which have led to such a situation. I will only say that we suspect that this is the culmination of the process by which the authorities are conspiring to destroy this citadel of Muslim culture and learning and shining example of secularism in this country.

Members have said here while taking part in this discussion that there should not be any majority character or minority character as far as education is concerned. But this is against existing facts. When minori-

ties are there in this country, they will also have their educational institutions. The Constitution has very clearly given them a right to establish, administer and manage their own educational institutions.

You are well aware that whenever we have had foreign dignitaries visting this country, be it President Nasser of Egypt, King Faisal of Saudi Arabia or President Soekarno of Indonesia, they were all taken to Aligarh Muslim University to show them this shining example of secularism in this country. To say today that this is against secularism is something that denies the very facts in accordance with which the authorities were acting so far.

You are aware that there has been disturbing development and serious designs against Aligarh Muslim University right from 1965, when because of some incident, the University's Court and Council were abolished and by an Ordinance the entire administration of the University was taken over. Later by an Act, the Central Government took full control of the University through a nominated Court and Council. Ever since then, there has been a consistent demand on behalf of the community to see that the minority character and democratic character of the institution should be retained, safeguarded and protected. This demand has been put forth from every corner of the country.

DR. KAILAS (Bombay South): Are we discussing demands of Education or Aligarh Muslim University only? Secondly, how do secularism and minority character go together?

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT: I do not yfield. We are having a discussion. Secular character means and the Constitution means that there should be protection to minorities when minorities exist.

MR. CHAIRMAN: The discussion is specific. You may refer to matter which may have taken place here and there. At the same time by dilating upon them and taking your entire time on it, you are wasting your time because you may have very important suggestions to make as far as education is concerned which you may not have the time to make.

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT: When I knew about these facts about the situation existing in the University, I just thought of raising the issue here at this time.

MR. CHAIRMAN: You can have another opportunity.

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT: Aligarh Muslim University issue is part and parcel of our educational system. It is a central university and hence the entire responsibility lies with the Education Ministry of the Government of India. Nobody can shut out the discussion of Aligarh Muslim University here.

May I say that Aligarh has produced some of the greatest sons of the country? People like Maulana Mohamed Ali, Dr. Zakir Hussain, Rafi Ahmed Kidwai, Maulana Hazrat Mohani and Raja Mahendra Pratap have all been the products of Aligarh Muslim University. These are facts. There is no question of national or anti-national in this. I am talking of facts.

SHRI VASANT SATHE (Akola): Why do you want to destroy that character?

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT: We do not want to destroy it. On the other hand, we desire to safeguard such a character. This great University has produced some of the great sons of this country. We have done great service to the country.

DR. KAILAS: We are worried about the future, not the past. Talk of the future. hink of what our grand children will say about us.

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT: Yes, we are also worried about the future of Aligarh Muslim University. We want that the minority and democratic character of the institution should be protected and continued.

You may ask what is the minority character? We do not shut out the gates of the university to anybody. Everybody should be there. All the communities should come there to get educated and enlightened, but again, this university has got a peculiar character. The Aligarh Muslim University was established by the Muslims for their own benefit. It was the Muslims themselves who contributed large sums of money, made endowments and constructed buildings, and thus requested the then Government of the country in 1920 to establish a university for the benefit of the Muslim community for their educational development. Even now, most of the Muslims in Bihar, Uttar Pradesh and other parts of the country are a backward community, and therefore they should be helped to come up. (*Interruption*). I want every backward community to come up. Every backward community should be given the opportunity to progress. That does not mean that because some community is not given adequate opportunity to progress, the Muslims also should not be given this opportunity. I do not say that the Muslim community alone should be given educational facilities to progress. I say that all the backward communities should be given equal and adequate facilities to improve themselves.

SHRI VASANT SATHE: You say that it was established by the Muslims, for the Muslims and of the Muslims. Is that your concept of your secularism?

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT: I have already said what I understand about secularism. I am talking about the estblishment of the university by the Muslims themselves. They gave the funds; they gave the endownment, and the buildings, and it was established for their benefit.

MR. CHAIRMAN: There are non-Muslims also.

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT: I admit still there are non-Muslims there. As far as the medical college and the engineering college are concerned, the proportion is 30 per cent Muslims and 70 per cent non-Muslims; and as far as the other departments of university are concerned, it is 60 per cent Muslims and 40 per cent non-Muslims, today.

SHRI VASANT SATHE: Why don't you get representation in the Governing Body? Why don't you accept that? That is more democratic.

MR. CHAIRMAN: Order, please. We are going on a wrong direction. Just a minute. Please sit down. The subject before us is education; you are confining yourself only to take Aligarh Muslim University. Your time is up and I will have to call upon you to end your speech, and then, I am afraid that, in spite of your experience, the House will be deprived of many good suggestions that you may like to give. That is why I request you to confine yourself to education.

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT: I am speaking on education, and the Aligarh Muslim University is part of the subject of education. So, it does not mean that I should exclude it when discussing education. When our friends get time they can speak instead of interrupting me now. (*Interruptions*). We can have the benefit of your wisdom also. I am not denying all this.

Now, even when the Chatterjee Commission was there, which went into the question of the Aligarh Muslim University, it suggested that there should be 65 per cent Muslims and 35 per cent non-Muslims in the university. That Commission itself

recommended this sort of proportion as far as the Muslims and the non-Muslim students in the university are concerned. All these facts are there. Now, why are we against the present policy? We say that not only is the minority character, but the democratic character of the university also is completely destroyed. That is what we say. An Aligarh Muslim University Bill was introduced in 1970 in the Rajya Sabha; it was withdrawn. That Bill was much better than the Bill which was introduced in 1972. This Bill we expected will be an improvement on the 1970 Bill. But instead Bill of 1972 was much worse. It went against the autonomy; the democratic character of the university was destroyed. This sort of Bill is being opposed today also by the Delhi and the Banaras Hindu Universities because it has no democratic character at all. The university's autonomy has been completely destroyed. All the powers have been given to the Vice-Chancellor, and Court and the Council is a completely nominated court and council. We want that this should be scrapped. We want that there should be a properly constituted court and council wherein we can have representatives of the minorities and others also with powers to administer the university. There should be effective minority representation, because, when we make a demand of minority charactr, we desire that the effective majority in the Court and Council should be of Muslims. When we say minority character, it also means that effective control should be in the hands of the true representatives of Muslim community.

SHRI VASANT SATHE: So, you say that the communal character should be maintained.

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT: No. I say that the minority character should be retained. There is no communalism here. So far as minorities are there, we have got our rights also.

We have to keep our identity. That is why we thought that we must have effective control in the administration of the University and the Muslim majority should be reflected there. This is what we have been demanding, and this is nothing that is against the Constitution. Throughout the country there have been agitations against this Bill. We demand that this Act should be withdrawn immediately and the *status quo* should be established, which means the bringing back of the 1951 Act. A new Bill should be brought based on the recommendations of the Beg Committee, which will fulfil the aspirations of the Muslim minority, and passed. This is what we are asking. Instead of that to have police raj in the university, shut down the University, ask the students to get out, destroy the career of the students and disturb the academic atmosphere in the University is not a wise step. The Government of India, which says that it is democratic and which says that it is a secular Government, should do this to improve the conditions of the student population in this country.

श्री अनंत प्रसाद धूलिया (बस्ती) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा से उपर बहुत से लोग बोल चुके हैं लेकिन मैं सिर्फ इसके सिस्टम पर बोलूंगा । भारतीय शिक्षा पद्धति में लार्ड विलिंगडन के जमाने से परिवर्तन की आवाज आती रही है और यह परिवर्तन अगर कहीं थोड़ा सा हुआ भी तो उसका बहुत ढिंढोरा पीटा गया और इतना रंग चढ़ाकर कहा गया जिसका कोई हिसाब नहीं । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी राष्ट्रीय नेताओं ने और बड़े बड़े एजूकेशनस्ट्स ने यह कहा कि शिक्षा पद्धति में समाज तथा समय की आवश्यकतानुसार परिवर्तन होना चाहिए । उसके लिए पूरे देश में कमीशन्स बिठाये गए, उसकी मीटिंग्ज की गई और उस पर लाखों रुपए खर्च किए गए परन्तु उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकला । उसका इम्प्लीमेन्टशन भी नहीं हुआ और न शिक्षा के ढांचे में कोई पर्याप्त परिवर्तन हुआ जबकि पूरा देश आपके मातहत था, पूरा शासनतंत्र आपके अंडर में था । यह एक बड़ी भारी

[श्री अनंत प्रसाद घूसिया]

दुर्भाग्य की बात थी । इसका कारण क्या है कि जब पूरा देश एक स्वर से यह चाहता था कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन हो, शिक्षा के द्वारा देश की उन्नति हो लेकिन वह नहीं हो सका जबकि पूरा देश आपके साथ था । उसमें कौन सी कठिनाई आई और वह क्यों नहीं पूरा हुआ ? मेरे खयाल में इसका एक ही जवाब है और वह यह है कि गवर्नमेंट ने कोई कारगर कदम नहीं उठाया । उसके साथ साथ यह की ब्यूरोक्रैसी और धनिक वर्ग तथा सामन्तवादी हमेशा जनशिक्षा के विरोधी रहे हैं, वह इसकी आड़ में बैठे रहे हैं । वे लोग कभी भी यह नहीं चाहते हैं कि वहां की शिक्षा जनशिक्षा हो, वह सामाजिक शिक्षा के अनुरूप हो जिससे देश की उन्नति हो क्योंकि इसमें उसका बहुत बड़ा लाभ है । लाभ यह है कि सरकारी नौकरियों में उनको बड़ी से बड़ी जगह मिल जाती हैं । कल-कारखाने चलाने के लिए उनको मौका मिलता है और व्यापार की बहुत सी सुविधायें उनको मिलती हैं । इससे उनको अपार धन इकट्ठा करने में बहुत साधन मिल जाते हैं । मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जो मौजूदा तालीम है उससे इस देश की उन्नति कभी भी नहीं होगी चाहे आप कुछ भी करें ।

जब तक इस तालीम को आप प्रोडक्टिव नहीं बनायेंगे तब तक देश की हालत सुधरेगी नहीं । और जो वर्तमान शिक्षा चल रही है इसको तो मेरे खयाल से बरसाती बाढ़ का पानी ही कहना उपयुक्त होगा जिस को न पीजिये तो प्यास बुझती नहीं है और अगर पीजियेगा तो जुखाम और बुखार हो जायगा । अगर इस तालीम को समाज के आवश्यकता के अनुरूप नहीं बनाया गया तो इसका परिणाम यह होगा कि भयंकर बेकारी होगी और इसके साथ नेशनल इंटिग्रिटी और फ्रंटर्निटी बिल्कुल नाम मात्र को रह जायगी तथा देश में बड़ी भारी बेचैनी सी आयेगी । माननीय शिक्षा मंत्री महोदय इसको नोट करें, इसकी शुरूआत अभी से हो चुकी है और आने वाली पीढ़ी इस गलती को कभी माफ नहीं करेगी ।

अब मैं अमरीका और जापान की शिक्षा पद्धति के बारे में बताना चाहता हूं । अमरीका में भी, जैसी इस वक्त वर्तमान शिक्षा हमारे भारतवर्ष में है, जब यूरप से सभी देशों के लोग गये थे वहां पर भी इसी तरह की शिक्षा थी । परन्तु बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में उन लोगों ने देखा कि इससे हमारी आर्थिक समस्या हल नहीं हो पा रही है तो बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में उन लोगों ने लैंड ग्रान्ट्स एक्ट पास किया और उस ने अनुसार बड़े बड़े फार्म तैयार कराये गये । हर एक सदस्य की कांस्टीट्यूएंसी में इन फार्मों पर साइंस, एग्रीकल्चर, पोल्टी और दूसरी किस्म की जो जरूरी चीजें हैं, सब पर वहां व्यावहारिक ट्रेनिंग दी जाती थी और जो सामुदायिक विकास केन्द्र होते थे उनमें वह काम करते थे । इसका नतीजा यह हुआ कि सभी क्षेत्रों में बड़ी अच्छी तरक्की हुई और देश समृद्ध हो गया ।

अब मैं पड़ोसी देश, जापान का भी जिक्र कर देना चाहता हूं । यहां की शिक्षा तो अमरीका से भी बहुत ज्यादा अच्छी है, और वहां की शिक्षा का ही परिणाम यह है क वहां पर अनुशासन और श्रम के विषय में इतनी मान्यता है कि ईश्वर की पूजा से भी बढ़कर इस चीज की मान्यता दी जाती हैं । इसका परिणाम यह हुआ कि संसार में जितने जहाज बनते हैं उसके आधे जापान में बन रहे हैं । मोटर कार, इलेक्ट्रानिक्स, मशीनरीज, सभी चीजें जापान यूरप के बहुत से देशों, और अमरीका तक से आगे बढ़ गया हैं, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि जापान से एक प्रतिस्पर्धा हो गयी हैं तमाम इंडस्ट्रियल कन्ट्रीज की हमारा वह देश है जहां कि आदमी अपने देश में जब आते हैं तो आपकी बड़ी इज्जत करते हैं और आपकी मातृभूमि के आगे सर झुकाते हैं ।

एक चीज में भाषा की पौलिसी पर भी कहना चाहता हूं कि आपकी लैंगएज पौलिसी कितनी गलत रही है । इस देश में भाषा के ऊपर कितने झगड़े हुए हैं जो शायद ही किसी देश में इतने हुए हों जितने कि यहां । यहां पर खून

खराबियां भी हुई । फिर महोदय आपने कुछ जगहों पर संस्कृत यूनिवर्सिटीज खोलीं । संसार में क्या कहीं किसी मुल्क में संस्कृत बोली जाती है ? कहीं भी नहीं । लेकिन फिर भी आपने संस्कृत विश्वविद्यालयों को ग्रान्ट दी । इसके साथ उन संस्कृत यूनिवर्सिटीज में क्या आप बता सकते हैं कि कितने मुसलमान हैं, कितने हरिजन हैं तथा दूसरी जातियों के हैं ? क्या आपने पाली, प्राकृत और फारसी भाषाओं को भी ऐसा ही दर्जा दिया जो कि संस्कृत को दिया? नहीं दिया । इससे साबित होता है कि आपकी भाषा पौलिसी अनवाईस्ड नहीं है ।

आपने कल्चर के नाम पर कुछ ग्रान्ट कुछ किताबों के प्रचार के लिये दी थी, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि गुरु नानक और संत कबीर के उपदेशों और उनके साहित्य के विषय में क्या किया ? कुछ नहीं किया । कबीर और नानक ऐसे संत थे कि जिस समाज में पैदा हुए उसी में रहे और ऐसे उपदेश इन्होंने लोगों को दिये कि हिन्दू इनको अपना समझते थे, मुसलमान अपना समझते थे और अछूत इन्हें अपना मसीहा समझते थे । लेकिन आपने उनके उपदेशों और साहित्य का कोई प्रचार नहीं किया ।

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिये । आप अनुचित लाभ उठा रहे हैं ।

श्री अनंत प्रसाद चूसिया : बस मैं समाप्त ही कर रहा हूं । अन्त में एक बात और कहनी है कि प्राइमरी से हायर सेकेन्ड्री स्कूल तक सब को नेशनेलाइज किया जाय और डिग्री कालेजेज में टैकनालाजी, ऐग्रीकल्चर की पढ़ाई पर विशेष जोर दिया जाय । इसके साथ साथ हरिजनों की शिक्षा के लिये शिक्षा विभाग में एक सैल तैयार किया जाय जो देखे कि हरिजनों और आदिवासियों की शिक्षा का ठीक प्रसार हो रहा है कि नहीं ।

MR. CHAIRMAN: Before I call upon the next Speaker, I would like to inform the House that at 5 minutes to 6 I will call upon the Minister to begin his reply. He will continue his reply tomorrow. I have got so many names. Some threatening letters are also coming to the Chair from some members. I think if members on this side do not take more than 5 minutes, I can call a few of them.

आज मंत्री जी खड़े हो जायगे और कल तक उनका रिप्लाई चलेगा । जितने नाम सदस्यों के आये हैं सब के सब ऐकोमोडेट नहीं हो सकते हैं । मैं समझता हूं कि उसके लिये कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी ।

श्री भान सिंह भौरा : एक एक मिनट हर माननीय सदस्य के टाइम में से कम कर दीजिये ।

सभापति महोदय : एक एक मिनट कम करने से मतलब नहीं रखता है । अच्छा होगा कि माननीय सदस्य चेयर के साथ ताबुन करें और कार्यवाही पूरी करने में मदद करें । माननीय शैलानी जो, आप पांच मिनट में अपनी बात कह दें ।

श्री चन्द्र शैलानी (हाथरस) : आप कहें तो एक मिनट भी न बोलूं । मिनिस्टर साहब ने 10 मिनट के लिये मुझसे कहा है और दसवें सरियल नम्बर पर मेरा नाम था, लेकिन आप 31, 32वें नम्बर पर बुला रहे हैं । आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, थोड़ा आप को सोचना चाहिये । अगर आप नहीं चाहते तो नहीं बोलूंगा ।

सभापति महोदय : आप बोलिये ।

श्री चन्द्र शैलानी: सभापति जी, मैं शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इतने कम समय में अपने विचार प्रकट करने में मैं अपने को असमर्थ पा रहा हूं । इसलिये मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा समय आप मुझे दें । शिक्षा के ऊपर किसी भी देश के भविष्य का निर्माण होता है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर भारत सरकार ने आजादी के बाद जो अपनी नीति अख्तियार की है वह, मैं यह तो मानता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी उन्नति

[श्री चन्द्र शैलानी]

हुई है और काफी प्रगति भी हुई है लेकिन जिस गति से उसकी उन्नति होनी चाहिए थी, मुझे जैसे इन्सान को उस पर संतोष नहीं है । मेरे जैसा समाजवादी विचारों और सिद्धान्तों को अमल में लाने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि आज शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, और वह तभी सम्भव हो सकता है, जब कि भारत सरकार इस बारे में बहुत गम्भीरता से सोचे और इसकी ओर ध्यान दे ।

यहां मैं महामहिम राष्ट्रपति के उन शब्दों को दोहराना अपना कर्त्तव्य समझता हूं, जो उन्होंने अजमेर में मेयो कालेज में कहे थे : शिक्षित वर्ग के बेरोजगारों की कतारें यह बताते हैं कि आज देश के शिक्षित वर्ग में बहुत बड़ी बेरोजगारी है और उनमें कब क्रान्ति का जलजला फूट पड़गा, कहा नहीं जा सकता ।

शिक्षा मंत्री, श्री नूरुल हसन साहब, भी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन के हामी हैं और उन्होंने कई बार कहा है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति होनी चाहिए । हमारे देश की महान् नेता और देश के करोड़ों गरीब, भूखे, नंगे और अनपढ़ लोगों और समस्त जनता के हृदयों की स्वामिनी, श्रीमती इन्दिरा गांधी, ने भी यह स्वीकार किया है कि शिक्षा में जबर्दस्त क्रान्ति की जरूरत है ।

मैं नहीं समझ पाता कि आखिर वे कौन सी चट्टानें हैं, जो हमारा रास्ता अवरुद्ध किये हुए हैं और जिनको हटा हम नहीं पा रहे हैं । मैं इस सम्माननीय सदन में यथार्थवादी विश्लेषण करने की गुस्ताखी करना चाहता हूं कि उन दीवारों को तोड़ने के लिए हमें क्रान्तिकारी कदम उठाने पड़ेंगे । इतिहास से विरासत में जहां हमें गुलामी मिली, वहीं असमानता विषमता, भदभाव, शोषण, साम्प्रदायिकता और जात-पात भी मिली । सामाजिक क्रान्ति और सामाजिक चेतना के द्वारा उनको दूर करना और उन पर विजय प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए और वह लक्ष्य है भी ।

कानून बनाने का काम इस संसद का है । यहां ऐसे कानून बनने चाहिए, जिन के द्वारा सच्चे मानों में शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन हों, जैसा कि हमारे नेतागण चाहते हैं । आज शिक्षा के पवित्र मन्दिरों में चलने वाली ठेकेदारी बन्द होनी चाहिए । देश की सारी शिक्षा का थोक व्यापार हमें अनाज के थोक व्यपार की तरह अपने हाथ में लेना होगा । जिस प्रकार प्रतिक्रियावादी और पूंजीवादी पार्टियां और उनके संरक्षक गल्ले के थोक व्यापार के सरकारीकरण का विरोध कर रहे हैं, उसी तरह शिक्षा के मन्दिरों को उन्होंने अपने निहित स्वार्थों का अड्डा और समाजवाद-विरोधी दकियानूसी व्यापार का साधन बना रखा है ।

मिसाल के तौर पर मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस का नाम लेना चाहता हूं । मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि आजादी के पच्चीस वर्ष बाद की अभी पिछले साल जब उत्तर प्रदेश विधान सभा के छ ; माननीय सदस्य अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहां पर हुए उपद्रवों के संबंध में तथ्यों की जानकारी लेने के लिए पहुचें और यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में ठहरे, और वहां के साम्प्रदायिक तत्वों को यह पता लगा, तो उन्होंने आ कर वहां उन का बेइज्जत किया, उन का सामान फेंक दिया और उन के कपड़ों पर पान की पीक फैंकी ।

आप को और इस सदन को, हिन्दुस्तान और पूरे संसार को पता है कि उससे पहले वहां पर राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत, श्री अली यावर जंग की, जब कि वह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर थे, हत्या करने का प्रयास किया गया । वहां के राष्ट्रपति विचार के लोगों ने उन को बचा लिया, वर्ना वहां कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती थी । मंत्री महोदय भी कुछ दिन पहले अलीगढ़ गए थे । उन के साथ जो व्यवहार हुआ, वह बहुत ही खेदजनक और लज्जाजनक था ।

अब मैं बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी पर आता हूं। जैसा कि मुझ से पहले बहुत से वक्ताओं ने कहा है, मैं चाहता हूं कि इन साम्प्रदायिक तत्वों का शीघ्र से शीघ्र इलाज किया जाये और विद्या के पवित्र मन्दिरों में जो विषैले नाग पल रहे हैं, उनको शीघ्र से शीघ्र वहां से हटाया जाये, अन्यथा यह नहीं कहा जा सकता है कि इस देश का भविष्य क्या होगा। मुझ से पहले कई वक्ताओं ने बताया है कि बनारस विश्वविद्यालय में एक भवन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने जबर्दसती कब्जा कर रखा है। यही नहीं, वहां पर आर० एस० एस० की 35 शाखायें लगती हैं।

जब बनारस यूनिवर्सिटी में उपद्रव हुए थे, तो वहां पर आर० एस० एस० के लोगों ने अर्थ शास्त्र विभाग के रीडर, डा० उमेश प्रसाद, को मारा और उन के दांत तोड़ दिए। आज भी वहां पर आये दिन उपद्रव होते रहते हैं और शांति भंग होती रहती है। साम्प्रदायिक तत्व विद्यालयों में पनपते हैं और उन को गिजा मिलती है। मेरी समझ में नहीं आता कि वे कौन सी ताकतें है जो उन को गिजा देती है। मेरा निवेदन है कि सरकार इन साम्प्रदायिक तत्वों को नेस्त नाबूद करने के उपाय सोचे, जिस से हमारा देश हरा-भरा हो और हमारे देश में अशांति की जगह शान्ति स्थापित हो। मुझे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, डा० त्रिगुण सेन के ये शब्द याद हैं कि शिक्षा में जो असमानता है, वह समाप्त होनी चाहिए, पब्लिक स्कूल बन्द होने चाहिए और मजदूर का बेटा हो या पूंजीपति का बेटा हो, सब को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन नौकरशाही की वजह से उन का यह सुझाव आज भी फाइलों में ही गुम है और पता नहीं, उस का क्या हो रहा है।

मुझ जैसे शोषित समाज के व्यक्ति को यह देख कर बड़ी वेदना होती है कि इस मूल्क में एक तरफ तो एक बाप अपने पांच बरस के बेटे को दून स्कूल में भेज कर पांच सौ रुपया महीना खर्च करता है और दूसरी तरह शोषित और दुर्बहारा वर्ग का एक बाप, जो सुबह से शाम तक कारखाने या खेत में खून पसीना बहा कर के इस देश का नव-निर्माण करता है, वह गरीब और मेहनतकश बाप अपने पांच बरस के बेटे की शिक्षा के लिए पांच रुपया महीना भी खर्च करने में असमर्थ है। इस मुल्क में शिक्षा के क्षेत्र में इतनी बड़ी असमानता देखने को मिलती है। समाजवाद का हमारा स्वप्न तभी साकार होगा, जब हम को शिक्षा के क्षेत्र में इन्साफ और समानता देखने को मिलेगी।

मुझे आश्चर्य होता है, जब मैं बी० ए० या एम० एस० पास नौजवानों को सड़कों पर रिक्शा खींचते हुए देखता हूं और एक पूंजीपति के कबाड़ी बेटे को कार में जाते देखता हूं, जिस को ए बी सी भी नहीं आती। आज पढ़े लिखे नौजवानों के सामने कोई निश्चित भविष्य नहीं है, और इसकी वजह से आज हम को लड़ाई-झगड़े उपद्रव, मारपीट और अनुशासनहीनता देखने को मिलती है।

मैं चाहता हूं कि इस मूल्क में समाजवादी विचार-धारा की शिक्षा हो, सामजवादी विचार-धारा से सोचने का तौर-तरीका हो और सच्चे मानों में नौकरशाही का स्थान लोकशाही ले। मैं चाहता हूं कि हमारे देश का नाम बदल कर भारतीय समाजवादी गणतंत्र होना चाहिए।

आज देश में समाजवाद की जरुरत है, क्योंकि समाजवाद के द्वारा ही इस देश में समानता आ सकती है। शिक्षा का आधार भी समाजवाद होना चाहिए।

अब मैं समाज कल्याण के बारे में कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। हमारे देश में बहुत समय से सामाजिक उथल-पुथल देखने को मिल रही है और यहां पर सामाजिक अव्यवस्था है। अगर आजादी के पच्चीस वर्ष बाद भी, आजादी की रजत-जयन्ती के बाद भी, हम को यह सामाजिक अव्यवस्था

[श्री चन्द्र शेखरी]

देखने को मिलती है, तो मैं सोचता हूं कि हमारा लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज आफ़ स्टेट पालिसी में संविधान के लागू होने के दस वर्ष के भीतर चौदह साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही गई है। क्या मैं समझूं की दस वर्ष का मतलब सौ वर्ष होता है? देश को आजाद हुए पच्चीस वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी मैं देखता हूं कि जिन बच्चों को शिक्षा देने की जरुरत है, जो शिक्षा प्राप्त करने पर डाक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर बन सकते हैं, जो देश के निर्माता बन सकते हैं, उन के भविष्य को बनाने के लिए कोई सामग्री नहीं जुटाई जाती है और आज वे बाजार में दोने चाट कर अपने पेट की ज्वाला को शान्त करते हैं, उनको रोटी मिलना भी दुश्वार है। मेरा निवेदन है कि सरकार का दर्जा एक पिता के बराबर है। अगर कोई पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं देता है, अच्छा खाना नहीं देता, अच्छे कपड़े नहीं पहनाता और उलटे जो कमाई कर रहा है उस से शराब पीता है तो उसे मैं नालायक बाप ही कहूंगा। इसी तरह से भारत की सरकार का यह परम कर्तव्य है कि वह भी अपने देश के हर नागरिक के लिए रोटी और रोजी का, उस की शिक्षा का पूरा इंतजाम करे और अगर इस में हमारी सरकार विफल रहती है तो मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय संविधान के जो प्रावधान हैं उन की तरफ उस का ध्यान नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा।

एक निवेदन और मैं आप से कहना चाहूंगा। वैसे मैं सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूं कि इस ने शैड्यूल्ड कास्ट ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को होम मिनिस्ट्री में से लिया है। यह स्वागत योग्य बात है। मैं चाहता था कि शैड्यूल्ड कास्ट एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए एक अलग से मंत्रालय खोला जाये। क्योंकि इस देश में छोटे छोटे विषयों, छोटी छोटी बातों के लिए मंत्रालय खोल रखे हैं जैसे पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन तो इतनी बड़ी समस्या जो शैड्यूल्ड कास्ट एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्ज की है उसके लिए भी अलग से एक मंत्रालय खोला जाये।

मेरा निवेदन है कि मेरी इन भावनाओं को सरकार तक आप पहुंचायें और उसके अनुसार ऐसे कार्य करें जिस से कि आप कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में तो तरक्की हो। आज शिक्षा के क्षेत्र में हालत यह है कि प्राइमरी स्कूलों में कहीं टाट नहीं है, पीने का पानी नहीं है और उन के अध्यापकों की हालत बहुत खराब है। पैरों में फटी चप्पल है, शरीर पर फटा कुर्ता और फटी धोती है। मेरा निवेदन है कि इस स्थिति में अवश्य ही सुधार होना चाहिए और इन विद्या के मन्दिरों का निर्माण इस तरह से होना चाहिए जिस से कि सच्चे मानों में इन में से देश भक्त और देश के निर्माता निकल सकें।

सभापति महोदय: देखिए यह बात जरा ठीक नहीं हो रही है। आपको जितना समय दिया गया उस का लाभ उठा कर आप और ज्यादा समय भी लेते हैं यह उचित नहीं है। आप दूसरे का भी ख्याल रखें। और भी बहुत से लोग बोलने वाले हैं। आप एक घंटा और बैठना चाहें तो दूसरी बात है नहीं तो इस डिस्कशन को तो आज खत्म करना ही है। इसलिए जितना समय दिया जाये उससे अधिक न लें।

*SHRI JAGADISH BHATTACHARYYA (Ghatal): Mr. Chairman, Sir, I would not go in detail about the working of the Ministry of Education and Social Welfare because the time at my disposal is short but still within this short time I would raise a few points for the consideration of the hon. Minister.

*The Original speech was delivered in Bengali.

Sir, even though we speak eloquently about the urgency and need for the education of the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, yet in practice we have not done really much. From my personal experience I can tell you Sir that whenever we go to our constituency the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the backward classes come to us and often say "why don't you give us a school?". These people are poor and in most of the cases they do not get a square meal a day yet they have a genuine craving for education. Sir, if we look into the census report, then we will be convinced that during the last 10 years nothing appreciable has been done for the spread of education among these people. Very often the Government proclaims and paints a rosy picture of the different schemes that they propose to undertake in future but I am not so much interested in future as in the present and therefore I would like to know what is being done for these people for the present for the picture of governmental action in this sphere is not very clear. Secondly I would like to say that the facilities that Government give for the benefit of the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes do not reach uniformly to all. It has so happened that even among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people a particular class has now emerged who have gained some higher status and most of the governmental benefits go to this circle at the cost of the multitude. In order to be entitled to the governmental benefits one has to conform to some educational standards. I must in this connection urge upon the Government that unless we liberalise our policy in this regard a great multitude of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people will always remain out of the purview of these benefits. If we look into the background of the students coming from this segment, we will find that a student may be the first in the whole of his generation who has come forward to get education. When this is the reality of the situation how can we expect a very high standard of education growing among the average students coming from this class. If a student fails in a particular class or he gets little less mark in the examination then he is denied the facilities that he was getting before. I feel that this attitude is not conducive to the development of an atmosphere where the students of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should feel enthused to pursue their studies. While I do not approve of it I feel that the matter needs to be looked into afresh for importing greater liberalisation into the whole scheme. In the world of sports we have failed to create a place of our own. Except in hockey, cricket and even in football, we have remained almost a non-entity in the field of athletics. If we are really serious to see that our country gains its rightful place in the world forum of athletics, it is imperative that the training schemes for atheletes should be started from the block level. I know Sir that some instructors and officers have been appointed for the promotion of games education among the rural youth but they survive on paper only and in fact they function no more and no less than a clerical hand to the B.D.O. They have no well chalked out programme before them nor they have funds to finance the same. Because of the lack of proper organisation, the entire rural youth energy is going waste. Sir, the rural young men particularly the Adivasis are far more energetic and to have a vast reservoir of stamina than their urban counterparts. I know Sir that a Adivasi youth can walk with ease 40/50 miles a day which may be an impossible task for even the best athlete who comes from the urban sector on whom the country mainly depends for a world competitive event.

Now, Sir, if we exploit this vast untapped source of energy who belong to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Adivasis and if we give them proper training

[Shri Jagadish Bhattacharyya]

then I am sure we would be able to create a new chapter in the world history of athletics and add to the glory of India. If we look to America, we will find that the Nigroes there, have brought laurels for their country and they are the persons who bag the largest number of medals in the Olympics for their country. Sir, a few days ago a wrestling competition was organised in Delhi. I was horrified to read in newspapers that the participating wrestlers were lodged in a house close to a latrine, the rooms were damp and the food was inadequate and even that too they had to cook themselves. This is the treatment that we are giving to our budding athletes from whom selections are made for our team for Olympics. Contrasting to this we often find that the cricket, hockey and football players are lodged in five star hotels. Why this difference in courtesy? Why this monsterous discrimination? Some housed in five star hotels and others in damp rooms near a latrine. We must try to end such appealing discrimination. India has a tradition in wrestling and we must try to regain the lost glory and to achieve it the first thing that we must do is to end discrimination.

I would now like to say a few words about the facilities given to destitute women. This is once again a sphere where the Ministry's record is a dismal one. Last year Rs. 15 lakhs was earmarked in estimates but it was actually reduced to Rs. 5 lakhs. Please note Sir from Rs. 15 lakhs to Rs. 5 lakhs. Whenever the Government wants to collect more funds, the Department of Education becomes the first casualty as if the country has no need for education and as if all other things should get a priority over it. But the irony of the matter is that even this small amount was not spent. Naturally a great number of destitute women, particularly the war widows who needed urgent help have gone without it. There are many destitute women in the rural areas whose demands are genuine and in many cases even when we have forwarded their applications through the BDO, they have lost their way into Government files never to see the light of the day and the needy women could never get any help in their life time.

Now I will come to Government's policy of allocation of funds for propagation of different languages. We have found that last year the Government had spent Rs. 3.36 crores for the propagation of Hindi and for the rest of the 15 languages which have been recognised by the Constitution, the Government have spent only Rs. 1 crore. I have no quarrel with Hindi. Let it prosper and if need be let Government double the allocation but why this apathy towards other languages. Do they not deserve a better deal. You are giving them only a pittance. It is nothing more than a charity donation. This lopsided policy of the Government is hardly conducive rather runs counter to the cultural integration of the country. Sir, the language in which I am speaking is the language which has given our nation its national anthem. It is through this language that Rabindranath Tagore won the Nobel prize. There are many writers and poets of immense promise who are languishing in poverty today in West Bengal. If we are able to rehabilitate them financially, not only that the Bengali literature will be enriched but in turn it will enrich the composite culture of our country.

Sir, when Shri Siddhartha Shankar Ray was the Central Education Minister, he had promised to bring forward a "children policy Resolution". Still today nothing has been done by Government in this regard. I would therefore urge upon the Government to hasten the matter and take an early decision.

When we are suffering from the banes of illiteracy, we find that in the rural areas the scheme for free female education upto the 8th class, is not being run properly. Here if a girl fails once, she is denied the benefit of free education. I am sure that

Government must look into the matter and see that such unnecessary restraints are removed and the girls are given proper encouragement to pursue their education. A little while ago Shri Yadav had said that persons beyond the age 45 would be excluded from the purview of the scheme for giving education. I do not approve of it. I strongly feel that age should not be a bar to education. All persons irrespective of their age should be given education. It is necessary. It is a must. It is possible. It is imperative when we find that illiteracy is growing in our country. Even in the war ravaged Vietnam, except the idiots and the lunatics, none has been denied the light of education.

Sir, I would briefly touch upon two more points and conclude my speech. In Dandakaranya project the refugee students were educated through the medium of Bengali. I have received letter from these refugees who have complained that instead of Bengali, the students are now being taught through the medium of Oriya or Hindi. I do not know how far it is correct. I would therefore request the hon. Education Minister to kindly take some personal interest in the matter and find out the truth and he should also see that all the students who were hitherto being taught through the medium of Bengali are once again given the same facility.

And finally about the youth centres. There cannot be two opinions that the youth of our country should be given better opportunities and all steps in the direction of creation of such facilities should be welcomed. But here I would like to sound a word of caution. From our experience we have found that whenever any organisation is set up with Government assistance it soon develops to become an appandage of the State Government which utilise them for their party interest. I would therefore like to suggest that all these youth centres should be made autonomous and utmost care should be taken to see that they are not utilised for political considerations.

श्री मुल्की राज सैनी (देहरादून) : सभापति महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं, आपने मुझे शिक्षा मंत्रालय की मांगों पर बोलने का अवसर दिया। हमारा शिक्षा मंत्रालय आज कैबिनेट स्तर का मंत्रालय नहीं है —मंत्रालय भी छोटा है उसका बजट भी छोटा है, उस के प्रयास भी छोटे हैं। देश बहुत बड़ा है, शिक्षा का काम बहुत बड़ा है और जैसाकि कई माननीय सदस्यों ने कहा है शिक्षा के बगैर मनुष्य पशु के बराबर होता है। उस को मानव बनाने के लिए शिक्षा की आवयश्कता होती है, वह शिक्षा हर स्तर पर, हर गांव में, हर शहर में, सारी जनता को मिलनी चाहिए।

लेकिन पढ़ कर और सुन कर बड़ा ताज्जुब होता है कि 38 करोड़ व्यक्ति इस देश के अन्दर शिक्षा से वंचित हैं। जो शिक्षा मिलती है, वह किस को मिलती है कहां मिलती—इस बात को भी सब ने माना है कि शिक्षा के अन्दर भी छूआ-छूत आ गया है, अछूत और पंडित हो गए हैं। जिस तरह से हमारे हिन्दू समाज में वर्णव्यवस्था है, उसी तरह से हमारी शिक्षा में भी कुछ पंडितों वाली शिक्षा है और कुछ अछूतों वाली शिक्षा है। पंडितों वाली शिक्षा उन व्यक्तियो को मिलती है जो वैस्टेड इन्टरेस्ट हैं, पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं, जहां एक बच्चे पर 500 रुपए महाबार खर्च आता है। अछतों वाली शिक्षा उन को मिलती है, जिनके पास साधन नहीं हैं, सरकार ने उन के लिए स्कूल खोल दिए हैं।

जहां तक शिक्षा के प्रसार का सम्बन्ध है वैसे तो 1962 तक 6 साल से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को फ्री कम्पलसरी एजूकेशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी पांचवी पंच वर्षीय योजना में अर्थात् 1979 तक 6 साल से 11 साल तक के बच्चों के लिए रखा गया है। 1979 तक इतना हो जाये तो भी ठीक है, लेकिन मन्जिल कब तक पार होगी यह कहा नहीं जा सकता और शिक्षा एक महत्वपूर्ण चीज है, जिस के बगैर इंसान इंसान नहीं

[श्री मुल्की राज सैनी]

बन सकता । चाहिए तो यह था कि इस पर प्रारम्भ से ही ध्यान दिया जाता , भारत के नागरिकों को शिक्षा दे कर राजनीतिक तरीके से कांश्शस बनाया जाता, सामाजिक तरीके से समाजवाद की तरफ उन्हें आगे बढ़ाया जाता, लेकिन आज 1973 में भी हम 1979 का नाम सुन रहे हैं और वह भी केवल 6 साल से 11 साल के बच्चों के लिए । शिक्षा में आज जो ना-बराबरी है, अगर यह खत्म नहीं होती, हर एक घर में जब तक शिक्षा नहीं पहुचाई जाती, जब तक शिक्षा निःशुल्क नहीं होती, तब तक देश के अन्दर हमारा यह कहना कि हम समाजवाद ले आयेंगे रजत जयन्ती वर्ष के अन्दर यह कहां तक उचित है ?

सभापति महोदय: अब आप कल बोलिएगा । इस समय रेल्वे मिनिस्टर एक बयान देंगे । रेल्वे मिनिस्टर ।

It seems there are 8 or 9 members from the Government side and three or four on the other side. I requested the Minister of Parliamentary Affairs about extension of time. He says the time might be extended by an hour. Therefore, the Minister will speak after these members speak.

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT: Is the Minister replying today?

MR. CHAIRMAN: Tomorrow.

STATEMENT RE. SHORTAGE OF COAL IN UTTAR PRADESH

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI L. N. MISHRA): Sir, Shri S. M. Banerjee raised the question of shortage of coal in Uttar Pradesh this morning. While there has been progressive improvement in the loading of coal from Bengal and Bihar fields, since 1970-71, it is a fact and I am conscious of it that there is considerable unsatisfied demand of slack coal and soft coke. The railways are making every effort in conjunction with the new Coal Mines Authority to improve the level of loading within the existing resources. I had already indicated in my budget speech that there was need for additional wagons and that 15,000 wagons have been recently ordered over and above the 26,000 wagons already in order. With the materialisation of these orders for additional wagons, the level of loading is bound to incease.

After the taking over of the management of all coal mines by the Government, it has been possible for the Ministry of Steel and Mines and the railways to initiate schemes to reorganise coal loading to improve the wagon availability with a view to satisfying different demands for coal at the required levels. At the Ministerial level and at the operating levels on the zonal railways, there is adequate co-ordination in planning and execution of coal movements. The Ministry of Steel and Mines are also actively coordinating with the State Governments to bulk the coal requirements of small-scale industries, the brickburning industry and domestic consumers and move coal in large quantities in train loads from the coalfields to selected points in the respective States. Eventually, it is the intention to open dumps at convenient places from which further distribution would be done by road within a given radius.

I have no hesitation in saying that as a result of the joint efforts of the two Ministries, there will be an improvement in the availability of coal in different consuming centres in the country.

18.03 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April 6, 1973/Chaitra 16, 1895 (Saka).

MGIPND—Job 1164—L.S.—JC 184—18-7-73—1010